

# हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1973 (द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय—सूची

मंगलवार, 13 मार्च, 1973 (द्वितीय बैठक)

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)1
बहिर्गमन	(8)46
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)68

## हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 1973 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में मध्याह्न-पश्चात् 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

### राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सबसे पहले दौलता साहब बोलेंगे, लेकिन दौलता साहब, पांच-सात मिनट में कन्क्लूड करना है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मुझे तो आप कम से कम आधा घंटा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : चौदह मिनट तो आप उस दिन बोल चुके हैं।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : दस मिनट तो बहुत थोड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष :** टाईम इसी तरह फिक्स कर रहे हैं क्योंकि बोलने वालों की सूची में काफी लोग हैं ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दो प्वायंट उस रोज कवर कर पाया था । डिटेल्ज में मैं सिर्फ उन बातों पर बोलूंगा जो पालिसी मैटर्ज की होगी या कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी । उस रोज मैंने अर्ज किया था कि गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन कैपिटल के बारे में साफ करनी चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट या दूसरे कार्ड इंस्टीट्यूशंस का चण्डीगढ़ से बाहर ले जाना हमारे केस को कमजोर करता है ।

दूसरी जो बात मैंने अर्ज की, वह थी हमारे सी० एम० के करैक्टर असैसिनेशन के बारे में हमारे, हरियाणा के बाहर, पार्लियामेंट में प्राईम मिनिस्टर के इमेज को डैमेज करने के लिए आल इंडिया पार्टीज ने कीं इंदिरा गांधी का नाम लेकर, कही मारुति का नाम लेकर हमारे सी० एम० के बारे में बिल्कुल गलत बात करना शुरू किया हुआ है । स्पीकर साहब, इसके लिए हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा । इसके बारे में लीगल आर्गुमेंट देने की बजाए मैं एक बात कहूँ कि जहां तक हरियाणा की जनता का ताल्लुक है, हरियाणा में, कांग्रेस में कोई डिसेडेंट नहीं हैं और यह जो गैर सरकारी कांग्रेस है यह करैक्टर असैसिनेशन के बारे में बिल्कुल क्लीयर है । जहां तक हरियाणा के जिम्मेवार कांग्रेस 'ओ' के लीडर चौधरी रिजक राम का ताल्लुक है, उन्होंने यह नहीं कहा कि इन्क्वायरी होनी चाहिए । और तो ओर जहां तक राव

बीरेन्द्र सिंह का ताल्लुक है, पार्लियामैंट में इस बहस में उन्होंने अपने आपको ऐसोशिएट नहीं किया और जहां तक हमारे बहुत बड़े लीडर चौधरी हरद्वारी लाल का ताल्लुक है उन्होंने बुहु बड़ा ब्यान सी० एम० के खिलाफ दिया । वे कल उनके दोस्त थे, आज नहीं हैं । कल वे फिर दोस्त हो जाएंगे । मैं इसमें बिल्कुल दखल नहीं देता लेकिन उन्होंने भी अपनी तकरीर में एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा जोकि करैक्टर असैसीनेशन का हो । So let it be clear to the Speaker of the Parliament, through you, Sir, that this House, which is the voice of Haryana , resents very much that Haryana's image through the character assassination of Chief Minister be tarnished.

स्पीकर साहब, अब मैं तीसरी चीज पर आना चाहता हूं। सिर्फ एक मिनट लूंगा मैंने सारे ऐड्रेस को देखा है.....विधन.....  
...स्पीकर साहब, जो कत्ल के मुकदमें की तरह तैयार होकर आए उसको तो कम से कम पांच मिनट ज्यादा देने चाहिए।.....  
.....(हंसी).....इस ऐड्रेस में ऐग्रेरियन रिफार्म का जिक्र आया है इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट का एक केस कोट करता हूं, “जगमल वरसिज फाईनैशनल कमीशनर, पंजाब, ” जो कि ए० आई० आर० 1969 के पेज 392 पर दर्ज है, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक जो सब-टैनेट हैं वह सैक्शन 18 के मातहत जमीन नहीं खरीद सकता । चूंकि जमीन असली कल्टीवेटर को खरीदने का हक नहीं रहा, इसलिए अमेंडमेंट के जरिए रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट से सब-टैनेट को इस सैक्शन की रू से

जमीन खरीदने का हक दिया जाए । हर रोज इस जमीन के बारे में जजिज प्वायंट आउट करते हैं और मुझे देखकर कहते हैं कि किसी का हो, यह ठीक कराओ वरना कल्टीवेटर को जमीन नहीं मिलेगी ।

तीसरा पैराग्राफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हैं । मैं कहूंगा कि हमारी ट्रांसपोर्ट बैस्ट है और जो टैक्सेशन है वह जस्टीफाईड है । अगर हम बैस्ट ट्रांसपोर्ट चाहते हैं तो टैक्सेशन तो आएगा ही ।

इससे आगे जो पैराग्राफ है वह ड्रिंकींग वाटर के बारे में है । मेरे हल्के की जो पोजीशन है उस बारे में मैं बाद में आगाह कर दूंगा । वैसे मैं इस पैराग्राफ को स्पोर्ट करता हूं ।

उससे आगे का पैराग्राफ है वह मैडीकल फैसिलिटीज के बारे में हैं । मुझे पता नहीं कि यह मकहमा किसके पास है । लेकिन इसके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं और सुझाव से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि एक दिन मैं चंडीगढ़ में एक दुकान पर खड़ा था । वहां पर एक बड़ी ही फैशनेबल लेडी आई और उसने लिपिस्टिक तथा कुछ और चीजे खरीदी । मैं वहां देख रहा था । आप कह सकते हैं कि मैं लिपिस्टिक नहीं देख रहा था बल्कि कोई और चीज देख रहा था ।.....(हसी)...थोड़ी देर बाद वह चली गई । मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि दुकानदार ने उससे जो कीमत चार्ज की वह दवाओ की थी । तो मैं कहना चाहता हूं कि इसका कुछ इंतजाम किया जाए । मुझे पता लगा कि मैडिकल

फैसिलिटीज का लोग इसी तरह फायदा उठाते है । गवर्नमेंट सर्वेंटस चाहे आई0 ए0 अफसर है, इस फैसिलिटी से दो सौ रुपये तक की इस तरह की चीजे खरीदते है । इसलिए महकमा इस चीज को देखे और अगर फिक्स कर दिया जाये तो ठीक रहेगा ।

इसके बाद स्पीकर साहब, एजेकेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। इसमें टीचर्स का राइटली पुट किया गया है। लाएंड आर्डर के पैराग्राफ में वहीं प्लेस ठीक है। मैं एजुकेशन पालिसी के बारे में भी अर्ज करूंगा । हमारे यहाँ तीन भाषाएं पढते हैं। हिन्दी हमारी भाषा है उसको हम पढेंगे । अग्रेजी जो है, उसको हम हिस्ट्री के झटके के साथ पीछे नहीं छोड़ सकते। तीसरी भाषा आपने साउथ इंडिया की लागू की थी लेकिन वह तर्जुबा फेल हो चुका है। उर्दू भाषा जो कि हरियाणा की भाषा है, वह पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं, लखनऊ की लैंग्वेज नहीं और दक्षिण की भी लैंग्वेज नहीं है। यह यहीं पैदा हुई और यह आज भी हरियाणा की भाषा है और अगर मेरठ डिविजन यहां मिल जाएगा तो भी यह उर्दू भाषा यहां की रहेगी । मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू भाषा यहीं रहनी चाहिए । मैं जनसघ पर करारी चोट करना चाहता हूं, मैं माफी नहीं मांगुंगा चाहे यह कितना ही बोले । जनसघ का जहाँ तक ताल्लुक है इनका बड़ा खतरनाक इरादा है, बड़ा डेंजरस इरादा है(व्यवधान).....स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरीयस मैटर और गम्भीर है। मैं कहता हूं कि अगर किसी और देश के सूबे के एम0 एल0 ए0 ने ऐसा काम किया होता जैसा

कि जनसंघ के एम0एल0ए0 ने किया तो उसे अपनी कांस्टिट्यूएँसी में धुसना मुश्किल हो जाता । ये यहां पर नान-आफिशियल रैजोल्यूशन लाते हैं कि हरियाणा में दूसरी लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए, मैं पंजाबी का विरोधी नहीं हूँ। मैं जनसंघ वालों को कहता हूँ कि जब लैंग्वेज की बिना पर यह स्टेट आग्रेनाइज हुई तो either be loyal to Punjab or be loyal to Haryana. पंजाब के जनसंघ वाले और अरबेनाइज्ड हिन्दू सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, रिट लाते हैं और कहते हैं कि we are linguistic minority. Our language is Hindi. And in Haryana, those very people say”, “ We are champions of Punjabi; we are men of minority, give us minority rights, because our language is not Hindi.” Such an approach to language by the same caste by the same community, by the same political party, is something reprehensible.

स्पीकर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे पंजाबी से कोई बुग्ज नहीं है । मैंने 1962 की अपनी पार्लियामेंट की सीट हिन्दी पंजाबी ऐजीटेशन पर खोई थी । जिस वक्त थारा हर आदमी पंजाबी पढ़ना चाहता था उस वक्त जनसंघ वाले कहते थे कि ईड़ी-उड़ा नहीं पढ़ेंगे और जब हिन्दी के नाम पर यह स्टेट बनी है तो यह रैजोल्यूशन लाते हैं कि पंजाबी स्टेट की दूसरी लैंग्वेज हो । यह चीज जनसंघ वालों की ठीक नहीं है ।

ऐग्रीकल्चर का महकमा भी अच्छा है और वजीर उससे भी अच्छा। उसके बाद डेरी और फारेस्ट है और इसके बाद

कोओप्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि काओप्रेशन और कुरप्शन दोनो लैग्वेज के एक ही लफज हैं ।

स्पीकर साहब, अब मैं कौनाल्ज के पैरा 7 के पार्ट ए और बी पर आता हूँ । जो लोग मुझे कुछ कहना चाहे, वे पेट भर के कह ले । मैं तो पोलिटिकली अगर किसी आदमी का मशकूर हूँ तो सर छोटू राम जी के बाद चौधरी बंसी लाल जी का हूँ जिसने कुछ कहना हो कहे जाये । स्पीकर साहब, जो इन्वैस्टमैन्ट बिजली और नहरो पर हुई है उसका असर आज से पांच-छः साल के बाद जब हरियाणा देखेगा तो पता चलेगा कि महेन्द्रगढ के इलाके में दुसरे रेतीले इलाको में कितनी तरक्की हुई है । पहले इस इलाके में हम ब्याह में जाया करते थे तो धड़ा साथ लेकर जाया करते थे.....तो इस पालिसी का जो असर होगा वह कितना वण्डरफूल होगा । कहने दो जो कहते हैं “Haste is waste ” स्पीकर साहब कुछ आदमी उस चीज पर रुपया खर्च होना बरदाश्त नहीं कर सकते, जिसके कारण से रूरल ग्रोथ हो । यह तो हो सकता है कि डिवैलपमेंट कर ली हो इससे कोन सा मुल्क बचा है ? सात साल हो चुके है एक नावल छपा था जो कि रूस की उस लाईफ के बारे में बताता है, जिसके ऊपर डाक्टर जयाकु को इनाम मिला और नोबल प्राईज मिला । एक और नावल को प्राईज मिला उसका नाम इन्नर सर्कल । स्पीकर साहब रूस जैसे मुल्क का यही हाल है जहां कि कुरप्शन के लिए उस वक्त डैथ पैनल्टी प्रोवाइड थी अब का मुझे पता नहीं । वहां के लोग भी कुरप्शन के बिना



नही मानते। यहां यह कहे कि नहरों में कुछ टुट गया, लोग खा गये तो इसके लिए सारे प्रोजैक्ट और डिवैल्पमेंट के कामों को कन्डैम करे तो यह कोई हैल्दी ऐप्रोच नहीं है। स्पीकर साहब, खेतों में पैदा हुए एक लाल ने बहुत अच्छे काम किये है और हरियाणा के अन्दर, जब ऐग्रेरियन इकौनामी पर हिस्टरी लिखी जायेगी तो उस पर भी सर छोटू राम जी के बाद नैक्सट नम्बर किसी का होगा तो वह चौधरी बंसी लाल का ही होगा मुझे यह पता नहीं कि उनके दिल में सर छोटू राम जी के प्रति कोई प्यार है कि नहीं लेकिन जो रूरल इकौनामी को समझते है, वे हमेशा याद रखेंगे। His contribution will be remembered and remembered for generations.

**श्री अध्यक्ष :** दौलता साहब, आपका समय हो गया है ।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता :** अच्छा जी अगर मेरा समय हो गया तो मैं बैठ जाता हूं ।

**श्री के० एन० गुलाटी(फरीदाबाद) :** माननीय स्पीकर साहब, गवर्नर महोदय को ऐड्रैस हमारे सामने है, मैं उनकी तार्ईद करता हूं । इसमे कार्ई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ बात जो मैं अब कहना चाहता हूं कि अगर वे बाते इस ऐड्रैस मे आ जाती तो गवर्नर ऐड्रैस को चार चांद लग जाते। स्पीकर साहब, मैं जल्दी से अपने कुछ इम्पोर्टैन्ट प्वायंटस आपके सामने रखूंगा । गवर्नर ऐड्रैस एक तो चण्डीगढ,फाजिल्का और अबोर का कार्ई जिक नहीं है । पंजाब वाले उसका आनन्द ले रहे है । वे

चण्डीगढ के अन्दर बैठे है और साथ मे फाजिल्का व अबोहर की सारी आमदनी भी खा रहे है। हमे धाटा पड़ रहा है। तो स्पीकर साहब, मै आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से, जो कि बहुत मजबूत है, अर्ज करूगा कि यह सारा इलाका, जो कि पहले हरियाणा को दिया जा चुका है, लेने के लिए काई ऐसा प्रोग्राम बनाये, काई सत्याग्रह करे और सब से पहले उस सत्याग्रह के जत्थे में, मै अपना नाम ओफर करता हूं। इसे ऐसा होगा कि जो इलाका हमें पहले मिल चुका है, वह हमारे पोजैशन में जा जाएगा ।

इसके बाद मै एक और बात आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं कि अगर गवर्नर ऐड्रैस में यह बात भी आ जाती कि सारे हरियाणा में शराब बन्दी लागू कर दी जाएगी तो जैसे कि हरियाणा पहले से कई चीजो में आगे है इस में भी आगे आ जाता । गांधी जी ने भी शराबबन्दी के बारे में आवाज बुलन्द की थी। मै इस बात को तो मानता हूं कि सरकार की जो रैवेन्यू की वसूली है वह सब से ज्यादा शराब से है लेकिन अगर यह शराब की आमदनी बन्द हो जाये और उसके स्थान पर देसरे टैक्सो के जरिये और पुराने जो एरियर्ज पड़े हुए है, उनकी रिक्वरी की जाए तो इस से भ्ज़ी रवेन्यू की वसेली काफी हो सकती है। मै लीडर आफ की हाउस से यह अर्ज करूगा कि अगर शराब बन्दी लागू कर दी जाये तो इससे गुण्डागर्दी है, वह बंद हो जाएगी। अगर ऐसी-ऐसी बाते कही राज्यपाल महोदय के ऐड्रैस में आ जाती तो इसकी और ही

शान होती । ऐसे कामो को करने के बाद हरियाणा ही एक पहली स्टेट होगी जोकि नाम कमा लेगी। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर ऐड्रैस में अन-एम्पलायमेंट के बारे में अच्छी बातें कही गयी हैं। जो ऐजुकेटिड लोग हैं, जिनको नोकरियां नहीं मिलती, उनके लिए कम से कम अन-एम्पलायमेंट अलाउंस होना चाहिए । हर धर में नोकरी के लिए कोई न कोई काईटेरिया होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक धर में तो चार आदमियों को नोकरी मिली हुई है और दूसरे धर में एक भी नोकरी नहीं है । कम से कम सरकार को तो ऐसा कोई काईटेरिया जरूर निकालना चाहिए, जिससे कि हर धर में एक आदमी तो कम से कम जरूर नोकरी में हो। अगर गवर्नर ऐड्रैस में यह आ जाता कि सारे हिन्दुस्तान में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है इसलिए हरियाणा में भी इसे खत्म कर रहा है तो ठीक होता, और इससे गवर्नर ऐड्रैस में और मैं और शान आ जाती । आप अंदाजा लगाईये कि प्रोफेशनल टैक्स का सारा भार तो गरीब नौकरी पेशा लोगों पर ही पड़ता है और दूसरे बड़े-बड़े लोग 6 हजार की आमदनी दिखा करके अपने आपको बचा लेते हैं । बेचारे गरीब ऐम्पलाईज इससे बच सकते हैं अगर इस प्रोफेशनल टैक्स को खत्म कर दिया जाए । इन बातों के करने से गवर्नर ऐड्रैस और भी चमक सकता था ।

स्पीकर साहब, एक और बात मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि एक प्रोपर्टी पर दो टैक्स नहीं होने चाहियें, एक को खत्म कर देना चाहिए। जैसे एक गरीब एक कमरा

ले कर रहता है, उस पर तो टैक्स लग जाता है लेकिन एक आदमी जो कि 20 कमरो की कोठी लिए बैठा है, उसको प्रोपर्टी टैक्स माफ हो जाता है । अगर हाउस टैक्स को खत्म करके प्रोपर्टी टैक्स को रिवाइव कर दे तो ठीक रहेगा ।

स्पीकर साहब, इसके बाद मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट ऐम्पलाईज, जिनमे कुड म्युनिसिपल कमेटीज के ऐम्पलाईज भी शामिल है, जिन्हे सैमी गवर्नमेंट ऐम्पलाईज गिना जाता है, उनके लिए हर जगहो पर रैजिडैशियल क्वाटर्ज होना चाहिए या उन्हे क्वाटर्ज अलाउस मिलना चाहिए। न ही उनको हाउस टैक्स रेंट मिलता है न ही उन्हे गवर्नमेंट की तरफ से काई रहने की सहूलियते दी गई हैं । जो ऐम्पलाईज या अफसर बाहर बदल दिये जाते है, वे बड़े परेशान होते हैं। उनके बच्चो को रहने के लिए बड़ी मशिकल पड़ जाती है। गवर्नमेंट कोई ऐसी पालिसी बनाये जिस से ऐसा हो कि जब कोई अफसरान या कर्मचारी कहीं बाहर बदल दिये जाएं तो उन्हे वहां पर रहनक के लिए मकान भी मुहैया किये जाएं । इस के साथ-साथ मैं एक और बात कहना भूल गया कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह जो फरीदाबाद कम्प्लैक्स बनाया है, जिस मे बल्लभगढ, फरीदाबाद व टाऊनशिप शामिल है, यह तो अच्छी बात की है पर बल्लभगढ,फरीदाबाद और टाऊनशिप में कुछ फर्क रखा गया है। टाऊनशीप में तो हाउस रेंट की फ़ैसिलिटिज दी गई हैं, मगर फरीदाबाद व बल्लभगढ में ऐसा नहीं हैं। तो मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगहो

पर हाउस रेंट दिया जाना चाहिए । अगर ऐसी-ऐसी बातें गवर्नर ऐंड्रैस में कवर हो जाती तो हर तरफ से सरकार की तारीफ ही होती । स्पीकर साहब, मैंने अभी जिकर किया कि जब अफसरान की ट्रांसफर हो जाती है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है । इस लिए मैं तो यह कहूंगा कि जो डिफाल्टर्ज है, कम से कम उन्हें ही बदला जाये तो अच्छा रहेगा, दूसरे अफसरों को न बदला जाए । जो ईमानदार अफसर है उन पर एतबार किया जाए और जो पोलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले अफसर व कर्मचारी है उनको बदला जाए दूसरे अफसरों को तंग न किया जाए ।

इसके पश्चात स्पीकर साहब, मैं कुरप्शन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । रिश्वत तो हर जगह है, हन्दुस्तान में हरियाणा के अन्दर, सब जगह पर है, पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है । कुरप्शन को चैक करने के लिए, चाहे पब्लिक का आदमी हो, या कार्ई और हो एक पालिसी होनी चाहिये कि जो गल्ती करने वाला हो, उसे सजा जरूर दे तब तो यह काम बन्द हो सकता है वरना नहीं । अगर ऐसी-ऐसी बात गवर्नर ऐंड्रैस के अन्दर आ जाती तो ठीक बात थी । और इससे हरियाणा सरकार की भी प्रशंसा होती ।

मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फरीदाबाद के अन्दर एक मैडिकल कालिज है जो प्राईवेटली चल रहा है मैं मानता हूँ कि उस में 44 लाख रुपये का गबन हुआ और उससे 221 लड़के इफैक्टिड हुए । मैं मानता हूँ कि सरकार ऐसे प्राईवेट अदायरो की

गलतियां चैक नहीं कर सकती । मै तो यह कहूंगा कि इस हरियाणा की धरती पर अगर कोई भी आदमी चार सौ बीसी करता है, किसी की जिन्दगी से खेलता है तो जरूरी है कि उस पर कोई ऐक्शन हो ।

स्पीकर साहब इसके बाद जो बात मै कहना चाहता हूं कि अगर यह बात भी गवर्नर ऐड्रेस में आ जाती तो कितना अच्छा होता । मै यह कहना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ने वहां पर कार्पोरेशन बना दी है। अगर ये उस को हरियाणा की कैपिटल डिव्लेयर कर दे तो इनकी बड़ी कृपा होगी। अगर कैपिटल न बना सके तो कम से कम जैसे सोनीपत, भिवानी ओर कुरुक्षेत्र जिले बनाए है उसे जिला ही बना दे । फरीदाबाद हरियाणा का एक बहुत बड़ा हैं । वह लेबर ऐरिया है, इंडस्ट्रियल ऐरिया है और दिल्ली के भी नजदीक है। दिल्ली से रोजाना बहुत से लोग वहां जाते हैं। अगर उसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाये तो वह चीफ मिनिस्टर साहब की भी शान होगी और हरियाणा की भी शान होगी और उसको देखकर दिल्ली तथा और जगहों से आने वाले लोग भी खुश होंगे कि फरीदाबाद कितना अच्छा शहर है। मै केवल फरीदाबाद की ही बात नहीं करूंगा मैं यह भी चाहूंगा कि यमुना नगर को भी उसका पूरा पूरा हक मिलना चाहिये, इस को भी जिला बना दिजिये ।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जहां पानी और बिजली या हर बात में पहल कर रहे है वहां इनको ऐजुकेशन की तरफ भी

ध्यान देना चाहिये । मै चाहता हूं कि हायर सैकेण्डरी तक एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिये । चीफ मिनिस्टर साहब हरियाणा को अगर इस बात में आगे ले जाएं तो यह बड़े फखर की बात होगी ।

स्पीकर साहब, थोड़े से प्वायंट्स मै आपके सामने और रखना चाहता हूं। एक डैमोक्रेटिक सैट-अप में म्यूनिसिपिल कमेटियो या कार्पोरेशंज के इलैकशनज न हो यह बात अच्छी नहीं लगती । मै सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कमेटियों का इलैकशन करवाए और फरीदाबाद में जो कम्पलैक्स है उसका भी इलैकशन करवाए ।

इसके बाद मै फूड-ग्रेन्ज पर आना चाहता हूं। फूड-ग्रेन्ज पर कन्ट्रोल किया जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। आज मैने देखा कि सारे हिन्दुस्तान में व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि स्टेट्स फूड-ग्रेन्ज को अपने हाथ में न ले । इस संबंध में गवर्नर महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 4 पर जिकर किया गया है कि सरकार यह व्यापार अपने हाथ में ले रही है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस चीज को गवर्नर में से काट दिया जाये ।

इसके बाद मै ऐम्पलाईज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये तीसरे पे-कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है। उस का रिजल्ट आते ही अगर हरियाणा सरकार भी अपने ऐम्पलाइज के लिए एक जनवरी

से उसे लागू कर दे तो मुझे भी फखर होगा और सभी ऐम्पलाइज को भी फखर होगा ।

एक प्वायट जो टीचर्ज पर आया था मैं उस पर ज्यादा टीका-टिप्पणी न करते हुए थोड़ा सा कहूंगा । मैंने पहले भी कहा था कि हम अपोजीशन वाल या दूसरे, सियासी अखाड़ा न बनाएं । हमें चाहिए कि हम टीचर्ज का प्यार से कहे कि एकांत में बैठ कर सोचो, ठण्डे दिल से बैठ कर सोचो कि समझोता कैसे हो सकता हैं- आज एजुकेशन का वास्ता देकर हमें एक मिनट के सोचना चाहिये, सारे हाउस को एक अवाज हो कर टीचरो को कह देना चाहिए कि आपने बहुत कर दिया है अब ऐजीटेशन वापिस ले लो हाउस के पांच मैम्बरो का ऐ पैनल बन जाना चाहिए, जो उनकी जायज मांगो पर सोच विचार करे । यह पैनल टीचर्ज को कहे कि तू अन-कंडीशनली स्ट्राईक वापिस ले लो हम तुम्हारी जायज मांगो का फैसला एक महीने के अन्दर करवा देंगे । फरीदाबाद मे इस वक्त जो कम्पलैक्स चल रहा है उसको बहुत ज्यादा पैसा दिया जा रहा है वहां पानी की कमी है और सैनीटेशन की कमी है । इन चीजो को देखकर बाहर से आने वाले लोग भला क्या महसूस करते होंगे ? सैनीटेशन की कमी के कारण फरीदाबाद में आज कल के समय में भी मच्छर इतने काटते है कि बगैर मच्छरदानी के कोई अगर पड़ जाए तो मां नानी याद आ जाती है ।...(हंसी)..... यह हंसी की बात नहीं है वहां जाकर देखिये । यह एक सच्चा जज्बात है : दूर दूर से लोग वहां आते हैं लेकिन पानी की कमी



को देख कर वे बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह कभी कभी गत बातें बताता रहता है। इस सम्बन्ध में मैं पानी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। फरीदाबाद के अन्दर 4 सैक्टर में गर्वनमेंट इम्प्लाइज के क्वार्टर है। वहाँ पानी का प्रेशर इतना है कि पानी फालतू है। इसी तरह 7 सैक्टर में भी पानी फालतू है। इन दोनों सैक्टरों में तो पानी फालतू है लेकिन दूसरे सैक्टरों में पानी की कमी है। सरकारी कर्मचारी न तो हरियाणा सरकार का ध्यान दिलाते हैं और न खुद काम करते हैं। पता नहीं क्या बात है उनका इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि दूसरे सैक्टरों की तरफ भी ध्यान दिया जाये। अभी मुझे 183 नं० सवाल के जवाब में बताया गया है कि हमारे किसी स्कूल में 98 हजार का फंड पड़ा है तो किसी में 50 हजार का पड़ा है लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। सरकारी अफसर कभी-कभी मिनिस्टर साहिबान को कई बातें नहीं बताते। इस चीज को ही लीजिए कि जब पैसा पड़ा है तो उसे खर्च क्यों नहीं किया जाता? सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे पैसे को खर्च करके स्कूलों की कमियों को दूर किया जाये। एक सवाल के जवाब में पता चला कि स्कूलों में हजारों स्टूडेंट्स हैं। हजारों स्टूडेंट्स से फीस ली जाती है लेकिन वहाँ पर जो स्वीपर रखे जाते हैं उनको 20 रुपये तनखवाह मिलती है जो कि बहुत कम है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि मेरी बातों पर अमल करे। मेरी बातों पर न खर्च आयेगा, न टाइम लगेगा अगर सरकार सिर्फ इनकी तरफ ध्यान दे तो बातें हल हो जायेंगी। (घंटी).....

..... मैं अभी दो चार बातें कह कर समाप्त करता हूँ। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद टाउनशिप में विडो होम्ज अलाट नहीं किये, मेरे पास केन्द्रीय सरकार का 26 जनवरी का लैटर है जिसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद टाउन शिप विडो होम्ज की अलाटमेंट करेगी। मैं मिनिस्टर साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वे सरप्राइज दौरा करे और डिफाल्टरो को चेक करे तो इसमें सुधार हो सकेगा। एक बात और बताना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कुछ ऐम्पलाइज हैं जिनकी जिनकी सर्विस 10-12 साल की हो गई है लेकिन वे अभी तक टैम्पेरी हैं। मेरा निवेदन है कि उनको परमानेंट किया जाये। इसी तरह से 20-22 साल की सर्विस वाला सुपर-वाइजरी स्टाफ है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। दूसरी चीज मैं हरियाणा सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि दफतरो में स्टाफ की कमी है। सरकार को इस कमी को दूर करना चाहिए। आज सरकारी बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब है। फरीदाबाद के अन्दर तमाम सरकारी बिल्डिंगों बगैर रिपेयर के पड़ी हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 उनको रिपेयर नहीं कर रहे हैं इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आचिारी प्वायंट जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि सरकार जो भी जमीन अलाट करे वह किशतों पर करे ताकि असली मायनों में गरीबी दूर हो सके। इन अलफाज के साथ मैं गवर्नर ऐड्रैस की ताइद करते हुए चाहूंगा कि मैंने जो अमेंडमेंट्स पेश की है, वे इस में आ जाएं।

**श्री निहाल सिंह** (महेन्द्रगढ) : स्पीकर साहब, गर्वनर साहब हमारे सदन मे पधारे और इस सदन को सम्बोधित किया, इसके लिए चौधरी सरूप सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया । मै इस प्रस्ताव की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले मै और बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाऊं मै एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि गर्वनर साहब अपना वैधानिक दायित्व निभाने के लिए इस सदन में पधारे थे और जब वे इस काम के लिए सदन में पधारे तो हम सब का फर्ज है कि वे जब सदन को सम्बोधित करने के लिए आये तो हम उनको पूरा मान दे, रिस्पैक्ट करे और ऐसा करके अपने विधान का भी मान करे । लेकिन कुछ सदस्यों ने जब गर्वनर साहब, हाउस मे आये तो वाक आउट/बहिष्कार करना उचित समझा । मै समझता हूं कि इस तरह न सिर्फ हमारे हाउस की बल्कि विधान का भी अपमान हुआ है.....

**चौधरी रिजक राम** : किसने किया था ?

**श्री निहाल सिंह** : वाक आउट नहीं किया था बहिष्कार किया था।

**श्री निहाल सिंह** : ठीक है जी, मैने भी बहिष्कार ही कहा है। तो मै अर्ज करता हूं कि जिन सदस्यों ने बहिष्कार किया और जो उस वक्त यहां हाजिर नहीं रहना चाहते थे उनको कम से कम इस ऐड्रेस पर बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये । ऐसी आप

परम्परा कायम करे । स्पीकर साहब, अगर हो सकता तो जो स्पीकरज कांफ्रेंस होती है उस में इस प्वाइंट पर फ़ैसला करवाये जो इस तरह ऐड्रेस का बहिष्कार करे उनको इस बहस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब मैं स्पीकर साहब यह अर्ज करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में मैबर साहिबान का ध्यान इस तरफ़ दिलाया है कि हमारी मौजूदा सरकार से इस बात के लिये वचन-बद्ध है कि अपने राज्य में से गरीबी दूर करनी हैं और यहां पर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है और ऐसा करने के लिए हरियाणा सरकार ने जो-जो नीति अपनाई है और जो-जो काम किये हैं उनके बारे में पूरे विस्तार से के साथ गवर्नर साहब ने सदन को सम्बोधित किया है। गरीबी दूर करने के लिए और वेलफ़ेयर स्टेट कायम करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हम जनता की आर्थिक हालत को ठीक करे और हरियाणा राज्य को आत्म निर्भरता की तरफ़ बढ़ाये। यह काम तभी हो सकता है जब हम तीन मोटी-मोटी बातों को ही यहां करें और जैसा कि गवर्नर साहब ने भी कहा है कि एक तो हमारी जो प्रजातन्त्र प्रणाली है वह पूरी तरह से सृष्ट हो, मजबूत हो और अच्छे ढंग से काम करे । दूसरे जितनी हमारी आर्थिक विषमताएँ जिनके बारे में गवर्नर साहब ने भी फ़रमाया है कि हरियाणा सरकार अच्छी रफ़्तार से इस तरफ़ बढ़ रही है ये विषमताएँ कम से कम हो और दूर हो। तीसरे जो भी पिछड़े इलाके हैं जिन में अभी तक तरक्की नहीं हुई उनको भी दूसरे इलाकों के मुकाबले में लाया जाये और सारे प्रदेश का संतुलित विकास हो । पहली बात जो मैंने अर्ज की

और जिसकी तरफ गवर्नर साहब ने भी अपने ऐड्रेस में इशारा किया है वह यह है कि हमारे यहां पोलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिये ताकि जितने भी विकास कार्य है वे अच्छे ढंग से बराबर चलते रहे । इस बारे में मैं अर्ज करूंगा कि हमारी मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने और सरकार ने यह स्टेबिलिटी लाकर हरियाणा की बहुत सेवा की क्योंकि इसने मजबूत, स्थाई और सुदृढ सरकार प्रदेश में बनाई है ताकि जो उम्मीदे लोग सरकार से और अपने नुमाईदो से रखते है उनको अच्छे ढंग से पूरा कर सके । जब हरियाणा बना था उस वक्त क्या हालत थी और आज क्या हैं ? इसमे जाने की जरूरत मैं नहीं समझता क्योंकि इस बारे में सब जानते है कि कितनी तरक्की यहां पर हुई है और उस वक्त कितनी अस्थिरता थी और आज कितनी स्टेबिलिटी इस प्रदेश मे आई है । हमारे ट्रेजरी बैचिंज में तो मजबूती हुई लेकिन दूसरी तरफ एक बात देखने मे आई कि जो अपोजीशन पार्टीज है वे कमजोर पड़ गई हैं । स्पीकर साहब, अपोजीशन पार्टीज का भी डैमोकसी में उतना ही कन्स्ट्रक्टिव रोल है उतना ही विकास के कामो में हिस्सा लेने का कर्तव्य है जितना कि ट्रेजरी बैचिंज का है लेकिन देखने में यह बात आई है कि अपोजीशन में भी डिफैक्शन होती है और अपोजीशन के अन्दर भी पार्टी को बदला जाता है । यह डैमोकसी के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं हैं । मैं अर्ज करता हूं कि इसी तरह अगर अपोजीशन पार्टीज इस बात को समझों कि जहां वे आये हैं वहां ही वे रहें तो इससे हरियाणा प्रदेश की अच्छी प्रगति होगी । चौधरी हरद्वारी लाल जी जो हमारे सदन में विरोधी दल के नेता

भी रहे हैं, उन्होंने, पहले जब वे चुन कर आये थे तो एक दफा पार्टी बदली थी और यह समझ कर बदली क्योंकि वे उस वक्त मिनिस्टर थे। उन्होंने यह समझ कर दोबारा चुनाव लड़ा कि वे मिनिस्टरी के जोर पर जीत जायेंगे और यह बात ध्यान में रख कर मिसाल कायम की। लेकिन मैं उन से पूछता हूँ कि अब कौन सी ऐसी बात हो गई कि उन्होंने फिर पार्टी को बदला ? एक पार्टी की तरफ से चुन कर दूसरी पार्टी में गये, मगर चुप करके बैठ गये। मैं समझता हूँ कि अपनी पिछली परम्परा को कायम रखने के लिये और पहले जो रवायात कायम की थीं उसे पूरा करने के लिए अच्छा होगा कि ते जनता से फिर पूछें और उससे इस बारे में मत लें। अगर ते समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब वहां जायेंगे, उनके चुनाव में दखल देंगे तो मैं उनको विश्वास दिला समता हूँ कि हम चीफ मिनिस्टर साहब की वहां नहीं जानें देंगे अगर वह इलैक्शन लड़ेंगे (तालियां)

**मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) :** मैं रोहतक जिला में ही नहीं जाऊंगा।

**श्री निहाल सिंह :** इन बातों को कहने का कोई फायदा नहीं कि अगर वे यह कहें कि मैं लड़ने के लिये तैयार हूँ अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी सीट छोड़ कर लड़े। मैं अर्ज करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब तो अपनी जगह पर कायम है और ये जिस पार्टी से टिकट लेकर आये थे, जिन सिद्धांतों को लेकर

चुनाव लड़ा था जो वायदे दे कर चुनाव लड़ा था दन पर कायम है  
.....

**चौधरी बंसी लाल :** मैं अपने इलैक्शज़न में भी वहां नहीं गया था ।

**श्री निहाल सिंह :** एक और बात चौधरी हरद्वारी लाल ने कही और हादस में उन्होंने कहा कि वह जो उनके पीछे सिलसिला लगा हुआ था वह कहां गया? वे मैम्बर कहां गये, किधर गये ? यह बात उन्होंने हाउस से पूछने की कोशिश की । उनको खुद अपने आपसे और आपने दिल से यह बात पूछनी चाहिये कि वे कहां गये ? मैं समझता हूं कि उनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे कोई एक देवी जा रहती थी । उसका अच्छा मकान और कोठी थी और तीन-चार बच्चे भी थे । कई दफा जब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि मम्मी जी हमारा डैडी कौन है ? तो वह कोई जवाब नहीं दे सकी और जवाब देने में असमर्थ थी । बच्चो ने कहा कि अगर यह नहीं बताती तो यही बता दो कि हमारे घर में जो इतनी आमदनी आती है यह सब कहां से हो रही है ? वह इस बात का जवाब भी नहीं दे सकी । कुछ दिन बाद जब बच्चे सियाने हुये तो वे समझने लग गये कि यह जो आमदनी हो रही है यह क्वेश्चनेबल मीन्ज से हो रही है और वे उसे छोड़ गये । इसी तरह से हमारे जो साथी इनके साथ लगे हुये थे जब उनको महसूस हुआ कि हरद्वारी लाल जी क्वेश्चनेबल पोलिटिकल लाअफ लीड कर रहे है तो जिस तरह वे बच्चे अपनी मम्मी को छोड़ कर

चले गये थे उसी तरह ये मैम्बर भी इनको छोड़ कर चले गये (हंसी) स्पीकर साहब, अब मैं और बातो की तरफ सदन को ध्यान दिलाना चाहता हूँ । गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में बताया है कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने तरक्की के काम किये हैं । हरियाणा सरकार के बहुत सारे महकमें हैं लेकिन मैं दो एक बारे में अर्ज करूंगा । सब से पहली बात यह.....

**चौधरी रिजक राम :** सब से ज्यादा जरूरी महकमे पर तो आप बोल लिये ..... (हंसी).....

**श्री निहाल सिंह :** तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस में खेती बाड़ी ने जितनी तरक्की की है वह बहुत ही सराहनीय है । हमारे प्रदेश का क्षेत्र सारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.5 है लेकिन इसके मुकाबले में जो हम पैदा करते हैं वह सारे देश की पैदावार का 4.6 है । यह बहु ही सराहनीय बात है (तालियां)..... स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमारे राज्य में अनाज की बड़ी की थी क्योंकि पैदावार बहुत कम होती थी । देश के बहुत कम इलाकों में अनाज पैदा होता था । लेकिन अब आप बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने उन इलाकों की कमी को ही पूरा नहीं किया बल्कि आज देश के भण्डार में पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं । जब हरियाणा बना था तो कुल 26 लाख टन अनाज पैदा होता था और उस के मुकाबले में आज हमें उम्मीद है कि 50 लाख टन अनाज इस साल पैदा होगा जबकि



इस साल बिजली की बहुत कमी रही है , प्रदेश के कई भागों में सूखा पड़ गया और वहां के किसानों को पूरी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकी । इन बातों के बावजूद भी हमने हरियाणा अनाज के सिलसिले में काफी तरक्की की है । हमारा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट और इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस बात के लिए रिसर्चिंग है कि किस तरह से हमने हरियाणा में इतना ज्यादा अनाज पैदा किया है । अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए दूसरा अहम काम जो हम करने जा रहे है वह स्टेट ट्रेडिंग है । स्टेट ट्रेडिंग के बारे में बुरी तरह से चर्चा की गई है । कुछ लोगों ने अंदेशा जाहिर किया है कि स्टेट ट्रेडिंग से बहुत से लोग बेकार हो जाएंगे, लोगों को रोजी नहीं मिलेगी और अनाज अच्छी तरह से लोगों तक नहीं पहुंचेगा । लेकिन यह बात ध्यान में रहे कि स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी हमारी नैशनल पालिसी है । सारी स्टेट में जो अनाज उपलब्ध है , वह सस्ते दामों पर, ठीक दामों पर लोगों को रैगुलरली मिलता रहेगा और किसानों को अपने अनाज की पूरी कीमत मिलती रहेगी । यहां यह कहा गया कि किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती नहीं मिलती । अगर गवर्नमेंट मार्केट में न हो , जैसा कि आपने पिछले साल रबी की फसल में देखा कि अगर गवर्नमेंट मार्केट में न जाती तो अनाज की कीमत 50 रूपये क्विंटल तक जाती । 50 रूपये प्रति क्विंटल तक जाने की सम्भावना हो गई थी जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता । लेकिन सरकार ने रेट मुकर्रर किया ताकि किसानों को ठीक कीमत मिल सके । अब स्टेट ट्रेडिंग का मसला हमारे सामने है । हमें

सरकार को सहयोग देना चाहिए, सरकार को मदद देनी चाहिए, ताकि स्टेट ट्रेडिंग करके गरीब वर्ग को अनाज सप्लाई की गारंटी हो सके और किसान को अनाज की पूरी कीमत मिल सकें ।

इसके इलावा दूसरा महकमा जिस के बारे में जनसंघ के एक माननीय सदस्य श्री राम लाल जी ने जिक्र किया था, वह है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट । इन्होंने इस महकमे के बारे में कहा कि ठीक काम नहीं चल रहा, अच्छा काम नहीं हो रहा और महकमे में एफिशिएंसी नहीं है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका तजुर्बा कुछ और है और उनकी पार्टी के सैक्रैटरी श्री यज्ञदत्त शर्मा का तजुर्बा कुछ और है । एक रोज मैंने और श्री यज्ञदत्त शर्मा ने हरियाणा रोडवेज बस में इकट्ठे सफर किया था तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है । उन्होंने इस बात की सराहना की कि यह महकमा ठीक तरह से काम कर रहा है । राम लाल जी को इस बात का ज्यादा पता होगा क्योंकि उन्होंने खुद ट्रांसपोर्ट का काम किया है । उनका तजुर्बा और जनसंघ के सैक्रैटरी का तजुर्बा अलहदा – अलहदा है । जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त रोडवेज पर बहुत कम रूपया खर्च होता था और उसके मुकाबले में आज हमने डेढ़ करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है । उस वक्त जहां 1 करोड़ 80 लाख रूपया रोडवेज ने दिया था वहां आज सरकार को 9 करोड़ के करीब पैसा दिया है । यह रूपया प्रॉफिट की शकल में, इन्ट्रैक्ट की शकल में और टैक्स की शकल में दिया है । इन बातों से

जाहिर होता है कि हमारी रोडवेज ने किस तरह तरक्की की है । यही नहीं, ये मानें या न मानें, प्लानिंग कमीशन का कहना है कि हरियाणा रोडवेज सारे हिन्दुस्तान में फाइनेंशियली साउंड है । हरियाणा रोडवेज ने जो रिटर्न दी है वह सारे हिन्दुस्तान में सबसे आगे है । पंजाब स्टेट हमारे मुकाबले की है । प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि पंजाब स्टेट के मुकाबले कें हमारी वर्किंग और फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा साउंड है । स्पीकर साहब, अपोजीशन के मैम्बर हरियाणा सरकार की तरक्की की रफ्तार को देख कर यह समझते हैं कि हरियाणा की तरक्की नहीं हुई, हरियाणा में ठीक तरह से काम नहीं हो रहा । यह जो बात यह कहते हैं इसको कहते वक्त यह भूल जाते हैं कि जब यह भाई आन्ध्रप्रदेश, यू.पी. वगैरा दूसरी स्टेटों में जाते हैं तो वहां जाकर हरियाणा की मिसाल देते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने कितनी तरक्की की है, कितना काम हुआ । उनको जाकर कहते हैं कि तूम भी छोटी – छोटी रियासतें बनाओ, राज्य बनाओ, आन्ध्रप्रदेश के टुकड़े करो, यू.पी. के टुकड़ें करो । यह दलील ठीक ही देते हैं कि हरियाणा की तरक्की सारे देश में सबसे ज्यादा हुई है लेकिन यहां ये ऐसी बात नहीं कहना चाहते । ये समझते हैं कि अगर हम यहां पर ऐसी बात कहेंगे, कोई तरक्की की बात कहेंगे तो हमारे पास कौन सी बात रह जायेगी जिसको लेकर हम जनता के पास जायेंगे । जैसा कि दौलता साहब ने कहा कि सारे देश में अपोजीशन पार्टी एक जबान बनी हुई है और उसने एक ही स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि किस तरह से क्रिटिसाईज किया जाए ।

लेकिन प्राईम मिनिस्टर के कामों की वजह से और हरियाणा में चौधरी बंसी लाल के कामों की वजह से देश ने जो तरक्की की है उस तरक्की को सामने रखते हुए ये नहीं कह सकते की हरियाणा प्रदेश में काम नहीं हुआ या सारे देश में अच्छी योजनाएं नहीं बन रहीं । उन्होने एक ही तरीका निकाला हुआ है कि इनका जो चरित्र है उसकी आलोचना की जाए जिसको करैक्टर असैसिनेशन कहा जाता है । इन्होने चरित्रहनन यानी करैक्टर असैसिनेशन के प्रोग्राम को अपनाया हुआ है । जनसंघ की डिस्ट्रिक्ट कान्फ्रेंस में जो जो बातें हुईं वह अखबार में आई है। कई बातें आई कि तरक्की होनी चाहिए । उन्होने यह भी कहा कि हरियाणा के मुख्य मंत्री के खिलाफ इन्कवायरी करवाने के लिए आन्दोलन खड़ा करेंगे । डिस्ट्रिक्ट लैवल कान्फ्रेंस के पहले फरीदाबाद में जनसंघ का सैशन हुआ था और वह सैशन स्टेट लैवल का था । दस सैशन में इन्होने यह प्रस्ताव पास किया कि मुख्य मंत्री के खिलाफ इन्कवायरी करवाने के लिए आन्दोलन खड़ा करेंगे । उसके बाद कानपुर में आल इंडिया सैशन में भी इनको कोई और बात नजर नहीं आई और चीफ मिनिस्टर हरियाणा के खिलाफ रैजोल्यूशन पास करते रहे । एक पोलिटिकल पार्टी जो आल इंडिया लैवल पर काम करती है और वह इस किस्म की बातें करे, एक व्यक्ति के बारे में इस किस्म के प्रस्ताव पास करे तो यह उनको कहां तक शोभा देता है। कांग्रेस पार्टी की एक हिस्टरी है, एक बैकग्राउंड है। कांग्रेसन जनसंघ की तरह किसी व्यक्ति के खिलाफ रैजोल्यूशन पास नहीं किया। कांग्रेस ने तो कहा कि हमने आर्थिक,

राजनैतिक ओर सामाजिक कार्य करने हैं, अच्छे काम करने हैं लेकिन व्यक्तिगत बातों में बिल्कुल नहीं जाना। जो पार्टी आल इंडिया लेवल के सेशन में इस किस्म की बातें रके, उसकी दशा वास्तव में शोचनीय है। एक बात दौलता साहब ने कही कि जनसंघ के प्रधान चौधरी मुख्तियार सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि चौधरी बंसी लाल जबान का मीठा नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चौधरी मुख्तियार सिंह और चौधरी प्रताप सिंह अमेरिका और रशिया से जो स्वीट डिशिंज खा कर आये हैं वे हमारे मुख्य मंत्री ने नहीं खाई ..... (हंसी) .....

**चौधरी राम लाल वधवा:** आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, क्या यह ऐड्रेस में सुझाव दिया हुआ है जो ये बोल रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष:** यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** मुझे तो ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ..... (विघ्न) .....

**श्री निहाल सिंह:** इनको सोचना चाहिये कि हमारे मुख्य मंत्री बातों से पेट भरने में यकीन नहीं रखते। जिन इलाकों में कुछ पैदा नहीं होता था, जहां रेगिस्तान था वहां आज गन्ना पैदा होता है। हमें तो यह देखना है कि हजारों गांव जो कड़वा पानी पीते थे, उनका मुंह उन्होंने मीठा किया है या नहीं किया है उनको पानी दिया या नहीं दिया। हमें तो यह देखना है कि लोगों का

मुह बातों से मीठा होता है, काम से मीठा होता है या कैसे होता है। ये सारी बातें मैंने इसलिए कही हैं, स्पीकर साहब, ताकि अपोजीशन पार्टीज के मैम्बर्ज ने जो बातें की हैं उनका जवाब दिया जा सके।

स्पीकर साहब, अपोजीशन पार्टीज वाले एक बात की बड़ी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा विषय आज कल उन्होंने इस बात को बनाया हुआ है और वह बात है हरियाणा में अध्यापकों की हड़ताल। हरियाणा में अध्यापकों की हड़ताल के बारे में आज ही शिक्षा मंत्री जी ने एक ब्यान दिया है। उसमें सारी बातें विस्तार से उन्होंने बताई हैं। स्पीकर साहब, जनसंघ के मैम्बरों ने यह कहा कि यह बड़ी पापुलर डिमांड है जनता की, यह बड़ी पापुलर डिमांड है लोगों की लेकिन स्पीकर साहब, लोगों की, जनता की अगर यह डिमांड होती तो उनको दिल्ली में जाकर ऐजिटेशन करने की जरूरत नहीं थी। आज भले ही वे कहें कि वे दिल्ली इसलिए भागे हैं कि यहां पुलिस का डंडा ज्यादा सख्त है लेकिन मैं यह कहता हूँ कि यह बिल्कुल गलत बात है। आज पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ है। आज अगर वे हरियाणा के किसी गांव में कहीं किसी जगह जाकर जनता को साथ लगाना चाहें तो जनता बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, स्पीकर साहब, पब्लिक ओपिनियन के डर से आज वे हरियाणा में नहीं रहना चाहते।  
(विघ्न)

**चौधरी दल सिंह:** स्पीकर साहब, यह बात ठीक नहीं है।

.....

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी साहब, आप इन्हें बोलने दीजिए, आप तो बहुत कुछ कह चुके हैं। (विघ्न) किसी की तरफ से कोई इंट्रूप्शन नहीं होनी चाहिए। राव साहब, आप बोलिए।

**श्री निहाल सिंह:** स्पीकर साहब, आज जो अध्यापक दिल्ली से गांव में जाता है वह दो दिन से ज्यादा वहां ठहर नहीं पाता। लोग उसे कहते हैं कि आपने यह क्या किया ? आपने तो बच्चों का नुकसान किया, आप इम्तहान के वक्त में चले गये, इम्तहान में रूकावट पड़ी है और शिक्षा में नुकसान हुआ है। तो वे दो दिन से ज्यादा गांव में नहीं ठहरते और अपना मोरल बूस्ट करने के लिये लौटकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। (विघ्न)

**श्री अध्यक्ष:** राव साहब को बोलने दीजिये। बीच में इस तरह से विघ्न करना अच्छा नहीं होता। जिस किसी को कुछ कहाना है वह कृपया आने समय में कहे।

**श्री निहार सिंह:** स्पीकर साहब, ये जो करैक्टर असैसिनेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट सर्वेट्स के द्वारा ऐजिटेशन चलाना चाहते हैं, यह एक ऐसी बात है कि जब इनको गवर्नमेंट की बुराई करने की कोई बात सूझती नहीं तो ये करैक्टर असैसिनेशन की बात करते हैं और गवर्नमेंट सर्वेट्स के द्वारा इस तरह के ऐजिटेशन फैलाते हैं। जो स्टेट ने एक अच्छा नाम पैदा

किया था सारे देश में कि हरियाणा में बड़ी तरक्की हुई है, इस किस्म के ऐजिटेशन फैलाकर उसे नलिफाई करने के लिए, उस काम को बिलीटल करने के लिए इन्होंने इस किस्म के तरीके इख्तियार किये हैं जिससे सटेट का नाम दिल्ली में सैन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने अच्छा न रहे। लेकिन इनको पता नहीं कि इससे कितना नुकसान हुआ है ? यह बड़ी गलत एप्रोच है। स्पीकर साहब, ये हमेशा इस तरह की बातों में उलझे रहते हैं, ये या इनका डेलीगेशन कभी प्लानिंग कमीशन के पास, फाईनैन्स कमीशन के पास या गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास इस बात के लिए नहीं जाता कि हमारी क्या दिक्कतें हैं, कितनी हमारे सामने मुसीबतें हैं, कहां कहा हमने पानी देना है, कितनी योजनायें हैं जिनको पैसा न होने की वजह से नुकसान पहुंचा है। उस काम के लिए तो ये समझते हैं कि यह तो एनटायरली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ये उसे अपना फर्ज नहीं समझते। मैं इनसे स्पकीर साहब, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से भले ही किसी तरह से लड़ें लेकिन जहां तक हरियाणा के इंट्रैस्ट का सवाल है, हरियाणा का प्लानिंग कमीशन से ज्यादा पैसा लेने का सवाल है उसमें हमें आपके सहयोग की भी जरूरत है, आपकी मदद की भी जरूरत है।

स्पीकर साहब, कई मੈबरों ने चंडीगढ़ इशू के बारे में भी कहा। इसके बारे में तो मैं भी कहूंगा कि यह सबसे अच्छा टाईम है जबकि इसका फैसला होना चाहिए। (विरोधी पक्ष की ओर



से तालियां) आज दोनों जगह, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो अवार्ड दिया है चंडीगढ़ के बारे में अगर आज उसको .... सकते तो हमारे लिये आगे चलकर और भी दिक्कत की बात हो सकती है, मुसीबत हो सकती है। आज पंजाब का इंट्रैस्ट हो सकता है कि वह किसी तरह इस बात को टाले, इस बात को टालने की कोशिश करे और आगे ले जाये क्योंकि उनका संत तो खत्म हो गया और वे समझते होंगे कि और संत पैदा होगा जिसके जरिये नई बात शुरू करें। तो स्पीकर साहब, इसके मुताल्लिक, आपके द्वारा मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, अपनी गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि हमें इस काम को करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए और यह जो मसला लटका हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी डिवैल्पमेंट रूकी हुई है खास कर उन इलाकों की जो इलाके हरियाणा में शामिल होने हैं उन सबके इंट्रैस्ट के लिए यह जरूरी है कि इस मसले का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

इसके बाद, स्पीकर साहब मैं री-आर्गेनाईजेशन आफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। री-आर्गेनाईजेशन आफ डिस्ट्रिक्ट्स एक बहुत जरूरी बात थी और इसको करके हमारी गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है। जो इलाके ऐसे थे, जहां तरक्की नहीं हो सकती थी वहां ऐडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करके उन इलाकों में तरक्की करने के लिये गवर्नमेंट ने जो काम किया है मैं उसकी तार्ईद करता हूं लेकिन

इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनको नुकसान हुआ है, खासकर महेन्द्रगढ़ शहर है वहां की तहसील के कुछ गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लगा दिये हैं। उसकी वजह से वह सबडिविजन बहुत छोटा पड़ गया है और महेन्द्रगढ़ की इकोनोमी में फर्क पड़ा है, उसकी इंपोर्टेस में फर्क पड़ा है। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से यही दरखास्त है कि ऐसी जगहें जिनकी री-आर्गेनाइजेशन की वजह से इंपोर्टेस कम हुई है, जिनको नुकसान हुआ है, उनको कम्पनसेट करने के लिए, वहां की तरक्की के लिए, उन लोगों को हौसला देने के लिए, उनकी दिक्कतों को दूर करने लिए, डिवैल्पमेंट का काम जल्दी से जल्दी किया जाये। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव चौधरी स्वरूप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसकी ताईद करता हूँ।

**चौधरी मनफूल सिंह (झज्जर):** स्पीकर महोदय, राज्यपाल साहब का यह जो ऐड्रेस है यह हाउस के सामने दो रोज पहले से जेरे गौर है और आज भी इस पर चर्चा जारी है। यह तो ठीक है कि हरियाणा बनने के बाद हर तरह से हरियाणा ने तरक्की की है। जब हरियाणा वजूद में नहीं आया था, जब हरियाणा बनने जा रहा था तब हमारी पड़ोसी स्टेट पंजाब के सभी भाई कहते थे कि हरियाणा का गुजारा नहीं होगा। वह बात उनकी गलत साबित हुई। हरियाणा ने जो तरक्की की है उसने सारे हिन्दुस्तान के नक्शे में जगह बना ली है। राज्यपाल जी का जो ऐड्रेस है उसमें उन्होंने कृषि की बाबत, बिजली की बाबत,

प्रोजैक्ट्स की बाबत जो जो बातें की हैं वे दरुस्त हैं जहां तक तरक्की का सवाल है लेकिन एक दो बातें वे छोड़ गये हैं जिनके बारे में मैं कुद कहूंगा।

स्पीकर साहब, जहां तक कृषि का सवाल है, यह बड़ी अहमियत का सबजैक्ट है। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में कहा है कि 1966-67 की 26 लाख टन की पैदावार 1972-73 में 47 लाख टन हो गई है। उन्होंने सफा चार पर यह भी कहा है कि किसान को उसकी पैदावार की ठीक कीमत मिली है। यह फिकरा है कि:-

“The procurement of surplus food grains has been stepped up in order to meet the requirements of deficit States of the country and also to ensure fair price to the producers.”

स्पीकर साहब, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसान को इस किस्म से उसकी पैदावार की फेयर प्राईस मिली है। गेहूँ का भाव इन्होंने 76 रुपये क्विंटल फिक्स किया है। अगर किसी ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किसी ऐक्सपर्ट से इसका हिसाब लगवाया जाये तो यह बात गलत सिद्ध होगी कि किसान को आज उसकी पैदावार की ठीक कीमत मिल रही हैं। जिस रेट पर उसे खाद मिलती है, जो उसके ट्रैक्टर की कीमत है जिस कीमत पर उसे ट्रैक्टर के इंप्लीमेंट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से तो 80-85 रुपये में एक क्विंटल गेहूँ तैयार होता है।

**(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुईं)**

इसके जवाब में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनके पास यह मिसाल होगी कि दूसरी तरफ कितने आदमी हैं जो लेबर का काम रकते हैं, लैंडलैस लेबर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो अनाज पैदा नहीं करते, वे इतना मंहगा अनाज कैसे खरीद सकते हैं ? इसका इलाज तो यह है कि किसान को तो उसकी पैदावार की ठीक कीमत मिले, ठीक दाम मिले और जो आदमी लेबरर्ज हैं, लैंडलैस लेबरर्ज हैं, सरकारी कर्मचारी है, जो अनाज खरीदकर खाते है उनको गवर्नमेंट सबसे डाइजड रेट्स पर अनाज मुहैया करें। दूसरे मुल्कों में भी यह है कि किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत मिलती है, ठीक भाव के पैसे मिलते हैं और उसको सरकार सबसे डाइजड करके गरीब आदमियों को फेयर प्राईस शोप्स की मारफत सस्ते दामों पर देती है।

### **15.00 बजे**

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी आपके द्वारा दरखास्त है कि यह जो 76 रूपये क्विंटल का भाव गेहूं का रखा हुआ है यह कम है। जो उनकी आनी लागत आई हुई है उन्हें उससे भी कम मिलता हैं। आप यह देखिये कि 76 रूपये क्विंटल का भाव आज से चार पांच साल पहली था और आज भी वही है। इन चार पांच सालों में हर बीज की कीमत बढ़ गई है। किसान जिस ट्रैक्टर को 14 हजार में खरीदता था आज वही उसको 28-29 हजार में मिलता है। फर्टिलाइजर का जो कट्टा 12-13 रूपये का मिलता था, आज वही कट्टा 37-38 रूपये का मिलता है। ऐग्रीकल्चर

इम्प्लीमेंट्स के भाव बढ़ गये, बिजली के दाम दुगने तिगुने हो गये हैं परन्तु किसान के गेहूं का भाव वही 76 रुपये क्विंटल चला आ रहा है। जब किसान की जरूरियात की चीजों की कीमत दुगनी हो गई है तो अनाज की कीमत भी बढ़नी चाहिये। इसलिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहना कि किसान को उसकी कीमत ठीक दी जा रही है यह ठीक नहीं है। उसको कम कीमत मिलती है, कीमत को बढ़ाना चाहिये।

किसान की दूसरी जरूरियात की काफी चीजें हैं, जिनके उसको दुगने दाम देने पड़ रहे हैं। यदि किसान ने आज एक मकान बनाना है तो उसे जो पत्थर, लोहा, सीमेंट और ईंट आज से पांच साल पहले जिस भाव पर मिलती थी आज वही चीजें उससे दुगने भाव पर मिलती हैं। पहले एक किसान के मकान बनाने में दस हजार रुपये लगते थे लेकिन आज उसी मकान को बनाने में 20-25 हजार लगते हैं लेकिन जो वह काश्तकारी करता है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ी। आज उसकी रोजाना की जरूरियात की चीजों के भाव भी काफी बढ़ गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये किसान को फूडग्रेन्ज की फेयर प्राईस नहीं मिलती है, कीमत कम मिलती है।

फसल के टाईम पर गेहूं का भाव 76 रुपये क्विंटल का था। उस टाईम पर छोटे किसानों को अपना अनाज बेचना पड़ता है, 90 फीसदी छोटे किसानों को बेचना पड़ता है, क्योंकि उनकी जरूरियात ही इतनी होती है कि उनमें पैसे की जरूरत रहती है।

दस फीसदी किसान ऐसे होते हैं जो 100–200 मन अनाज अपने घर पर रख सकते हैं लेकिन छोटे किसानों को 76 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचा वही गेहूं बाद में 110 रुपये से लेकर 140 रुपये क्विंटल तक बिकता है। आप अन्दाज लगायें इतना भाव बाद में बढ़ जाता है। छोटे किसान को फसल के टाईम पर अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए अनाज बेचना पड़ता है, परन्तु बाद में उसी किसान को मंहगे भाव का अनाज खरीदना पड़ता है। दूसरे, जो गरीब आमदी है एक साल का स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं उनको भी मंहगा खीदना पड़ता है। वे थोड़ा-थोड़ा खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो लोग माहवारी तनख्वाह लेते हैं उनको भी मंहगा हो खरीदना पड़ता है। जिस अनाज को छोटे किसान ने फसल के टाईम पर 76 रुपये क्विंटल खरीदना पड़ता है ज्यादा पैसा देना पडता है। बाद में जो कीमतें बढ़ती हैं इसका फायदा किसको हुआ ? वह पूंजीपतियों, सरमायेदारों और बड़े बड़े किसानों को होता है जो बहुत ज्यादा स्टॉक रखते हैं। फसल के टाईम पर 76 रुपये क्विंटल और बाद में 140 रुपये क्विंटल के भाव से गेहूं मिलता है 64 रुपये क्विंटल का फर्क है। इससे आप अन्दाजा लगायें कि वे कितना लाभ उठाते हैं। यह जो 64 रुपये क्विंटल का फर्क है यह अमीर की जेब में जाता है। इसका न छोटे किसान को फायदा हुआ, न ही गरीब आदमी को हुआ जिसे हर महीने अनाज खरीदना पड़ता है और किसान को उसके उत्पादन की फेयर प्राईस नहीं मिली।

डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब के अभिभाषण में कुछ प्रोजैक्ट्स का भी जिक्र है। इस साल हरियाणा में बिजली की बड़ी दिक्कत रही है। पिछले साल तो किसानों को बिजली दिन की बजायें रात को मिलती थी लेकिन इस साल काफी कमी रही है। यह ठीक है कि सरकार थर्मल प्रोजैक्ट लगाने जा रही है। पानीपत में और बदरपुर में भी यह प्रोजैक्ट लगाने जा रही है। इसके अलावा ब्यास प्रोजैक्ट पर भी बिजली पैदस की जायेगी। मेरी आपके द्वारा सरकार से दरख्वास्त है कि इस काम को जल्दी से जल्दी करे ताकि किसानों को जो सबसे ज्यादा बिजली की कमी महसूस कर रहे हैं, वह मिल सकें। किसान को जब तक उसकी मर्जी के मुताबिक बिजली नहीं मिलेगी तब तक वह ठीक नहीं होगा, वह अपनी पैरावार को नहीं बढ़ा सकता है। जैसे सरकार नहरों पर पैसा लगाकर पानी देने की सहूलियत दे रही है इसी प्रकार से बिजली का भी प्रबन्ध करना चाहिये। लोगों ने जहां पर ट्यूबवैल्ज लगाये हैं वे बिजली के बिना खाली पड़े रहते हैं। अब उन ट्यूबवैल्ज को उखाड़कर डिजल के ट्यूबवैल्ज लगा रहे हैं या पम्पिंग सैट्स लगा रहे हैं। इसलिये मैं फिर गुजारिश करता हूं कि बिजली की कमी की ओर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, राजपाल महोदय ने दस्तकारी के बारे में भी अपने ऐड्रेस में जिक्र किया है। यह ठीक है कि जिस एरिया में दस्तकारी होती है उस एरिया की तरक्की होती है, उसका पिछड़ापन भी दूर होता है, उस इलाके की उन्नति भी होती

है, रोजगार मिलता है और ऐम्पलायमेंट भी मिलती हैं लेकिन एक बात आप देखें कि जहां पर दस्तकारी शुरू हो जाती है, वहां सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। सब वहीं पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं। हमारे नजदीक सोनीपत और उधर फरीदाबाद पड़ता है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे वहीं जाते हैं। जो एरिया तरक्कीयाफता हो चुका है, अब उसकी बजाये बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज ऐस्टैब्लिश करनी चाहियें ताकि पिछड़े हुये इलाकों की भी उन्नति हो सके, तरक्की हो सके, वहां के लोगो को ऐम्पलायमेंट मिल सके, रोजगार के साधन पैदा हो सकें और उस इलाके को ऊपर उठा सकें। दस्तकारी के सिलसिले में मेरी हाउस से दरखास्त है कि यह इकट्ठी नहीं होनी चाहिये। जैसे हमारे यहां झज्जर, नाहड और महेन्द्रगढ़ है इनमें दस्तकारी नहीं है। मैंने कई दफा सरकार से दरखास्त की है कि जो बैकवर्ड एरियाज है उनमें दस्तकारी लगानी चाहिये लेकिन सरकार ने कोई विशष ध्यान नहीं दिया और न ही गवर्नर साहब के ऐड्रेस में कोई ऐसी बात कही गई है।

मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, इंडस्ट्री के बारे में एक और बात भी करना चाहता हूं। मिल्क प्लांट्स भी एक तरह से इंडस्ट्री ही है। गवर्नर साहब के ऐड्रेस में दो बड़े मिल्क प्लांट्स का जिक्र किया गया है कि जींद और भिवानी में लगाये जा चुके हैं तथा तीसरा प्लांट अम्बाला में लगाने जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने परसों हाउस में माना था, तसलीम किया था कि सबसे ज्यादा दूध झज्जर तहसील से आता है। उनके कहने का मतलब यह था कि वहां



सबसे ज्यादा दूध मिलता है। जब वहां से दूध लाते हैं तो वहां से लाने में बहुत खर्चा होता है। हमारे एरिया के दूध को जींद में लाया जाता है। यदि एक मिल्क प्लांट वहीं पर लगा दिया जाये तो यहां से ले जाने का गवर्नमेंट पर खर्चा नहीं पड़ेगा। जहां आप अम्बाला में मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं वहां हमारे एरिया में भी लगाना चाहिए। मैं अम्बाला का विरोध नहीं करता, वहां भी लगाना चाहिए। लेकिन हमारे एरिया में तो लगाना बहुत जरूरी है। 150-200 मील से दूध ले जाना पड़ता है, खर्चा ज्यादा पड़ता है। इसीलिये आपके जरिये सरकार से मेरी दरखास्त है कि झज्जर एरिया में मिल्क प्लांट अवश्य लगाना चाहिए क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा दूध मिलता है।

गवर्नर साहब के ऐड्रेस में इकोनोमिक डिस्पैरिटी की बात कही गई है। हर आदमी चाहता है कि डिस्पैरिटी दूर हो। हर आदमी का, हर पार्टी का यह प्रोग्राम होता है कि समाजवाद लाया जाये चाहे दिल से वे न चाहते हों लेकिन इलैक्शन के दिनों में ये कहेंगे कि हमारी पार्टी का मैनिफैस्टो यह होगा। हरेक पार्टी का प्रोग्राम यह होता है कि डिस्पैरिटी दूर हो लेकिन असलियत क्या है इसका कुछ पता नहीं होता। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में यह बताया कि इकोनोमिक डिस्पैरिटी दूर हो रही है, जल्दी ही दूर हो जायेगी। मेरी आपके द्वारा सरकार से दरखास्त है कि जब तक आमदनी का हिसाब मुकरर नहीं किया जायेगा तब तक समाजवाद कैसे आ सकता है ? मुलाजिम की तन्खाह में एक और आठ की

रेशो हो, एक और दस की हो, एक और बारह की हो, कुछ न कुछ रेशो हो। कोई आदमी तो अरबपति बना बैठा है और कोई आदमी 100 रूपये महीने की तनखाह लेता है। अगर एक सरकारी मुलाजिम 200 रूपये माहवार लेता है तो आफिसर की तनखाह 2000 रूपये कर दी जाये। कोई हदबन्दी तो होनी चाहिये इसी प्रकार से जब तक आमदनी में हदबन्दी नहीं होगी तब तक इकोनोमिक डिस्पैरिटी दूर हो, समाजवाद आये लेकिन उन्होंने यह नहीं फरमाया कि वह कैसे दूर हो ? तो मैं आपके जरिये सदन से दरखास्त करता हूँ कि जब तक सरकार कोई असल नहीं अपनाती है, कोई हदबन्दी मुकर्रर नहीं करती है तब तक यह डिस्पैरिटी दूर नहीं हो सकती है। हर आदमी की आमदनी पर हर मुलाजिम की तनखाह पर जब तक हदबन्दी नहीं होगी उस वक्त तक हम समाजवाद की तरफ कदम नहीं उठा सकते हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक और बात जो है वह यह है कि इस ऐड्रेस में कुरप्शन को दूर करने का कोई जिक्र नहीं है। यह एक मानी हुई बात है, सरकार भी मानती है और हम भी कहते हैं कि कुरप्शन को सरकार कभी भी अकेली दूर नहीं कर सकती। इसके लिये पब्लिक की को-ऑप्रेशन भी जरूरी है। कुरप्शन को दूर करने के लिये क्या उपाय किए हैं, यह तो दूर की बात है लेकिन इसमें तो इन्होंने कुरप्शन का जिक्र भी नहीं किया है। कुरप्शन को कैसे दूर किया जाये, यह बड़ी जरूरी बात है। मैं आपसे द्वारा सदन से यह दरखास्त करता हूँ कि यह एक ऐसा

मसला है जो सारे देश के अन्दर फेला हुआ है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी तरफ अगर संजीदगी से न सोचा गया, गौर न किया गया और इसे दूर न किया गया तो इससे सारे देश का बेड़ा गर्क हो जायेगा। पहले तो यह होता था कि अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसको साबित करो अब यह कि है रिश्वत कौन नहीं लेता, यह साबित करो। अगर किसी को कहें कि फलां आदमी रिश्वत नहीं लेता है तो वह कहता है कि साबित करो रिश्वत नहीं लेता। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह तो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर इसका कोई इलाज हो जायें तो अच्छा है वरना तो सारा ढांचा ही खराब हो जायेगा।

एक मामला और है जो टैक्स इवेजन का है। इसमें इन्कम टैक्स भी है, सेल्ज टैक्स भी है और ऑक्ट्राय भी शामिल है। इस बारे में बड़ी ब्लैक है, बड़ी गड़बड़ है और बड़ा घपला है। इसके लिये भी राज्यपाल महादेय ने अपने ऐड्रैस में कोई बात नहीं कही है। सेल्ज टैक्स की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले दियासलाई पर कोई सेल्ज टैक्स नहीं था। आप सेल्ज टैक्स लगने से पहले की फिगर्ज देख लें और अब की फिगर्ज देख लें उसमें बहुत फर्क पैदा हो गया है। दुकानदार दूसरी चीजों को भी पहले माचिस की बिक्री के रूप में दिखता था लेकिन जब से इन पर सेल्ज टैक्स लगा है तब से सारी की सारी माचिसें गोदाम में चली गई हैं। इनसे गोदाम जरूर भरे पड़े हैं, लेकिन वह कागजात में नहीं दिखलाता। एक माचिस जो लगभग 8-10 पैसे की आती है,

उस पर सेल्ज टैक्स लगने से पहले की बिक्री का हिसाब देख लें और लगने के बाद का हिसाब देख लें, दोनों में बहुत अन्तर हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि देश के अन्दर सेल्ज टैक्स, इन्कम टैक्स और औकॉट्राय की बहुत चोरी होती है।

इसके इलावा राज्यपाल महोदय ने एक और बात नहीं कही जो सबसे जरूरी है और वह है फैमिली प्लानिंग की। फैमिली प्लानिंग से जरूरी कार्ड दूसरा मसला सारे देशमें नहीं है। लेकिन इस ऐड्रेस में इसका कार्ड जिक नहीं है। आप इस देश में कितने ही ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेंज खोल दे, दाखिले पूरे नहीं हो सकते, कितने ही आप अस्पताल खोल दे, अस्पतालो में सब को जगह नहीं मिल सकती, कितनी ही आप बसे चला ले, बसो में सबको जगह नहीं मिल सकती। जब तक आप फैमिली प्लानिंग पर जोर नहीं देंगे, तब तक कोई दूसरा मसला हल नहीं हो सकता। इसके लिए हमारी स्टेट हैल्थ मिनिस्टर, जो अकेली है, काम में जुटी रहती हैं। मैं आपके द्वारा चौधरी भजन लाल जी से दरखावस्त करूंगा कि वे उनकी सहायता करे और फैमिली प्लानिंग को हमारे देश के अन्दर और स्टेट के अन्दर कामयाब बनाये।.....  
....(व्यवधान).... इसके लिए फोर्थ फाईव ईयर प्लान का जो बजट था वह 6 करोड़ का था। अगली प्लान में मैंने इसके लिए 4 करोड़ देखा हैं। मेरे विचार में और महकमो से रूपया काटकर इस और ज्यादा रूपया रखा जाये। जब तक आप फैमिली प्लानिंग पर पूरी तवज्जुह नहीं देगे तब तक कोई मसला हल नहीं होगा

।मै तो इस बारे में यहा तक कहूंगा, फिर आप कहेंगे कि यह अन-कांस्टीच्यूशनल है कि अगर इस देश को आगे ल जाना है या इस कौम को कुछ बनाना है तो इस बारे में एक कानून बनाना पड़ेगा कि शादी के बाद केवल दो बच्चे पैदा करो । जब तक फ़ैमिली प्लानिंग का मसला हल नहीं होगा तब तक चाहे देश कितनी ही तरक्की कर ले, वह आगे नहीं बढ़ सकता । बेशक हमारा हरियाणा अनाज में आज सरप्लस है लेकिन देश में तो अनाज सरप्लस नहीं होता । हमारा अनाज दूसरी स्टेट्स को चला जाता है हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इस मामले में डैफिसिट में हैं । हम चाहे कितनी ही पैदावर कर ले, जब दूसरी स्टेट्स में कम अनाज पैदा होगा । और पापुलेशन बढ़ती जायेगी तो यह सब बेमायने है । देश का सबसे बड़ा मसला तो तब हल होगा जब फेमिली प्लानिंग का मसला हल हो जायेगा ।

**कृषि मंत्री (चोधरी भजन लाल):** माताओ और बहनो से भी कह दो ।

**चौधरी मनफूल सिंह:** मैने तो कहा है कि आप उनकी सहायता करे । राज्यपाल महोदय ने अपने ऐड्रेस में यह लिखा है कि प्रांत में सौ प्राइमरी स्कूलज खोले गये । इसमें कितने स्कूल प्राइमरी से मिडल अपग्रेड हुये और कितने मिडल से हाई स्कूल हुये, इसका जिक नहीं है । सवालो के दौरान हमें जवाब मिला था कि इस साल के दौरान कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं होगा । कई जगहें ऐसी हैं जहां पर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगज हैं यह भी

ठीक है कि बजट का ज्यादा हिस्सा आप तरक्की के कामों में लगाये, हालांकि स्टेट में पहले ही स्कूल काफी हैं लेकिन आप अपग्रेडेशन तो बिल्कुल बंद न करे । जहाँ पर बिल्डिंगें अच्छी हैं, तीन चार मील तक कोई मिडल स्कूल नहीं है, लोगों ने लाखों रुपया लगाया हुआ है और लोगों की जैनुइन डिमांड है वहाँ पर मैं आपके द्वारा सरकार से दरखास्त करता हूँ कि अपग्रेडेशन जरूर की जाये । चाहे आप सारी स्टेट में 20-30 ऐसे स्कूल खोलें लेकिन खोले अवश्य । हर कांस्टीचुएँसी में एक या दो स्कूल जरूर खोले जाये वरना जो लोगों ने दो-तीन साल से लाखों रुपया है वह बेकार पड़ा रहेगा । वहाँ पर बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं और लोग यहाँ चंडीगढ़ में फिरते रहते हैं कि हमारे यहाँ कब तक स्कूल बनवायेगे ?

अबोहर और फाजिल्का के बारे में दोलता साहब ने भी जिक्र किया है और कांग्रेस बैचिज की ओर से भी जिक्र हुआ है । फाजिल्का और अबोहर के लिये यह एक दुरस्त मौका है । अगर इस मामले को ठील देते गये इस तरफ हमने गौर नहीं किया, इस तरफ हमने ध्यान न किया या इसको महने ठीक ढग से न उठाया तो यह हमेशा के लिए जिस तरह से पहले हमने चंडीगढ़ का मामला ठीला रखा था और वह हमारे से चला गया था यह भी हमारे हाथ से चला जायेगा । अब इन इलाको का क्या हाल है ? न तो पंजाब वाले इसका ध्यान रखते हैं और नही हरियाणा वाले अपने इन इलाको को भूलते हैं । ये वे इलाके हैं जो हमारे अपने

इलाके है और इसके लिए हमें अपना संधर्ष और तेज करना होगा। चाहे काग्रेसी भाई है या दुसरे हैं, यह सब का इकट्टा की मसला है। अबोहर और फाजिल्का के बारे में प्रधानमंत्री से या सैन्टर से या किसी भी मिनिस्टर से बड़ी संजीदगी के साथ यह मामला उठाना होगा वरना अगर यह मामला ढीला पड़ गया तो जैसे चण्डीगढ हमारे हाथ से चला गया, वैसे ही अबोहर और फाजिल्का भी हमारे हाथ से चला जायेगा। जितना जरूरी यह मामला है उतना ही जरूरी इसे लिया नहीं जा रहा है। मैं आपके द्वारा सदन से यह दरख्वास्त करता हूं कि फाजिल्का और अबोहर हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितने कि हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं। यदि अबोहर और फाजिल्का हमें चन्द दिनों में न मिले तो फिर यह मामला खटाई में पड़ जायेगा। जब सन् 1966-67 में चण्डीगढ का मामला चल रहा था, उस वक्त भी हम कुछ ढीले पड़ गये थे। पंजाब और सैन्टर वाले उससे यह समझे कि हरियाण को इसकी जरूरत नहीं रही क्यों कि हरियाणा की तरफ से इस बारे में कोई मांग नहीं उठी और न ही कोई रिप्रैजेंटेशन हुई। इस वजह से मेरी आपके द्वारा सदन से दरख्वास्त है कि अबोहर और फाजिल्का का मामला तरक्कीयात कीसब स्कीमों से ज्यादा अहमियत वाला मामला है, इसमें हमारा सब का इंट्रैस्ट है इसलिये इसकी तरफ ध्यान न दिया जाये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात ठीक है कि हरियाणा हर चीज में दूसरी स्टेटों से आगे। जैसे इंडस्ट्री में तथा और दूसरी कई चीजों में।

**उपाध्यक्षा:** चौधरी साहब, आप कितना टाईम और लेंगे ?

**चौधरी मनफूल सिंह:** एक दो मिनट। हरियाणा ने ऐग्रिकल्चरल प्रोडक्शन, नहरों और बिजली आदि के मामले में काफी तरक्की की है। जितनी तरक्की हरियाणा ने की है, उतनी तरक्की हिन्दुस्तान में किसी भी दूसरी स्टेट ने इसके मुकाबले में नहीं की है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।

टीचर्ज का मसला है इसके बारे में सरकार का कुछ गलतफहमी रह गई। कुछ टीचरों का भी यह ख्याल था कि यह मसला इतनी गंभीर शक्ल अख्तियार नहीं करेगा। शायद हमारा भी यह ख्याल नहीं था कि इस मामले में इतने आदमी इकट्ठे हो जायेगे। हमारा यह ख्याल था कि इसमे इतने ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता यह मामला एक गंभीर मामला बनता चला गया। मेरी इस बारे में लीडर आफ हाउस से यही दरख्वास्त है कि अगर इस मामले को सुलझा लिया जाये तो यह स्टेट के इंट्रैस्ट में ठीक होगा वरना इससे शिक्षा का स्तर खराब ही होगा। आज इस हड़ताल की वजह से स्कूलों में इन-डिसिप्लिन आ गया है। एक गांव की मैं आपको बात बताऊं कि वहां पर क्या हुआ ? गांव वाले स्कूल में वहां के टीचर्ज से यह कहने लगे कि आप बच्चो को पढ़ाते क्यों नहीं ? इस पर स्कूल के बच्चो ने वहां के टीचर्ज पर भी और पब्लिक मैन पर भी पत्थर मारने शुरू कर दिये। सारे के सारों को स्कूल से निकाल दिया।



इस तरह से आज स्कूलों में इन-डिसीप्लिन पैदा हो गया है इसलिये मेरी लीडर आफ दी हाउस से यह दरखास्त है कि इस मामले में किसी न किसी तरीके से समझौता किया जाये ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर जो रेजोल्यूशन श्री सरूप सिंह ने रखा था उस पर बहस हो रही है। ये शब्द तो मैं बाद में कहूंगा कि हम लोग गवर्नर साहब के आभारी हैं और सब को बगैर किसी शक-शुबह के उनके अभिभाषण का समर्थन करना चाहिये ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर हम इस ऐड्रेस को देखे तो पता चलता है कि तकरीबन हरेक डिपार्टमेंट में और हरियाणा में जो तरक्की हुई है उसकी सही तस्वीर इसमें खीच कर रखी है और अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाये तो पता चलता है कि हरियाणा में कितनी तरक्की हो रही है। अगर हम फूड प्रोडक्शन को ही ले तो मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में जितनी तरक्की हुई है। पहले हमें अपने खाने के लिए बाहर से एक लाख टन अनाज मंगाना पड़ता था लेकिन पिछले साल ही हमने 26 लाख टन अनाज बाहर भेजा है और इस दफा भी जैसा कि बताया गया है 32 लाख टन अनाज बाहर भेजेंगे। इसके अलावा मेरे अपोजीशन के भाई तथा कुछ दूसरे भाई कहते हैं कि किमतें बढ़ रही हैं। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए इस सरकार अनाज के होलसेल ट्रेड को अपने हाथ में ले रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब

होता है जब मैं देखता हूँ कि इसके लिए ऐजीटेशन होता है, कई डैपुटेशन मिलते हैं कि ऐसा न किया जाये । पता नहीं लोग इसकी मुखालिफत क्यों करते हैं ? अगर हम इस स्कीम को देखे तो जो कच्चा आढ़ती है उसको तो कार्ड नुकसान ही नहीं है, उसको खत्म नहीं किया जा रहा है और न उस पर कोई असर होगा। उसको तो जो उसकी आढत होगी वह मिल जायेगी। जब किसान अपने माल को मण्डी में लाता है तो उसका ख्याल होता है कि उसके माल की कीमत ठीक मिल जाये। अगर सरकार उस माल को खरीद कर अपने पास रखती है तो इससे कच्चे आढ़ती को क्या फर्क पड़ा ? फर्क तो उसको पड़ता है जो माल का स्टॉक करता है और जो आदमी स्टॉक करता है वह 6 महीने के बाद उस स्टॉक करता है वह 6 महीने में के बाद उस स्टॉक से इतना पैसा कमा लेता है जितना कि किसान ने दिन रात एक करके मेहनत की और उसके बाद भी उसको उतना फायदा नहीं हुआ। यह बड़ी नाजायज बात थी और इसीको सोचकर सरकार ने ऐसा किया और इससे कीमते भी नहीं बढ़ेगी। सरकार का ध्येय मुनाफा कमाना तो है नहीं। वह तो उस अनाज पर पर जो खर्चा आयेगा उसी हिसाब से पब्लिक को बेचेगी। मैं कहता हूँ कि यह चीज बहुत पहले की कर देनी चाहिए थी। ताकि जनता को इसका फायदा पहले ही पहुंचता। इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो कि पूंजीपति है और वही इस सम्बन्ध में मुजाहरे कर रहे हैं। जो हमारे अपोजीशन के भाई हैं उन्होंने तो हाउस में गवर्नमेंट की हर चीज को चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो, क्विटसाइज ही करना है लेकिन

अगर उनसे हाउस के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं कि यह ठीक है।

इसी तरह से बिजली जो कि हरियाणा के सारे गांवों में पहुंच चुकी है। हरियाणा सारे देश का पहला सूबा है जहां पर सबसे पहले सारे गांवों में बिजली दे दी गई है। इसी तरह से एग्रेरियन रिफार्म था। इसमें भी हरियाणा का पहला प्रांत था जिसने यह काम सब से पहले किया।

हरियाणा ने सबसे पहले अच्छा एक काम और किया कि टोटल ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया है। इस काम में हरियाणा सब से फर्स्ट है। जब हमारा प्रदेश इतनी तरक्की कर रहा है तब विरोध क्यों किया जाये ? अभी मेरे एक अपोजीशन के भाई ने कहा कि ट्रांसपोर्ट में ऐसी लगजरीज हो रही है कि सीनेमा दिखाये जाते हैं। एक तरफ तो जब हम दूसरे देशों की बातें करते हैं तो सब कहते हैं कि दूसरे देशों ने इतनी तरक्की कर ली है। मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका आदि देशों जितनी तरक्की हुई है उसके मुकाबले में तो हम पासंग भी नहीं हैं।

**चौधरी राम लाल वधवा:** मैं तो यह कहा था कि आम आदमी को दिखाओ, केवल अमीरों को नहीं।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** अगर आपने यह कहा था कि सब को दिखाओ तो यह अच्छी बात है लेकिन कोई भी चीज शुरू की जाती है तो उसमें कुछ दिक्कतें होती हैं। जब 1952 में

चंडीगढ़ की बाबत सरकारने फैसला किया कि चण्डीगढ़ को बसाया जाये तो उस वक्त यहां सिर्फ नदी नाले थे लेकिन आज चण्डीगढ़ को वर्ल्ड का बड़ा मशहूर और बैस्ट सिटी होने के नाते से इनाम मिला है। शुरू में कोई आसमान पर नहीं पहुचता, तरक्की जो होती है वह आहिस्ता-आहिस्ता होती है।

इसी तरह से इरीगेशन को ले लें तो मैं कहूंगा कि वह बराबर बढ़ रही है। मैं तो अपने इलाके नारायणगढ़ की बात कहूंगा और उसकी बाबत जब बजट पर बोलूंगा तो बताऊंगा कि वहां और क्या होना चाहिए। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि तरक्की नहीं हुई। नारायणगढ़ का ऐरिया ऐसा था कि आज तक जितने सर्वे हुये यदि उनकी रिपोर्ट देख ली जाये तो, उनमें यही लिखा हुआ है कि वहां पानी नहीं है इसलिये ट्यूबवैल लगाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जब सर्वे हुआ तो पता चला कि वहां इतना पानी है उसमें कमी नहीं आ सकती। यह ठीक है कि हमारे यहां नहर नहीं आ सकती। लेकिन अगर झज्जर का काम बन गया तो जिस तरह से जुई कैनल का लिफ्ट इरीगेशन से काम हुआ है उस तरह से तो हम भी नहर का स्वप्न देख लेगे। हमारे इलाके में ट्यूबवैल्ज की काफी तरक्की हो रही है। लोग पहले हमारे यहां जाते थे और आज अगर वे उधर जाकर देखे तो काफी फर्क नजर आयेगा। पहले यह था कि चाहे किसी तरफ से चले जाओ बरसात के दिनों में तो कमर तक पानी के कास किये बगैर नारायणगढ़ नहीं पहुच सकते थे लेकिन इसकी बाबत तो मैं बाद में कहूंगा

लेकिन जो तरक्की हुई है उसकी सराहना तो करनी चाहिए। दूसरे ऐरियाज जैसे महेन्द्रगढ़ या हिसार के हैं जो बैकवर्ड हैं उनको प्रैफैल देकर तरक्की करनी चाहिये ताकि इलाको के लोगो में जो बैकवर्डनैस है वह दूर हो सके ।

अभी कुछ देर पहले दौलता साहब ने कहा था कि कौ-आपरेशन और कुरप्शन को इकट्ठा कर दें तो एक चीज है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो कौ-आप्रेटिव डिपार्टमेंट है उसमें और जगहो से करप्शन बहुत कम है। मैं इस बारे में बताऊं कि कोआप्रेटिव सैक्टर में जो डिपोज है और इंडिविजुअल्ज के पास जो डिप्रोज है उनको अगर आप देखे तो दोनो मे दिन रात का फर्क है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह ठीक है कि कहीं करप्शन हो सकती है लेकिन वह जो सिस्टम है उसमे हमें सुधार लाना चाहिए और वह सुधार इस तरह से लाये कि वहां पर अच्छे आदमियो की सिलैक्शन हो। हर जगह पर कुरप्शन है, किस जगह पर करप्शन नहीं है ? को-ओपरेटिव सोसाईटिज में और इंडिविजुअल सोसाईटीज में कितना फर्क है। मुझे बारे में पता है क्योंकि मैं बहुत अर्से से को-ओपरेटिव सोसाईटिज से संबंधित रहा हूँ। आपकी जो ये राईस मिलज है और जो इंडीविजुअल्ज की है जब उनसे चावल लेने की बात आती है या उनको ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो उस वक्त बड़ा ताज्जुब होता है कि को-ऑपरेटिव की निस्बत प्राइवेट वाले वैगन्ज वगैरह जल्दी ले

आते हैं। इसकी वजह यह है कि इंडीविजुअल्ज तो कोई मीन्ज इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा सकत है और को-ऑपरेटिव की मे तो ऐसे मीन्ज नहीं है क्योकि वे लोग कुछ दे नहीं सकते हैं। लिहाजा उनका माल पीछे कर देते है। तो मै यही कहूंगा कि जहां पर को-ऑपरेटिव और प्राइवेट का सवाल है, वहां हमे को-ऑपरेटिव को पहले तरजीह देनी चाहिए बल्कि मै तो हरियाणा सरकार व भारत सरकार से कहूंगा कि जब रेलवेज में यह चीज आती है, वैगन्ज वगैरह की तो को-ऑपरेटिव को पहले तरजीह देनी चाहिए ताकि अगर वहां कहीं पर कोई कुरप्शन है तो वह कम हो जायेगी। इसके अलावा मै यह भी अर्ज करूंगा कि कुरप्ट आदमियो की हमे सिफारिश नहीं करनी चाहिये, हमें ऐसे आदमी के पीछे पड़ जाना चाहिये। तभी उन लोगो मे ऐसे कामो के लिए काफी रुकावट आयेगी और यह कुरप्शन भी काफी हद तक बन्द हो जायेगी। अगर हम ऐसा करेगें तो ऐसे काम करने के वक्त वे कुछ धबरार्येंगे । लेकिन जब उस को लीड मिलती है तो उसमें हौसला आ जाता है। डिप्टी साहिबा, गवर्नर ऐड्रेस में, अगर मोरनी हिल्ज का जिक्र आता तो ज्यादा अच्छा होता क्योकि मोरनी हिल्ज का ऐरिया ऐसा है कि उस की तरक्की बड़ी तेज रफतार से होनी चाहिए । अगर बजट में किसी प्रकार की कट हो जाये, तो उसमें उसको शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे सड़को के मुताल्लिक सरकार ने सलो-डाउन किया है। सरकार अगर मोरनी की सड़क को देखे तो आधी इधर से बनी हुई है और आधी उधर से बनी हुई है बीच में कुछ गैप सा रह गया है। उसको जल्दी ही पूरा कर

देना चाहिए। अगर उस गैप को जल्दी की पूरा न किया गया तो कही ऐसा न हो कि बना हुआ हिस्सा भी वैसे ही पड़ा हुआ नाकारा हो जाये। इसलिये इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए ताकि वहां पर तरक्की के कार्य हो सके ।

**उपाध्यक्षा:** आप कितना टाईम और लेंगे क्योंकि अभी और भी मैम्बर बोलने वाले है ? आप 2 मिनट और बोल सकते है ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** ठीक है। डिप्टी स्पीकार साहिबा हमारे प्रधान जी और मेरे दोस्त दौलता साहब ने कहा और मैं उसकी ताईद भी करता हूं कि शाह कमीशन ने जो फैसला किया था, वह हमारे बड़े भाई पंजाब का पंसद नहीं आया और फिर उसने बावेला मचाया तथा प्राईम मिनिस्टर ने उस पर अवार्ड दे दिया। उस अवार्ड को यहां लागू होना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि शाह कमीशन का जो फैसला था अक्वल तो उसकी ही सरकार को लागू करवाना चाहिये नहीं तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अपना अवार्ड दिया कि चण्डीगढ़ पंजाब में ही रहेगा और फाजिल्का और अबोहर का इलाका हरियाणा के पास रहेगा, उसको जल्दी से जल्दी लागू करवाये जाये। पंजाब तो चण्डीगढ़ का भी मजा ले रहा है और फाजिल्का व अबोहर भी नहीं छोड़ रहा। दोनो में से कोई बात तो पंजाब को माननी पड़ेगी। अब जबकि दोनो सूबो ने कांग्रेस की हकूमत है मैं सरकार से कहूंगा कि प्राईम मिनिस्टर के अवार्ड को या तो लागू करवाया जाये या शाह कमीशन का फैसला लागू करवाया जाये वरना 1975 की जनवरी में

हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जायेगी। अगर चण्डीगढ़ एक दफा बिना कुछ लिये दिये हाथ से निकल गया तो मैं यकीन से यह कह सकता हूँ कि फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा.....(विधन).

.....

**चौधरी प्रताप सिंह दौलता:** बिल्कुल ठीक है।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसलिये मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड को जल्दी से जल्दी लागू करवाये जाये। मैं एक दो बातें और अर्ज करूंगा। हमने गरीबी दूर करनी है। अब सरकार ने फैसला किया है कि जो लैंडलैस लोग हैं, उनको हाउस साइट्स मिले। जो ऐपिलकेशनज आती हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो देहातों की बजाय शहरों में रहते हैं। इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हमने पहले ऐग्रेरियन रिफार्मज के सिलसिले में किया है उसी तरह से हमें जोर डालना चाहिए कि सीलिंग आन प्रॉपर्टी जो है उसको जल्दी लाये ताकि जो आदमी गरीब है उन्हें भी कुछ राहत मिल सके उन्हें भी फायदा पहुंच सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐजुकेशन और टीचर्स के बारे में इस हाउस में बहुत शोर हुआ। उसके बारे में, मैं एक दो बातें आप से कहना चाहता हूँ। जहां तक ऐजुकेशन की तरक्की का सवाल है पिछले साल यानि 71-72 की निस्बत 72-73 में 400 प्राइमरी स्कूल और खोले गये हैं। यह कोई मामूली सी बात नहीं है। इसी से ही आप तरक्की का अन्दाजा लगाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह तरक्की इसी तरह से



होती रहेगी। यह ठीक है कि इस साल बजट में प्रोवीजन ज्यादा नहीं था इसलिये आगे के लिए यह प्रोविजन ज्यादा होना चाहिए। टीचर्ज के मुतालिक मैं यह कहूंगा कि उन्होंने ऐसे मौके पर स्ट्राइक की है जबकि बच्चों के इम्तहान सिर पर है। यह ठीक बात नहीं है यह सरासर नाजायज है और सही बात नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि एक टीचर को ऐसी बात सूझी क्यों ? उसके दिमाग में ऐसी बात आई क्यों ? बल्कि इसके स्थान पर तो टीचर्ज को चाहिये था कि वे अपनी मांगों के बारे में सरकार के पास आते । जैसे टीचर वगैरह जब उन्हें नोकरियां नहीं मिलती तो बार बार इंटरव्यू पर जाते हैं कि हमारी नोकरी का प्रबन्ध करें तो इसके लिए भी बार बार उन्हें सरकार के पास आना चाहिए था। ऐसा करने से उनकी तकलीफ सरकार जरूर दूर करती। लेकिन उन्होंने यह सब कुछ सोचते हुए भी की लड़कों के इम्तहान सिर पर है, हड़ताल की। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके पास दूसरी रैमिडी भी थी, वे हाईकोर्ट में भी जा सकते थे। 1969 में टीचर हाई-कोर्ट गये वह उनकी रिट 16 जुलाई, 1971 को खारीज हो गई । अगर उसमें कोई जान होती तो टीचर्ज ये यह कहूंगा कि यह हड़ताल उन्हें वापिस लेनी चाहिए। सरकार के यह देखना चाहिए कि अगर सरकार ऐसे यह मानने लग गई तो सरकार का दीवाला निकल जायेगा और जनता के ऊपर और टैक्स लगेंगे..... (विघ्न)...(धंटी).....

**उपाध्यक्षा:** आपको बोलते हुये बहुत टाईम हो गया, अब आप बन्द करिये क्योकि और मैम्बरो ने भी बोलना हैं ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप बार—बार घण्टी बजा रही है मै तो थोड़ी सी बाते ओर कहना चाहता था ।

**उपाध्यक्षा:** टाईम बहुत हो गया है हाउस के दूसरे मैम्बरो ने भी बोलना है । अब श्री उमेद सिंह बोलेंगे ।

**चौधरी हरद्वारी लाल:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे भी टाईम देने के लिए कहा गया था ।

**उपाध्यक्षा:** आपको बाद में जरूर टाईम मिलेगा ।

**श्री उमेद सिंह(मैहम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मै गवर्नर साहब के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अभिप्राय सरकार की नीति और कार्य पर प्रकाश डालना होता है । यह परम्परा अग्रेजो के समय की एक पुरानी परम्परा है । मै चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में राज्यपाल महोदय के ऐड्रैस की बजाये चीफ मिनिस्टर साहब सदन में अपना वक्तव्य दे । बंगाल की असैम्बली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजय सिंह नाहर ने यह मांग की है कि । तो मै आपसे प्रार्थना करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के स्थान पर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य विधानसभा का सैशन शुरू होन से

पहले दे । राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह निश्चित रूप से से सरकार के तेज गति से काम करने को दर्शाता है ।.....

**उपाध्यक्ष:** आपने विजय सिंह नाहर पंजाब में कहा है वे तो बंगाल के हैं ।

**श्री उमेद सिंह:** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बंगाल ही कहा है पंजाब का नहीं । तो मैं अर्ज कर रहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के काम काज को दर्शाता है । मैं सरकार से इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि बंसी लाल सरकार ने कम से कम एक चीज में तो राष्ट्र में प्रथम नम्बर पाया है और वह है परिवहन का राष्ट्रीयकरण । समाजवाद के लिये यह एक बहुत की महत्वपूर्ण कदम है । हरियाणा की बसों की सर्विस सारे राष्ट्र में नम्बर एक पर है । जैसे राव साहब ने कहा कि जनसंध के श्री यज्ञदत्त शर्मा ने उनको बात-चीत में कहा कि हरियाणा की बसों की सर्विस देश में नम्बर एक पर है । लेकिन जनसंध वाले दिल में किसी बात का चाहे सच्ची भी मानते हों पर स्टेज पर और पब्लिक में उनकी झूठ बोलने की आदत है । फिर भी जो कुछेक कमियाँ हैं उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा । जैसे बस-स्टैंडज पर सफाई के प्रबन्ध के बारे में है । इसके बारे में मैंने महसूस किया है जैसे रोहतक बस-स्टैंडज है वहाँ पर टट्टिया वगैरह जो हैं न तो उनके दरवाजे और न ही पानी का इंतजाम है । इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए दूसरी चीज बस स्टैंडज पर जो कैंटीन है उनके बारे में है । कई जगहों पर इनका

इन्तजाम बहुत अच्छा है जैसे करनाल में सरकार ने नो प्रोफिट नो लोस बेसिज पर कैंटीन खोली है। लेकिन अम्बाला में कोकाकोला की बोतल बाजार में तो 60 पैसे की मिलती है बस स्टैंड पर 80 पैसे की मिलती है। इसी तरह एक दूसरे बस स्टैंड की बात है और मेरा खुद का तजुरबा है कि जूस का छोटा गिलास जो बाजार में एक रूपये में मिलता है वह स्टैंड पर 1-50 का मिलता है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो ।

**एक अवाज:** शराब का भाव भी बता दे। .....(विधन)

**श्री उमेद सिंह:** सरकार करप्शन को रोकने के लिए बहुत काम कर रही है जो कन्डक्टर है उनकी भी चैकिंग होती रहती है लेकिन जो लम्बे रूट की बसें हैं से झुनझुनु और रोहतक जयपुर इनकी चैकिंग पूरे तौर पर नहीं होती। मेरी मांग है कि इनकी भी पूरी चैकिंग की जाए। पीने के पानी का जहां तक संबंध है सरकार ने इसके आरे काफी उठाये हैं । अब तक सरकार ने 529 गांवों को जल सुविधा प्राप्त करवाई है परन्तु जहां हरियाणा में 6669 गांव हैं तो ये 529 गांव तो आटे में नमक के बराबर हैं। सरकार से यह बात कहूंगा कि स्वास्थ्य के लिये जो बढ़िया पानी होता है वह उपलब्ध नहीं है। कई जगह पानी में क्लोरीन की मात्रा अधिक होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जहां ऐसी बात हो वहां इसकी चैकिंग करके उचित मात्रा में क्लोरीन डालनी चाहिए। इसलिये वाटर सप्लाई स्कीम्ज की तरफ ज्यादा से

ज्यादा ध्यान दिया जाये । चिकित्सा के बारे में काफी काम किये गये हैं। परन्तु मैं सरकार का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वह और हॉस्पिटल खोले, उनमें डाक्टरों की संख्या बढ़ाये । यह भी एक जरूरी बात है । सबसे बड़ी जो बात है वह मास ऐजुकेशन की । जनता के विश्वास के प्रति उसको जागरूकता करना, लोगों की बीमारियों से बचाव करने संबंधी बातें बताना। विनरल डिस्सीजिज(यौन रोगों) के बारे में लोगों को शिक्षा देनी। लेकिन हमारा समाज कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से लोगों को इस बारे में बता नहीं सकता। लोगों को बीमारियों के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे उनको प्रिवैन्ट करने के तरीके अपना सकें । चाईना में जब कम्युनिज्म आया तो पांच करोड़ ओदमी इस तरह की विनरल बीमारियों से पीड़ित थे परन्तु सरकार ने उस तरफ ध्यान दिया और उनका बचाव किया गया आज वह मच्छर मक्खी तथा चूहे बिलकुल नहीं रहे। ऐसा करना अच्छी बात है चाहे वह कोई भी देश हो । मैं चाहता हूँ कि हर सरकार को यह चाहिए कि वह इस किस्म की बीमारियों को दूर करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करे । मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जो गुरु गोविन्द सिंह कालेज फतेहबाद के बारे में है। गुलाटी साहब ने विद्यार्थियों के बारे में कहा । मेरी सहानुभूति न तो विद्यार्थियों के प्रति है और न ही उस आदमी के प्रति है। जो लड़के डाक्टर बनने के काबिल थे उनको दाखिला नहीं दिया गया और जो काबिल नहीं थे। उन्होंने रूपयों के बल पर दाखिला ले लिया । मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस तरह के मैडिकल कालेज का

किसी भी हालत में खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जिन आदमियों ने गलत काम किये हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए ।

जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम उनके आग्र अपना सिर झुकाते हैं और हमें महसूस होता है कि संसार का बहुत बड़ा आदमी हमारे सामने है । मैं कहता हूँ कि अगर अध्यापक वही गुरु का स्टैन्डर्ड रखे और उसी तरह करें जिस तरह पहले वक्तों में अध्यापक पढ़ाया करते थे तो हरियाणा की जनता और हम विधायक सभी उनकी सहायता करेंगे । मैं अध्यापकगण ये सहां सदन में प्रार्थना करता हूँ कि वे हड़ताल को वापस लेकर अपने काम पर आये और उनको उनके काम का ईनाम मिलेगा । एक बात मैं और कहना चाहूंगा और जैसे कि जैन साहब की तरफ से भी इस बारें में एक प्रस्ताव आया है कि वह जो प्राइवेट इंस्टीच्यून्शन्ज है, तालीमी अदारें है, इनको नैशलेलाइज किया जाये । मैं भी इसे पक्ष में हूँ । अगर सरकार से पास इस वक्त धन की कमी है तो कम से कम मैट्रिक स्टैन्डड तक जो स्कूल है उनको जरूर नैशलेलाइज कर देना चाहिए । इसके साथ-साथ जो टैक्सट बुक्स की तरफ ही बच्चों का ध्यान दिलाया जाये ताकि उनकी ओरिजनैलिटी खत न हो । मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात की तरफ भी ध्यान दे ।

सरकार ने खेती के मैदान में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है । गांव-गांव में बिजली पहुंचाकर, ट्यूबवैल्ज लगाकर और

दूसरी इरीगेशन की स्कीम्ज को प्रायोरिटी देकर लोगों को खेती के लिए पानी देकर सरकार ने बहुत ही अच्छा, सरहानीय काम किया है जिसे लियेवह हम सब की बधाई की पात्र है। परन्तु हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम साईटिफिक ढंग से खेती का काम करने लगेंगे। यह तभी संभव हो सकता है अगर बड़े-बड़े फार्म बना दिये जायें। चाहे जमीन को नैशलेलाइज करके बनायें, चाहे को-ऑप्रेटिव तरीके से बनायें। अगर इस तरह से छोटी-छोटी दो-दो बीघे की और दो-दो बीघे की और दो-दो कले की लैंड होल्डिंग्स चलती रहेंगी तो न इतनी छोटी खेती के लिये अच्छे बैल रखे जा सकते हैं, न पूरी खाद और न ही अच्छे बीजों का प्रबंध इतने छोटे किसानों की तरफ से किया जा सकता है। इन छोटी-छोटी होल्डिंग्स को मिलाकर अगर को-ऑप्रेटिव ढंग से हजारों बीघे के फार्मज हों जिन पर ट्रैक्टर चलें, अच्छे बीज और खाद डाली जायें, साईटिफिक ढंग से खेती हो और हवाई जहाज से दवाइयां छिड़की जायें तो हम ज्यादा पैदावार करने की अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो स्नातक निकलते हैं उनको नौकरी देने की बजाय उनके लिये एक स्कीम बनाई जायें और वह यह कि लैंड सीलिंग हो जाने से जा सरप्लस जमीन निकले उस हरिजनों में बांटन की बजाय उसके बड़े-बड़े सरकारी काफर्म बना दिये जायें। हां उनमें यह किया जायें कि ऐम्पलायमेंट उनमें हरिजनों और लैंडलैस लोगों को ही दी जायें और हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्नातक निकले उन

फामर्ज पर मैनेजर बनाकर उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाये और उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाये कि जितना ज्यादा वे अन्न पैदा करेगे उतनी ही ज्यादा उनकी तरक्की होगी और तन्खाह मिलेगी। अगर सारी जमीन के ऐसे बड़े-बड़े सरकारी फार्म बना दिये जाये। हां उनमें यह किया जाय कि ऐम्पलायमेंट उनमें हरिजनों और लैडलैस लोगों को ही दी जाये और जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्नातक निकलें उन फामर्ज पर मैनेजर बनाकर उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाये और उन पर यह जिम्मेदारी डाली जाये कि जितना ज्यादा वे अन्न पैदा करेगे उतनी ही ज्यादा उनकी तरक्की होगी और तन्खाह मिलेगी। अगर सारी जमीन के ऐसे बड़े-बड़े सरकारी फार्म बना दिये जाये। हां उन में यह किया जाये कि ऐम्पलायमेंट उनमें हरिजनों और लैडलैस लोगों को ही दी जाये और जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से स्नातक निकले उन फामर्ज पर मैनेजर बनाकर उनकी योग्यता का परीक्षण किया जाये और उनपर यह जिम्मेदारी डाली जाये कि जितना ज्यादा वे अन्न पैदा करेंगे उतनी ही ज्यादा उनकी तरक्की होगी और तन्खाह मिलेगी। अगर सारी जमीन के ऐसे बड़े-बड़े तो उसके कुछ हिस्सों के फार्म बनाकर उनकी मैनेजमेंट उन स्नातकों के हवाले करके यह ऐक्सपैरीमेंट जरूर किया जाना चाहिए। (घंटी) मुझे पांच मिनट और दे दे तो ठीक रहेगा, वरना मेरे कुछ प्वायंट्स रह जायेगे।



**उपाध्यक्षा:** आप दो मिनट में खत्म करे क्योंकि बहुत बोलने वाले है और संत जी को भी टाईम देना है।

**श्री उमेद सिंह:** संत जी के बारमें भी मै दो मिनट जरूर लेना चाहूंगा और एक दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे संता जी चीफ पापुलैरिटी लेने के लिए अध्यापकों के लिए बड़ा दर्द दिखाते है कि उनके दिल में उनके लिए बड़ा दर्द है। रात को उनको नींद नहीं आती। इन्होंने अखबारों में एक लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि बंसी लाल जी ने उनको स्टेट की डिक्लेरमेंट के बारमें मिसगाईड किया था वह मिसगाईड हुये या नहीं हुये लेकिन कम से कम एक बात मै जरूर कह सकता हूं कि हम जरूर मिसगाईड हुये है।.....(विधन).....

**चौधरी राम लाल वधवा:** किस की तरफ से?

**श्री उमेद सिंह:** हम समझते थे कि वे सरकार की जो अच्छी नीति है, अच्छे काम है उनका समर्थन करेगे और जहां कमियां है उनके बारें में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम करके ठीक सुझाव देगे लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता लगा कि संत जी न तो सरकार का समर्थन करते है और न विरोध करते है। वह तो अपना पैसा बनाने में और ब्लैमेलिंग मे लग रहते है। ये कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते है और कभी कुछ और कह देते है। चौधरी हरद्वारी लाल जी के साथ तो यह कहावत पूरी उतरती है जो

हमारे देहात में प्रचलित है कि 'पिटी हुई डूमनी गाये आल पचाल अर्थात एक निराश आदमी गलत सलत बात कहता है।

**चौधरी राम लाल वधवा:** आप समर्थन के लिये लगे हुये है या अपोजीशन के लिए?

**श्री उमेद सिंह:** यह आप ही देख ले कि मैं क्या कर रहा हूँ।

**चौधरी राम लाल वधवा:** मिसगाईड किसने किया आपको?

**श्री उमेद सिंह:** चौधरी हरद्वारी लाल ने। (हंसी).....  
.....तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो बिजली की कमी हरियाणा में हो रही है उसके लिये थर्मल प्लांट्स लगाकर इस कमी को दूर किया जाये। इसके अलावा केन्द्र से पैसे लेकर सहायता लेकर ऐटोमिक एनर्जी पैदा करके इस बिजली की कमी को पूरा किया जाये।

मैं एक बात स्पोर्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि दूसरे देश क्यों हमसे स्पोर्ट्स के मैदान में आगे निकल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे देशों में बचपन से ही बच्चों को स्पोर्ट्स के लिये फिजीक बिल्डिंग की जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। दौड़ने, कुश्ती, जिमनास्टिक वगैरा-वगैरा खेलों के हिसाब से शुरू से ही उनको ढाला जाता है और फिजीकल

एक्सर्साइज करता है, मसल बिल्डिंग कराते है। लेकिन हमारे यहां तो 15/16 साल की अमर में खेलना शुरू कराते है, प्रौपर मसल बिल्डिंग खेल के हिसाब से नहीं हो पाती है। पहले मसल और तरीके के बने होते है फिर और बनते है और इस तरह हमारे खिलाड़ी अच्छी फिजिक नहीं बना पते है। इसलिए यह जो स्कूल खोला गया है इसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और वह धन्यवाद की पात्र भी है। अब हरियाणा भारतवर्ष में ऐसे खिलाड़ी पैदा कर सकेगा जो दुनिया में इस देश का नाम ऊंचा करेगे। इन शब्दों के साथ मैं अंत में मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और उनसे यह प्रार्थना और आशा करूंगा कि वे लगातार हरियाणा से गरीबी दूर करने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि यह जो कुरप्शन की बीमारी है, और जो मुनाफाखोर और होरडर्ज है उनक पर कड़ी दृष्टि रख कर हरियाणा को तरक्की के मैदान में आगे ले जायेगे। मैं इसके साथ साथ मैबर साहिबान से भी प्रार्थना करूंगा कि वे जहां पर कही कोई कमिया है उनको ठीक रकने के लिये सरकार को सहयोग दे और कंस्ट्रक्टिव नुक्ताचीनी करें। मैं अपनी तरफ से सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की जो अच्छी नीतियां है उनमें मैं अपना पूर्ण सहयोग सरकार को देता रहूंगा।

**श्री गरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जा

प्रस्ताव चौधरी सरूप सिंह जी ने सदन के सामने रखा है और गौड़ साहब ने जिसका अनुमोदन किया मैं भी उसका समर्थन करके चंद बाते सदन के सामने आपके जरिये रखना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सदन में आया है वह बड़े अजीब तरीके से आया है। इस ऐड्रेस में तीन मुख्य बातें हैं। एक तो उन्होंने यह औब्जैक्टिव रखा है। कि हमने किस उद्देश्य से काम करना है! दूसरी बात रखी है कि हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे कारनामों आज क्या हैं और आगे चलकर भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं? ये तीन बातें हमने हर वर्ग के विकास के लिए बना रखी हैं। इस औब्जैक्ट को लेकर आज हमारी प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस देश में समाजवाद की नई रूप रेखा रखने का वचन लिया है और इस चीज को पूरा करने के लिए कारगुजारी का कदम उठाया है। हम ऐसा प्रदेश बनायेंगे जिसको कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्टेट कहते हैं और उसमें से हमें गरीबी दूर करनी है। सिर्फ गरीबी ही दूर नहीं करनी है सामाजिक विषमता का भी दूर करना है। हमने ऐसी कल्याणकारी स्टेट बनानी है। जिसमें सामाजिक विषमता कतई दूर हो। समाजवाद क्या चीज है? समाजवाद कहते हैं इक्वैलिटी आफ अपॉरचुनिटी और इक्वैलिटी आफ ह्यूमन स्टेटस इन सोसाइटी का पूरा मौका मिले। अगर गेनफुल एम्प्लायमेंट मिलेगी, काम करने का पूरा मौका मिलेगा तो व्यक्ति अपनी काबिलियत को जाहिर कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम गेनफुल एम्प्लायमेंट पैदा करें, काम

करने की लियाकत पैदा करे, उससे पहले हमें शिक्षा की जरूरत है। किसी देश में समाज को आगे बढ़ाने की बात तब तक नहीं हो सकती जब तक उस देश में शिक्षा का विकास न हो। इसलिए हमारे प्रदेश में शिक्षा की बहुत जरूरत है और सरकार ने इस पर बहुत जोर दिया है। गेनफुल ऐम्प्लायमेंट के लिए राज्यपाल के ऐड्रेस में भी जराये रखे गये हैं और कल सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटस में भी ऐजुकेटिड अन-ऐम्प्लायमेंट को दूर करने के लिए धन की व्यवस्था की गई। ये चीजे सदन के समाने आई और आपकों मालूम है कि किस तरह सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन इन सब चीजों को राने के लिए एक चीज बहुज रुरी है जिसकी तरफ मै सदनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारा मुल्क आजाद हुआ, हमें सियासी आजादी तो मिल है लेकिन वह सियासी आजादी मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक इकतसादी आजादी हासिल न हो, जब तक इकौनोमिक फ्रीडम लाने के मायेन है कि दिल और दिमाग आजाद हो जाये। दिल वह ही जिस के अन्दर सच्चाई, सदाचार और निर्भयता व सादगी हो और दिमाग वह हो जो दिमागी परेशानियों से दूर हो, ऐसा दिलो दिमाग होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारा दिमाग परेशान किया है, और वह है रोटी का सवाल चिकित्सा का सवाल, मकान का सवाल, शिक्षा समुचित का सवला और इसके अतिरिक्त और भी कई सवाल हैं। दिमाग की आजादी तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक दिमाग परेशान है, जब तक दिमाग को परेशान करने

वाले प्रश्न दूर नहीं किये जा सकते तब तक दिमागी परेशानी दूर नहीं होगी। यह बहुत बड़ी चीज है जिसको हमने समझना है। हमने इन प्रश्नों का दूर करने के लिए कोशिश करनी है, इनके लिए जराये पैदा करने है और जराये पैदा करेगे के लिए पहले देखा जाता है। कि हमारी इकानौमिक पोजीशन क्या है डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा स्टेट एक छोटी सी स्टेट है जब यह स्टेट बनी थी तब इसकी क्या हालत थी, यह सब को मालूम है। उस वक्त केवल 36 करोड़ का रैवेन्यू था। इस प्रदेश में और तरक्की करते-करते अजा रैवेन्यू डबल से आगे हो गया। हमने आमदनी के जराये खुदखुद पैदा किए, सैन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया और कई लूप-होलज डाउन किए। सबसे बड्ती चीज जो इस वक्त जनता के लिए बहुत जरूरी है वह बिजली की सप्लाई। जहां तक बिजली की सप्लाई का ताल्लुक है, आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। सड़के 60 परसेंट बन गई है और कुछ रह गई है।

जहा तक पानी का सवाल है, एक समय था जब हमारे देश में पानी की बड्ती कमी थी जहा पर रेगिस्तान था, कुछ नहीं उगता था, वहां आज पानी के साधन पैदा किए गए है। हमने अम्बाला को पानी नहीं देना है, हिसार और भिवानी के इलाकों को भी देना है ताकि रेगिस्तान बढ़ता बढ़ता कहीं अम्बाले तक न आ जाए। हमने पानी इनके लिए ही नहीं हरियाणा की स्टेट को उठाना है न कि किसी विशेष इलाके या वर को, हमने तो सारी स्टेट में विकास के काम करने हैं पिछले कुछ अर्से में बहुत से

सवालों को हल किया गया है और स्टेट को ऊंचा उठाया गया। जब ये प्रश्न हल नहीं हुए थे तो यही वजह थी हम सिर्फ 26 लाख अन अनाज पैदा करते हैं कि अपने खाने के बाद सैन्ट्रल गवर्नमैट और केरल गवर्नमैट को अनजा देते हैं। हम उन प्रदेशों को अनजा देते हैं जहां भुखमरी है। हरियाणा वह प्रदेश है जो बहुत पिछड़ा हुआ था और अज देसरो को अनजा देने वाला बन गया, यह हरियाणा प्रांत के लिए बहुत बड्डी चीज है। यह सब कारगुजारी हरियाणा सरकार ने की है डिप्टी स्पीकरसाहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हमने लैंड रिफार्म किया है। यह हमारी बहुत बड्डी अचीवमैट है। एक साथी ने बताया कि हरियाणा स्टेट हर चीज में नम्बर वन पर है। आप इलैक्ट्रिसिटी की उन्नति की बात ही न ले, बल्कि हरियाणा स्टेट सबसे पहली स्टेट है जिसने लैंड रिफार्म को एकट भी सबसे पहले पास किया। जहां तग नैषनेलाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है यह भी एक सराहनीय कमद है ट्रांसपोर्ट नशनेलाइजेशन से हरियाणा की ट्रांसपोर्ट की शकल तबदील हो गई है। मैंने वह वक्त देखा है जब यहां पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टी चलते थे। मेरे एक विधायक है वे पहले ट्रांसपोर्टर थे लेकिन अब नहीं रहे। कल वे मजदूरों के लिए कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन जब वे मालिक थे तो मजदूरों की बात को भूल गये थे और उनकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट तक गए और कुछ मुलाजिम मर गए लेकिन उसवक्त उनके दिल में मुलाजिमों के प्रति कोई प्यार नहीं उमड़ा। आज जब नैशनेलाइजेशन आफ ट्रांसपोर्ट हो गइ तो ये बातें करने लगे कि

ट्रांसपोर्ट गलत है, इसमें खामिया बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट सारे हिन्दुस्तान में सब से बढ़िया है। सिर्फ ट्रांसपोटी ही बढ़िया नी है, ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को जो सहूलियते दी गई है वे सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। आज ड्राइवर और कंडक्टरा को 500 से 550 रूपये तक तनक्षाह मिलती है और 12 परसैट बोनस मिलता है। वर्दी भी फस्ट क्लास मिलती है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपकी मारफत सदन को बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को टैरीकाट और वाशा एंड वीयर की वर्दियो दी है ताकि वे धाये और पहल कर बड़े आराम ये चले। एक चीज जरूर है कि हमारे पास वैहिकल्ज ज्यादा नहीं है। जिस वक्त गांव गांव में सड़के बने जाएंगी, ट्रांसपोर्ट चलने लगेगी, बिजली का विकास होने से गांव-गांव छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगेगी तो हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जो दूसरों को रास्ता दिखायेगा कि हम क्या कर रहे है, आगे क्या करेगे और किस तरह आगे बढ़ेगे हम हिन्दुस्तान के आगे एक नमूना पेश करेगे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैडिकल फैसिलिटीज में भी हरियाणा सरकार ने काफी कारगुजारी की है। कई स्कीमें बनाई गई है। पहले ये स्कीमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर तहसली लेवल पर और फिर गांवों में खेलने की कारगुजारी की जा रही हैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैडिकल फैमिलिटीज पर सरकार पहले 5 रूपये प्रति व्यक्ति खर्च करती थी लेकिन आज 10 रूपये खर्च कर



रही है मैडिकल फ़ैसिलिटी में खर्च दुगना हो गया है, आखिर यह खर्च काम करने से हुआ है, लोगों को राहत देने से हुआ है।

इसी प्रकार एजुकेशन में हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की है। प्राईमरी स्कूल से अप-ग्रेड करके मिडल स्कूल और मिडल स्कूल से हायर सेकैन्डरी स्कूल किए गए। इस तरह से इन चीजों के द्वारा एजुकेशन के सिलसिले में हम आगे बढ़ जाऐगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जहां स्कूल हो, चाहे वह प्राईमरी हो, मिडल हो या हायर सेकैन्डरी हो, वहां शिक्षा एंसी होनी चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने लायक बन सके। बच्चे के अन्दर अपने पांव पर खड़े होने की बात पैदा करने के लिए सबसे जरूरी चीज चरित्र उत्थान की है और शिक्षा के साथ ऐसा ढंग पैदा करने की है जिससे बच्चा शुरू से ही समझे कि उसका किस तरफ जाने का रुझान है ताकि वह अना और अपना और अपने देश नाम रोशन करे। स्पोर्ट्स का भी जरूर ही ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारा प्ररेश पहलवानी में सबसे आगे रहा है। अभी बनारस में इन्टर स्टेट अज़ैर आल इंडिया कंपिटीशजं हुएथे। उसमें हमारे एक नौजवान बच्चे ने , जिसका नाम झांगी राम ळै और जो एम.एल.एन. कालेज यमुनानगर का विद्यार्थी है, अपना खुछ का वेट केवल 51 किलो होते हुए 105 किलो वेट उठाया और इन्टर स्टेट और नैशलन चैम्पियनशिप के दो गोल्ड मैडल किलए। कितनी खुशी की बात है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली में जा इन्टर स्टेट टूर्नामैन्टस चल रहे है उसमे हरियाणा ने दिल्ली

को हाकी में हराकर इन्टर स्टेट टूर्नामेंट में चैम्पियनशीप जीतकर नया रिकार्ड कायम किया है इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स में जो अखराजात किए जा रहे हैं। वे बिल्कुल वाजिब हैं। मैं तो यह भी कहूँगा और पहले भी कहना चाहता था मगर मुझे उस समय बोलने का मौका नहीं मिला कि सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट में राई में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के लिए जो नौन रैकरिंग ग्रांट दी गई है। वह रैकरिंग ग्रांट होनी चाहिए। हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, आपने देखा ही था कि म्युनिख ओलम्पिक में क्या बात रही थी? हरियाणा के बच्चे अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाएं तो ओलम्पिक में भी तो विदेशों देशों के मुकाबिले में वे गोल्ड मैडल ले सकते हैं। इस तरह हमारी तवज्जुह अवश्य होनी चाहिए।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आ रहा हूँ। इस बात की तरफ कि लेबर के सिलसिले में हरियाणा ने क्या कारगुजारी की है। चूंकि मैं लेबर से ताल्लुक रखता हूँ। इसलिए कह सकता हूँ कि लेबर के सिलसिले में हरियाणा की कारगुजारी किसी भी स्टेट से आगे ही है कम नहीं। हमारे पड़ोस में पंजाब है, उधर दिल्ली है उधर हिमाचल है ओर दूसरी तरफ यू.पी. है हरियाणा ने जा शडयूल्ड ऐम्पलायमेंट खोली और दूसरे दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में नीचे की मिनिमम वेज का स्तर तय कर दिया कि इससे नीचे किसी को वेज नहीं मिलेगा। अब मैं आपके सामने मिनिमम वेज का ब्यौरा रखता हूँ। ब्यौरा इस प्रकार है:—

## मोटर ट्रांसपोर्ट

125 रूपये मिनियम वेज हरियाण में है,  
पंजाब में उतन ही है,  
राजस्थान में 85 रूपये है और  
दिल्ली में 75 रूपये है ।

## टैक्सटाईल इंडस्ट्री

118 रूपये हरियाणा में,  
100 रूपये पंजाब में और  
104 रूपये दिल्ली में है ।

## सा एंड टिम्बर ट्रेड

115 रूपये हरियाणा में,  
100 रूपये पंजाब में ।

## नौन फ़ैरस इंडस्ट्रीज

112 रूपये हरियाणा  
पंजाब 90 रूपये ।  
दिल्ली 65 रूपये ।

साइंटिफिक इंडस्ट्री

110 रूपये हरियाणा

शौप एंड कमशियल ऐस्टैब्लिशमैट

105 से 113 रूपये हरियाणा,

पंजाब में 95 रूपये

यू.पी. में 70 रूपये

दिल्ली में 75 रूपये ।

कंस्ट्रक्शन एंड मैटेनैन्स ऑफ रोडज एंड विलिडिंग  
आपरेशनज

114 रूपये मिनमिम वेज हरियाणा में,

पंजाब में 100 रूपए से कुछ अधिक,

राजस्थान 85 रूपए

और दिल्ली में तीन रूपए पर डे के हिसाब से ।

टयूबवैल्ज आपरेशन

हरियाणा में 171 रूपए ।

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहने का मतलब यह है कि  
यदि नजदीकी स्टेट्स से हरियाणा का मिलान किया जाए ता

हरियाणा का मिनिमम वेज हर स्टेट से आगे रहेगा जैसा कि मैने बतलाया है। इसके साथ ही 50 पैसे और एक रूपयापर प्वायंट राईज डी.ए. में भी दिया है आर कौस्ट आफ लिविंग इंडैक्स से जोड़ कर दिया है। 50 पैसे का मतलब है पचास परसेंट और एक रूपये का मतलब है सैट परमैट म्यूट्रेर्लाजेशन। तो उपाध्यक्ष महोदया, आज हरियाणा मिनिमम वेज के साथ-साथ डी.ए. भी दे रहा है जोकि किसी किसी हिस्टरी में नहीं है, जो किसी स्टेट के कायदे कानून में नहीं दिया है।

दूसरी चीज लेबर के सिलसिले में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा में बहुत बढ़िया की है। जब चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने लेबर पालिसी की डिक्लेयर करते हुए कहा कि लेबर को वीकर सैक्शन माना जाए। आज गवर्नमेंट बड़े सैक्शन के मुकाबले से लेबर की इमदाद करती है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। उस पालिसी के तहत और भी कार्यवाही हुई। इंडस्ट्रियल कोर्ट्स बनी, कंसिलिएशन औफिसिज बने और चही नहीं, हैल्थ के सिलसिले में यह पहली स्टेट है जहां ऐक्सरे से फिटिड मोबाईल प्लांट मूव करता है। लेसिज टू प्लेसिज और फैक्टरी में जाकर वर्कर्स के ऐक्सरे लिए जाते हैं। और रिकार्ड रखा जाता है। टी.वी. एंड हैजारइड्स बीमारियों की जांच होती है ताकि काम करने वाले हृष्ट पुष्ट हैं ज्यादा पैदावार पैदा करें, उत्पादन बढ़े। इन नुक्तातगाह से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां लेबर की रीक्रिएशन के लिए भी बन्ध किया

गया है। यहां ऐनुबल फ़ैस्टिवल डिस्ट्रिक्टवाइज और स्टेवाइज होते हैं जिसमें लेबरर, उसकी फ़ैमिली ओर बच्चे पाटिसिपेट करते हैं बाकायतदा उनको इनाम देते हैं फटी के सिलसिले में डिप्टी स्पीकर साहिबा, सेपटी कौंसिल भी बनाई गई है। इसके लावा हरियाणा सरकार मजदूरों के लिए एक तीमाही जनरल भी निकालती है। जिसमें सारी डिफिकल्टीज का ब्यौरा दिया जाता है। यह लेबर के सिलसिले में हरियाणा सरकार की कारगुजारी है। इसके आग्र हरियाणा में और क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में मेह हमारे राज्यपाल ने अपनी अभिभाषण में दिया है। उनहोंने कहा है कि हरियाणा में क्लास वन और क्लास टू वैलफेयर सैन्टर्ज खेलने के दरकार हैं। इन सैन्टर्ज में स्विमिंग पूल लेडी विंग एंड ऐम्ब्रोडयरीस्कूल, चिल्डर्न क्रेच, प्ले ग्राउंड, नाईट क्लासिज फार अडल्टस डिपैन्सरी और हौस्पिटल का इंतजाम होगा। इस तरह से वहां लेडीज, बच्चों और मर्दों आदि सभी के लिए इंतजाम होगा। आज लेबर आइसोलेटेड क्लास नहीं है। वह अगर है तो बच्चों के साथ है, उसकी औरत भी है, बच्चे भी हैं। हमने उसका उत्थान करना है बतौर फ़ैमिली के। जिहाजा हमने उसे वे सहूलियात देनी हैं जिनमें न सिर्फ लेबरर एंटरटेनमेंट करे बल्कि उसकी फ़ैमिली भी करे।

तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा की लेबर के सिलसिले में तरक्की की बातें में आपसे कह रहा था। अब मैं दूसरी चीज की तरफ आता हूं। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा ने

बनाया। उन्होंने किन मुश्किलों से गांव गां में बिजली पहुंचाई, कितने बड़े इंट्रैस्ट पर पैसा लिया और अपने पांव पर खड़ा होकर तहैया की जाए। मैं कहूंगा कि राज्यपाल का अभिभाषण इतना ब्रौड बैस्ड है जिसका कोई हिसाब नहीं। वह बहुत सारे फ़ैक्टर्ज को टच करता है, सारे फ़ैक्टर्ज को राज्यपाल महोदय ने यहां रखा है और एक असूल की बात हाउस के सामने रखी है। क्या अचीवमेंट्स की है, उनको रखा है और जितना खर्चा किया जा रहा है उसको भी रखा है।

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह बात यह है कि भ्रष्टाचार के सिलसिले में कुछ तो कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकती है, कुछ कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाती है और कुछ कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ाती है और कुछ कहते हैं कि वह भ्रष्टाचार करती है। लोग इस तरह से बड़ी नुक्ताचनी करते हैं मैं कहता हूं कि चोर को पकड़ने के लिए चोर की मां को पकड़ो,। सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार कहां से पैदा होता है? आज हम देखते हैं कि समाज का फ़ैब्रिक, ताना-बाना सब भ्रष्ट है आज हम सब चोर हैं मैं सदन के सामने सामने साफ बत कहता हूं कि अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखो कि हम कहां पर हैं? हमें कोई हक नहीं है। नुक्ताचीनी करने का जब तक हमारा दामन पाक न हो। गांधी जी कहां करते थे कि कहने का हक उसी को है जो कुछ करता है।

जो कुछ करता ही नहीं वह कुछ कह नहीं सकता भ्रष्ट दरअसल हमारा समाज है और अगर आज सही समाजवाद लाना है तो हमें एक नया समाज बनाना है, इस भ्रष्ट समाज को दूर करना है मगर इस भ्रष्ट समाज को दूर करने को हमारे समाज की ऐप्रीज गलत है। दरअसल हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जहां वेद, पुराण, भागवत, रामायण और गुरुवारण आदि जैसे ग्रन्थ लिखे गए और जहां बड़े पवित्र लोग पैदा हुए। उसके बाद यहां विदेशियों का आगमन हुआ, राजाओं और बादशाहों के हम गुलाम रहे। इस संघर्ष से हमारा चरित्र का बिखराव हो गया है। पहले लोग सोचते थे कि समाज में उस इन्सान की इज्जत और मान्यता दी जाए जो सच्चरित्र हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, सदाचारी हो, जिसमें सादगी हो चाहे वह गरीब क्यों न हो। लेकिन आज उसकी इज्जत दी जाती है जो अमीर हो, पैसो वाला हो, सरमायेदार हो, जिसके पास साधन हो। उसके चरित्र में बेशक कोई खोट हो, दुराचारी हो लेकिन आज उसकी इज्जत होती है। गवर्नमेंट की सिर्फ लीगल सैक्शन से इन चीजों का सुधार नहीं हो सकता। इनके लिए सोशल लैक्शन भी होनी चाहिए। यह ठीक है कि वे गलत काम कर लें, ब्लैकमाकिटिंग कर लें, होडिंग, कर लें लेकिन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है जो आदमी सोशल सैक्सन, सामाजिक बन्धानों से परे है ऐसे आदमियों के सोशल फंक्शंस का, उनकी शादियों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। अगर हमें समाज को सही करना है तो



यह करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार कह देने से काम नहीं चलेगा हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं मंहगाई के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। मंहगाई के बारे में भी समाज की बात आ गयी। हमारा समाज क्या हो? आप देखिये, सैन्ट्रल गवर्नमैट का लोक सभा में बजट आया। कुछ अदारों पर टैक्स लगाये गये, उसी वक्त सामान गायब हो गया। वह सामान पुराने दाम का था। अक्सर लगने के बाद कीमत बढ़ी तो सामान गायब हो गया। जिस चीज पर टैक्स नहीं लगा, उस चीज की भी कीमत बढ़ गयी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं वर्कर्स के केसिज फाइट करता हूँ। जिस दिन हम वर्कर्स को बोनस दिलवाते हैं उसके दूसरे दिन ही भाव भी बढ़ जाता है आमतौर पर जब कोई वर्कर अपनी बीबी और बच्चों को बाजार में ला जाता है, पे या बोनस उसकी जेब में होती है। तो बच्चे और बीबी कहते कि यह चीज लेनी है। दुकानदार को पता होता है कि जेब भरी हुई जितना मर्जी आये भाव लगाता है बेचारा मजदूर कुछ भी कहने से लाचार होता है क्योंकि बीबी और बच्चे मजबूर कते हैं। उसको बोनस का कोई लाभ नहीं होता है। एक दिन में ही खर्च कर देता है। जब वह घर जाता है तो उसकी जेब सफाचट होती है उसकी हालत पहले की बनिस्बत ओर गिर जाती है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसकी क्या वजह है? आज सब ने अपने रहने सहने के तरीके को, वे-आफ लिविंग को बदला हुआ है। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिये, हमारी लिविंग

क्याह ीनी चाहिए? हमारे धरेलू चलन का क्या तरीका होना चाहिए? जितनी हमारी आमदनी हो उससे कम न हो तो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए हमें सादगी में रहना चाहिए। हमें क्या जरूरत है कि चार कोट रेखे? मुझे क्या जरूरत है कि इतनी चीजों को होरडिग करूं? हमारे यहां औरते कुछ गहने और कुछ पैसे की होरडिग करती है। नम्बर नम्बर दो का माल तो सभी जगह चलता है। इस पैसे का तो कोई हिसाब नहीं होता है। मैं यह कहे बगैर नहीं र सकता कि जो नम्बर दो माल है, जो काला धन व हपकडत्रा जाना चाहिए। उसे कौन पकड़ेंगा? जो भ्रष्ट तरीकों पर चलने वाले लोग है। जिन पर प्राइमाफेसिया साबित हो जाये कि इन्होंने भ्रष्टचार किया, ब्लैकमाकिटयर्ज है, सामान होर्ड किया है उनसे बारें में एम.एल.एज. का एक कोड होना चाहिए कि हमें ऐसे आदमी को बचाना नहीं है, उसकी सिफारिश नहीं करनी है। उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। अगर उस आदमी को सजा मिलेगी तो उससे दूसरों आदमियों को भी नसीहत मिल जायेगी, तभी यह भ्रष्टाचार निकलेगा। होता क्या है? सभी लोग मिनिस्टरों के पास सिफारिश करने पहुंच जाते है कि इस आदमी को छोड़ दो, इसको बचा दो। तो हमें इनचीजों पर कोड बनाना है, कुछ रिवायात बनानी है, कुछ तरीके ईजाद करने है तभी हमारे भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। भ्रष्टाचार तो हमारे समाज में है। महात्मा गांधी जीन कहा था—

“Hate the sin but no the sinner.”

सिन से नफरत करो, सिन करने वाले से नफरत न करो, उसका सिन दूर करने की कोशिश करो। अगर असका सिन दूर हो जायेगा, वह एक अच्छा इन्सान हो जायेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै हाउसिंग बोर्ड के सिलसिले में भी कुछ आपने विचार रखना चाहता हूं। हाउसिंग बोर्ड ने जो मकान देनक का तरीका रखा है उसमें-----

**उपाध्यक्षा:** आप जल्दी खत्म कीजिए।

**श्री गिरीश चन्द्र जोशी:** मेरा तो यह पहला मौका है मै इससे पहले नहीं बोला हूं। आप कुछ टाईम दे दें तो मेहरबानी होगी। यदि मै जल्दी जल्दी बोलूंगा तो उससे रिपोर्टजै को भी दिक्कत होकगी। मै हाउसिंग बोर्ड के सिलसिले में कुछ बातें रखना चाहता हूं मजदूरों को उससे इतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मेरे विचार के अनुसार तो उस तजवीजत को बदलना पड़ेगा। जिस हिसाब से जमीन ले कर और मकान बना कर किशतों पर मजदूरों को देना चाहते है उस हिसाब से जो डिवैल्पमेंट चार्जिज पड़ता है वह सही नहीं है अधिक है जो मौजूदा स्कीम है इसकी बजाए दूसरी बनायी जोय डिवैल्पमेंट उतनी ही की जाये जितनी उसकी जरूरत है। ऐसा करने से डिवैल्पमेंट चार्जिज कम लगेंगे। मजदूर की पाकिट के हिसार से डिवैल्पमेंट चार्जिज लगाने चाहिए। यह मेरी तजवीज है ताकि वे मकान ले सके।

तीसरी चीज टीचर्ज की स्ट्राइक के बारे में है। मेरे साथी यह सोचते हैं कि इन्टक के नेता नहीं बोले। टीचर्ज को हक को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने मजदूरों के और दूसरों के केसिज लड़े हैं। हमने हड़ताल भी करवायी है। हमें तरीके पता है कि किस तरह से हड़ताल होनी चाहिए, किस बिना पर होनी चाहिए। हरियाणा में टीचर्ज ने जो हड़ताल की है उसमें मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। इसे स्ट्राइक कहिए या जदोजहद कहिए, इसमें सब से पहले हमें यह देखना पड़ता है कि जो हमारी मांग है वह जस्टिफाइड है या नहीं। जस्टिफाई करने के साथ साथ जिनसे मांग की है उनकी एबेलिटी एन्ड स्टेबिलिटी को भी देखना है। यह कायदा है हड़ताल का। जब तक हम इसको नहीं करेगे हमारी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। टीचर्ज ने जो स्ट्राइक है, क्या यह सही है? क्या यह वक्त सही है? आज जब बच्चों के इम्तहान होने जा रहे हैं टीचर्ज ने हड़ताल शुरू कर दी। उनका यह तरीका सही नहीं है। हमारे रोडवेज के वर्कर्स की मांग थी। गवर्नर साहब के टाईम पर 3 दिन की हड़ताल की गयी। गवर्नमेंट इम्पलाइज ने भी हड़ताल की थी। उस टाईम पर कितने ही निकाले गये, ससपैन्ड हुए लेकिन उन लोगों को हमने बाद में री-इनस्टेट करवाया और जो उनकी मांग थी वह भी पूरी करवायी। साढ़े बारह परसेंट उनकी बोनस दिलवाया। आज वही रोडवेज के एम्पलाईज सबसे ऊचे हैं। हमें उन का फख्र है। (तालियां) वह एक तरीका था। वे गवर्नमेंट सर्विसिज में थे उनके भी ग्रीवैन्सीज थे। उनको सही रास्ता बताया तो चीफ मिनिस्टर साहब भी मान गये। इसी

तरह से टीचर्ज भी सही बात और अपनी डिमान्ड को तरीके से रखते तो हमारी चीफ मिनिस्टर साहब कभी इन्कार नहीं करते। मजदूरों के बारें में तोवे कभी इन्कार नहीं करते है। अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट को इनटेरिम रिलीफ दिया गया और वह उस टाईम पर दिया गया जबकि हरियाणा क्राइसिस थे। कुछ पैसा उन्हें नकट दे दिया और कुछ पैसा प्रौविडैन्ड फन्ड में करा दिया। प्रौविडैन्ड फन्ड में जमा करा देने से उनको कितना फायदा होगा? को उस पैसे पर इन्ट्रैस्ट मिलता है और बाद में उस पैसे को डबल पेमेन्ट मिलती है। का भी क्रिटिसिज्म किया। इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की काबलियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। वे बड़ी सूझ बूझ से काम लेते है। दौलता साहब ने ठीक कहा है और मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। जैसा कि कहा गया है:—

गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवों महेश्वरो।

गुरु साक्षात् परम ब्रह्मो तस्मयी श्री गुरुवे नमो।

मैं तो गुरु भगवान को मानता हूँ। टीचर को गुरु नहीं मानता हूँ। ये गुरु नहीं है ये तो गुरु घन्टाल हो सकते है। जिस काम के लिए उनको रखा गया है, जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदार आयद है, जिन्होंने देश को बनाना है, बच्चों को बनाना है उनको हड़ताल पर जाने की जरूरत नहीं। वे अपनी मांगे पेश कर सकते थे। लेकिन वे तो सियास्तदान प्राईम मिनिस्टर साहिबा का और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर असैनिशिनेशन

करना चाहते हैं यह कोई तरीका नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर साहब को सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने ऐग्जिनोरेट तो इनको एक बहाना मिल गया और टीचर्स को लेकर आगे पहुंच गये। ये कहते हैं टीचर्स के साथ यह हो गया, वह हो गया। अगर उनमें हिम्मत हो तो खुद हड़ताल करे। व हड़ताल करे या मरण व्रत रखे। ऐसे ही वे टीचर्स के बड़े भारी हमदर्द बने बैठे हैं। टीचर्स फेमिली का रहा हूं। इसलिये वे मे साथी हैं। मैं आज उनको आह्वान करता हूं कि वे बिना किसी संकोच के अपनी हड़ताल समाप्त कर दें। उनकी मांगों के बारे में हम एक मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। चाहे हाथ जोड़कर करे या किसी और तरीके से करे, समय और मौका देखकर हम उनकी मांगों के लिये चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। यह तरीका ठीक नहीं है कि हम अपनी मांगों के लिए बन्दूक लेकर खड़े हो जाये। इसके में कतई खिलाफ हूं, चाहे इस वजह से मुझे कुछ भी समझे। हम इस बात के बिल्कुल साथ नहीं हैं पेपर्ज ने भी इस बारे में बडत्री पब्लिसिटी दी है। पेपर्ज वाले यहां खुद बैठे वे भी सुन ले, उन्होंने बडत्री गलत पब्लिसिटी दी है। एक कोई हरवेल सिंह चितरंजन नाम आ आदमी है वह औरत की कमाई खाता है। और टीचर्स को एडवाइजर बनता है। जो इसके द्वारा पब्लिसिटी दी गई है, वह बिल्कुल गलत है। यमुना नहर में किसी भी ट्रेड यूनियन टीचर्स की सहयोग नहीं दिया क्योंकि वे हड़ताल नहीं चाहती थी। वह पढ़ाई का मौका है, बच्चे ने पढ़ना है। इसके अलावा हम इकौनोमी की भी बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में यह एक मैन पावर होती है आज सैन्ट्रल सर्वट्स को भी

बोनस मिले जैसे पी.एड.टी डिपार्टमेंट या रेलवेज कौमशियल डिपार्टमेंट है जो इनके के ऐम्पलाईज है, वे गवर्नमेंट को पैसा कमा कर देते है। हरियाणा रोडवेज के सा बिजली बोर्ड के ऐम्पलाईज है, उये भी कौमशियल ऐम्प्राइज है, ये स्टेट को पैसा कमा कर देते है। ये टीचर्ज काक्या है? प्रोडक्शन देने के लायक नही है प्रोडक्शन के िबल नही है। वे कि बुनियाद पर पैसा लेने की उम्मीद करे? अगर उनके स्टैप्स देखे जाये तो बड़े अनुचित है। अगर वे सीधे ढंग से बात करें तो क्या उन लोगो की बात सुनने के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नही होगा? हमारे यहा बहुत से ऐसे भाई है जो उनसे भी नीची तनख्वाह लिय 'बैठे है, ऐसे भी जिनको सौ रूपया भी नही मिलता। वे लोग भी कम करते है जो डेढ सौ रूपया भी नही लेते है। क्या वे इस आजाद देश के रहने वाले नही है? ये सारी सोचने की बातें है हमें इनके रैलेटिवली और औब्जैक्टिवली सोचना है। मै अपने इ अपोजीशन के साथियों से कहूंगा कि जो ये उनकी बातों को बढ़ावा दे रहे है, ये बहुत बड़ी गल्ती कर रहे है। मेरे यमुनानगर के इलाके में कही भी हड़ताल नही है। वहां पर पहले कुछ टीचरो ने गड़बड की थी लेकिन अब सारे जगाधारी सब-डिवीजन में कही कोई ऐसी बात नही है यमुनानगर मे सिर्फ 20 आदमी छुट्टी पर गये हुये है बाकी सब काम पर है और मिडल वगैरा के एग्जाम हो चुके है। बाहर की बात तो मै नही करता लेकिन मै इतना जरूर कहता हूं कि यमुनानगर की बातें भी अखबारों में आ गई है, जो ठीक नही है। इस तरफ से काम नही चलेगा। मै अखबार वालों से

भी अर्ज करूंगा कि ऐस इकोनोमी वाली बातें पर उनकी भी औब्जैक्टिवली सोचना चाहिये और जो पब्लिसिटी वे करते है वे किसी औब्जैक्टिव तरीके से करनी चाहिये। हमारी स्टेट एक छोटी सी स्टेट है और डिवैल्पिक स्टैट है। हमारी इकोनोमी अीी पूरी तरह से साउन्ड नहीं है। अीी हमने बहुत से काम करने हैं हो सकता कि आगे जाकर इस स्टेट के पास साधन हो जायें और इन टीचर्ज के स्केल दुगने कर दे। इन शब्दों केसाथ मै आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उनके सम्बन्ध में जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, मै उसका अनुमोदन करता हूं।

**चौधरी प्रभु राम (छछरौली, अनुसूचित जाति):** डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहब ने जो ऐड्रेस पेश किया था, मै उसकी तार्ईद करता हूं और कहता हूं कि उनहोने एक बहुत अच्छा ऐड्रेस पेश किया। इसके सथ साथ मै अपने चीफ मिनिस्टर साहब, चाञ्जैधरी बंसी लाजी को भी बधाई देता हूं। कि उन्होने हरियाणा स्टेट को थोड़े ही समय के अन्दर हिन्दुस्तान भर में चमका दिया है। इस सरकार के होते हमारे इलाके में बिजली आई, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मेरे इलाके के किसी भी गांव में पहले बिजली नहीं थी। जब भी पहले, मेरे इलाके के गांवो के लोग शहरों में आया करते थे तो वे शहरों में बिजली के पंखे चलते हुए और लाईट जलती हुई देखा करते थे, लेकिन आज हमारे इलाके के घर-घर में बिजली पहुंच चुकी है। इस बारे में



एतराज तो हमारे अपोजीशन के भाईयों को भी नहीं है कि बिजली गांव गांव में क्यों आई। उन्हें तो थोड़ा सा अपना ही लालच है और वह पूरा नहीं होगा। इनको बिजली के कर्मचारियों के बारे में या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में कुछ कहने की आदत सी पड़ी हुई है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने दिन-रात लग कर जिस तेजी से हमारे इलाके में बिजली पहुंचाई उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। हमारे इलाके में तो ऐसे कई देहात हैं जहां पर आदमी पैदल भी बड़ी मुश्किल से जा सकता है लेकिन आज वहां पर हर गांव में बिजली चमक रही है। यह सरकार ने एक बड़ा भारी और काबिले-तारीफ काम किया है। इसके लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी और बोर्ड के कर्मचारियों को भी, जिन्होंने बहुत थोड़े समय के अन्दर इतना बड़ा काम किया है, मुबारिकबाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ, सड़कों के बारे में जो काम हुआ है, उससे भी सभी भाई खुश हैं। मेरे इलाके में तो पहले कोई विशेष सड़कें भी नहीं थी, सिर्फ एक सड़क थी जो जगाधरी से छछरौली तक की थी, उसके आगे कोई सड़क नहीं थी। एक और मिलटरी की सड़क भी थी जो कच्ची थी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उस इलाके में बहुत सी सड़कें पहुंचाई हैं। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो अभी बननी बाकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो बन रही हैं। मेरे ख्याल में जिन गांवों के लिए सड़कें बननी बाकी रह गई हैं, वे भी थोड़े समय में कम्प्लीट हो जायेंगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अलावा हमारे सामने अनाज की पैदावार का एक बड़ा अहम सवाल है। मेरे इलाके में ऐसे कई देहात हैं, आपको भी इस बारे में पता

हैं क्योंकि आप भी उसी इलाके में पैदा हुई हैं, और आने वह घूम फिर कर देखा भी हुआ है कि जो घाड़ का इलाका है पहले वहां पर पैदावार बहुत कम होती थी और यहां तक कि कई जगहों पर तो बिल्कुल ही अनजा पैदा नहीं होता था लेकिन आज वहां पर वही जमीन सोना पैदा कर रही है जिसकी वजह से किसान बहुत खुश हो रहा है। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य प्रिंसिपल ईश्वर सिंह पदासीन हुए) अब गवर्नमेंट ने गांव में अनाज की बहुत सी सहूलियतें कर रखी है। मेरे ख्याल में अनाज के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने से छोटे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। पहले जो किसान भाई अनाज को मंडियों में ले जाते थे उनको उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता था, व्यापारी लोग उससे काफी मुनाफा ले लेते थे। खरीदते वक्त उनको वही अनाज मंहगे िगाव पर मिलता था। इस बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि गवर्नमेंट अनाज का व्यापार अपने कब्जे में लेकर जगह-जगह पर डिपो खोल दे ताकि छोटे किसानों को इससे फायदा पहुंच सकें गवर्नमेंट के इस कदम के लिये भी मैं उसको मुबारिकबाद देता हूं। मेरे इलाके में अनाज की कोई अच्छी मंडी नहीं है। केवल एक छोटसी सी मंडी ब्लाक वाले बना रहे है। अगर एक अनाज मंडी खिदराबाद में बना दी जाये तो वहां के इलाके के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। जहां तक हरिजनों का सवाल है, मेरे इलाके में हरिजन जाति बहुत ज्यादा है। वे बड़े गरीब लोग हैं और बेरोजगार है। अगर मेरे इलाके में उनके लिये कोई इंडस्ट्री बगैरा लगा दी जाये तो उससे उनको रोजगार मिल

सकेगा। उनके वहां पर फूस के मकान हैं, हर साल अक्सर उनमें बारिश हो जाती है और उनकी तबाही हो जाती है। जो हरिजन हैं या ऐसे गैर-हरिजन भी को अपनी रोटी कमाने के कोई साधन नहीं हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, उनको मकान वगैरा मुहैया कर दिया जाये जिसकी कीमत वे किशतों में वापस कर सकें तो ....  
..... भी बच जायेगा और उन्हें सहूलियत भी होगी।

ताजेवाला हैडवर्क्स से निकलती है और करनाल की ओर जाती है। वहां पर यू.पी. का इलाका भी साथ लगता है। उसके किनारे-किनारे यू.पी. सरकार एक पुल बांधने लग रही है लेकिन हमारे इलाके में नहीं लग रहा। अगर यू.पी. सरकार ने वहां पर पुल बांध दिया तो मरे उस इलाके में, नुकसान होगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अगर वैसा बांध जैसा कि यू.पी. सरकार वहां पर बांध रही है, हमारी हरियाणा सरकार भी बांध देगी तो हमारी वह इलाका तबाही से बच जायेगा। स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से आपके जरिये यह हनवेदन करता हूं कि मेरे इलाके में यह बांध अवश्य लगायें। मैंने पिछले सेशन में कहा था कि मेरे इलाके में कोई पुल नहीं है इसलिए वहां पर पुल बनाये जायें। जगाधरी से पौंटा साहब की रोड जो हरियाणा को हिमाचल से कोनैक्ट करती है, वह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की कृपा से बनी है जिसके लिये मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं। मेरे इलाके में जो तीन पुल थे, वे बड़े जरूरी थे। उन पर काम बड़े जोर शोर से होने लग रहा है और मैं यह समझता हूं कि वे बहुत

जल्दी ही तैयार हो जायेंगे। इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह नारायणगढ के इलाके में पानी की कमी है उसी तरह मेरे इलाके में भी कमी है। वहां पीने का पानी नहीं है। सरकार ने जो वाटर सप्लाई की स्कीम शुरू की हुई है उसके तहत मेरे इलाके में पीने का पानी पहुंचाया जायें। आजकल सरकार ट्यूबवैल भी लगा रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरी कांस्टीच्युएँसी में ट्यूबवैल लगाकर लोगों को पानी देकर उनकी तकलीफ को दूर करें।

स्पीकर साहब, मेरे इलाके में नहर जमनगर्बी से पानी आता है लेकिन हमारे यहां लैवी भाखड़ा नहर की वसूल की जाती है जो कि नाजायज है। मेहरबानी करके उसको हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि भाखड़ा नहर सरकार ने अपने पैसे से तैयार की थी और इस नहर के निकालते वक्त किसानों ने जमीन का कोई पैसा नहीं लिया था इसलिए इस लैवी को सरकार हटाने की कृपा करें।

मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां की जमीन को महकमा जंगलात वाले एक्वायार कर लेते हैं। ऐसी जमीनों को भी वे एक्वायार करते हैं जिन पर लोग बहुत समय से बैठे हुये हैं। इसलिये मैं सरकार से

प्रार्थना करूंगा कि जो आबपाशी के लायक जमीन है उसे एक्वायर न करें।

मेरे इलाके में ताजेवाला हैड से एक माइनर वनार निकलता है जिससे कि कई देहातों को पानी लगता है वह माइनर बरसात के मौसम में फ्लड की वजह से टूट जाता है जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है। पनीरी लगाने के टाइम पर भी किसानों का काफी नुकसान होता है और गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है क्योंकि वह फिर तैयार करनी पड़ती है। अगर इस माइनर को 1 आर 0 से 2 आर में तबदील कर दिया जाये तो कई देहातों को सहूलियत मिल जायेगी।

नहर जमनगर्बी से हमारे गांव को पानी पूरा नहीं मिलता लेकिन लगान सरकार पूरा लेती है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारी पानी की डिमांड को भी पूरा किया जाये।

छछरौली में जो सड़क हिमाचल और हरियाणा को मिलाती है उस पर तीन पुल अब बनने लगे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मरी रिक्वेस्ट मान ली थी मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करता हूं। बिलासपुर घनौरा रोड पर सरस्वती नदी के उपर एक छोटा सा पुल है अगर उस पुल को जल्दी मुकम्मल कर दिया जाये तो यह रास्ता हिमाचल के लिए खुल जायेगा।

टीचर्ज की स्ट्राइक का जहां तक संबंध है उन्होंने बिलकुल गलत काम कियसा है। जमींदारों ने और मजदूरों ने

अपनी मेहनत का पैसा बच्चों की शिक्षा पर लगाया है जिससे कि उनके बच्चे पढ़ सकें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ऐक्शन लिया है वह ठीक है।

यहां पर रेस्ट हाउसिज का भी जिक्र आया। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे अफसर इतनी मेहनत से काम करते हैं तो अगर रात को जाकर वे वहां ठहर जाते हैं तो इसमें हर्ज क्या है ? स्पीकर साहब, मेरे इलाके में कुछ हिस्सा बैकवर्ड घोषित है और कुछ हिस्सा बैकवर्ड घोषित नहीं हैं मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उसको भी बैकवर्ड करार दिया जाये और जो सुविधायें बैकवर्ड इलाके को मिलती हैं वे उसको भी दी जायें। इसके अलावा यहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं बैकवर्ड इलाका होने के नाते उनको नौकरी के मामले में विशेष सुविधा दी जायें तो मेहरबानी होगी।

स्पीकर साहब, मेरे इलाके में लकड़ी के साधन बहुत हैं और वहां से लकड़ी बाहर जाती है अगर वहां पर कोई इंडस्ट्री लग जाये तो जो उस इलाके के बेराजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है।

स्पीकर साहब, आपने मुझे टाईम दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

**चौधरी हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़):** स्पीकर साहब, मैंने एक तरमीम राज्यपाल महोदय के ऐड्रेस के सिलसिले में दी थी

और वह यह भी थी कि टीचर्स की स्ट्राइक को गवर्नमेंट ने जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है और शिक्षा की जो पालिसी है वह गलत है और आपने उसको रद्द कर दिया। लेकिन आज जो मुझे समय मिलेगा उसका बेशतर हिस्सा इन टीचर्स की स्ट्राइक और शिक्षा पालिसी जो सरकार की है उसी पर अर्ज करूंगा। एक बात मैंने और सोची थी कि मेरे मुतालिक जो बातें कही गईं हं, उनके बारे में मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन हाउस के सामने रखूंगा। मैंने यही सोचा था कि मैं आपकी खुशामद करूंगा और आप मुझे इस सिलसिले में पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का टाईम दे देंगे।

तहरीके मोहरिक और कुछ दूसरे मैबरान ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाये। अगर ये इल्जाम महज जाती होते तो इनको नजरअन्दाज करता लेकिन इनका एक ऐसा पहलू है जिसको नजरअन्दाज करके मैं यह समझता हूँ कि अपने फर्ज की अदायगी में कोताही करूंगा। तहरीके मोहरिक और कांग्रेस के जो प्रधान हैं और इस ऐवान के बड़े मोअजिज सदस्य है ..... (व्यवधान) .....  
.....

**श्री अध्यक्ष:** आप बोलते जाइए। मैं कोशिश करूंगा कि कोई बीच में न बोले।

**चौधरी हरद्वारी लाल:** आपकी कोशिश तो जरूर कामयाब हो सकती है। मसलन इन्होंने और कुछ मैबरान ने कहा

कि मैंने पोलिटिक्स आफ डिफैक्शन को जन्म दिया। 1967 में .....  
....

**श्री अध्यक्ष:** चौधरी साहब आपको 15 मिनट समय दिया जाता है आप इसमें ही खत्म करें।

**चौधरी हरद्वारी लाल:** फिर तो मैं बतौर नाराजगी के वाक आऊट करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह बड़ी बेइन्साफी है। एक शख्स पर चार घंटे तक इल्जामात मैंबर साहिबान लगाते रहे हों और उसका जवाब देने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिये जायें यह मेरे साथ बड़ी बेइन्साफी है।

**श्री अध्यक्ष:** यह बेइन्साफी आपके साथ किसने की है इसको आप स्पष्ट कर दें।

**चौधरी हरद्वारी लाल:** वह भी बताऊंगा आप मुझे टाईम दें ...

**श्री अध्यक्ष:** इसके लिए किसने बेइन्साफी की .....

**चौधरी हरद्वारी लाल:** आप मुझे बोलने दें तब .....

**श्री अध्यक्ष:** मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि बेइन्साफी किसने की ?

**चौधरी हरद्वारी लाल:** मेरे साथ यह बेइन्साफी की कि मैंबर आफटर मैंबर .....



श्री अध्यक्ष: कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है।  
(व्यवधान)

**Ch. Hardwari Lal: \*\*\*\*\***

श्री अध्यक्ष: चौधरी हरद्वारी लाल ने जो कुछ कहा है यह ऐक्सपोज कर दिया जाये कोई रिकार्ड न करें।

चौधरी हरद्वारी लाल: मैं इस बेइन्साफी के खिलाफ वाक आऊट करता हूँ।

(इस समय चौधरी हरद्वारी लाल सदन से बाहर चले गये)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब .....

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमिशन थी  
....

श्री अध्यक्ष: मैंने श्री गुलाब सिंह को बोलने के लिए कह दिया है इसलिये आप बैठ जाइए।

श्री गुलाब सिंह जैन: स्पीकर साहब, हाउस के सामने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में जो चौधरी सरूप सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा

हुआ हूँ। इस अभिभाषण में सरकार की पालिसी के बारे में गवर्नर महोदय ने स्पष्ट बातें कही हैं। यह सदन को मालूम ही है और जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि गवर्नर कांस्टीच्यूशनल हैड है और वह सरकार की पालिसी के बारे में ही सब कुछ बातें अपने भाषण में कहते हैं।

**श्री अध्यक्ष:** बाबू जी, आपको पन्द्रह मिनट दिये जाते हैं आप पन्द्रह मिनट में खत्म कर दें।

**श्री गुलाब सिंह जैन:** अच्छा जी। बोलने के लिये तो बहुत कुछ था लेकिन अब तो सारा सिलसिला ही खत्म हो गया।

स्पीकर साहब, कांस्टीच्यूशनल हैड के तौर पर जो उनकी तरफ से बनता था उसके बारे में उन्होंने कहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है इसलिये कांग्रेस पार्टी की सरकार की पालिसी के बारे में उन्होंने पढ़ा। स्पीकर साहब, हमारी कांग्रेस पार्टी की पालिसी है कि देश के अन्दर हमने एक क्लास लेस सोशलिस्टिक सट्रक्चर पैदा करना है और उसके अनुसार ही हमने यह सारा काम करना है।

**गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल):** स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि चौधरी दल सिंह जी बाहर जा रहे हैं, यह सदन की सिम्पथी में जा रहे हैं या कि अपने तौर पर जा रहे हैं।  
..... (हंसी) .....

**श्री गुलाब सिंह जैन:** अभिभाषण के पहले जेज पर ही गवर्नर साहब ने साफ शब्दों में कहा है और जिसका सब सदस्यों को अच्छी तरह से ज्ञान है। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बचनबद्ध है। इसका अर्थ न केवल गरीबी को दूर करना है – जिसे देश की परिस्थितियों के सन्दर्भ में अनिवार्यतः परम अग्रता दी जानी चाहिए, अपितु उन बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना भी है जिनके अभाव में जीवन का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि पेय जल, खुराक, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं और शिक्षा की व्यवस्था करना, तथा सामाजिक विषमताओं को दूर करना, कुछ ऐसी बातें हैं, जिनकी और सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है और इसके आगे गवर्नर साहब कहते हैं कि इसका उद्देश्य लोगों के सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उसके परिणमस्वरूप प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की दृष्टि से आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना, आय तथा पूंजी की विषमताओं को कम करना और संतुलित प्रादेशिक विकास करना भी है। स्पीकर साहब, अब हमने देखना है कि आगे चल करके जो जो बातें उन्होंने कहीं कि क्या-क्या कदम इस हरियाणा सरकार ने उन बातों को पूरा करने के लिए उठाये हैं और क्या क्या कदम और उठाने जा रही है। इन बातों की ओर आया गवर्नर साहब ने हमारा पूरा ध्यान दिलाया है कि नहीं। स्पीकर साहब, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां के लोगों के, यहां की जनता के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए सब से बड़ी बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में, जनता

को, जमींदारों को पानी मुहैया करें। स्पीकर साहब, पानी भी हमें दो तरीकों से देना है, एक तो दरियाओं के जरिये, दूसरा जमीन के नीचे से पानी को उपर लाकर। इसी तरह से हमें बिजली की जरूरत है। स्पीकर साहब, किसी देश या प्रदेश की तरक्की के लिए, बिजली एक बहुत बड़ा अहम स्थान रखती है और आबपाशी हमारे देश के लिए अहम है। इसलिये अगर इस अभिभाषण को पढ़ा जाये तो इससे सब कुछ पता चलता है कि हमने इसकी तरक्की के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किये और अब तक इसको देने के लिए क्या क्या कदम उठाये तथा आगे सरकार क्या क्या कदम उठाने जा रही है। एग्रीकल्चर के बारे में गवर्नर साहब के अभिभाषण में यह बात साफ तौर पर कही गई है। बिजली के बारे में गवर्नर ऐंड्रैस में बड़ी तफसलील के साथ दिया गया है। फरीदाबाद में 60 मैगावाट क्षमता वाले दो यूनिट स्थापित किया जा रहे हैं। प्रथम यूनिट संभवतः अप्रैल 1974 तक तथा दूसरा मार्च, 1975 तक चालू हो जायेगा। पानीपत में थर्मल प्लांट स्थापित करने संबंधी कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इस तरह से वहां से 220 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ताजेवाला हैडवर्क्स के निकट 12 मील लम्बा एक नया जल-मार्ग बनाने का प्रस्ताव है। इस जल-मार्ग पर तीन बिजली घर होंगे जिनसे हमें 45 मैगावाट बिजली मिलेगी। राणा प्रताप सागर से भी हमें अपना शेयर मिलेगा। ब्यास-सतलुज लिंक के पूरा होने और भाखड़ा बिजली के सुनिश्चित हो जाने पर राज्य में बिजली की स्थिति में सुधार होने की आशा है। इससे हम देख सकते हैं कि प्रदेश में तरक्की हुई है

या नहीं। स्पीकर साहब जैसे मैंने अपने पहले शब्दों में भी कहा है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए अगर एग्रीकल्चर की यहां पर तरक्की हो रही है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वाकई सही मायनों में हरियाणा में तरक्की के कार्य हुये हैं। इसके बारे में मैं 'लिंग' से एक लेख को आपके द्वारा पढ़ करके सुनाता हूं, उसमें मुझे हरियाणा के बारे में कुछ शब्द मिले हैं, लिखते हैं:-

“Haryana's performance in the production of food grains over the last five year has indeed been spectacular. In wheat production alone Haryana has registered an increase by 150 per cent during this period. Wheat production, for instance in 1967 was 10.59 lakh tonnes and this year it is expected to be 21 lakh tonnes. Similarly, in 1967 the total production of wheat, gram, barley and othe rabi pulses, was 18.45 lakh tonnes and in the target fixed for 1972-73 it was 35-70 lakh tonnes.”

Then it writes:-

“In other words, in a short period of 5 years, Haryana would be in a position to contribute to the Central pool more wheat than its total production in 1967. Because of this increase in food grains production, Haryana's growth rate is the highest in the country.”

Further it writes:-

“As a result of this, increased production per capita income of Haryana in this period too has registered a marked increase. In 1965-66, per capita income was Rs. 446 and in

1969-70, it increased to Rs. 788. Haryana now has the highest per capita income in the country after Punjab.”

स्पीकर साहब, मेरा इन बातों को कहने का मतलब यह है कि गवर्नर साहब के अभिभाषण के अन्दर जिस चीज पर जोर दिया गया है, वह एक ही बात है कि हमने किस तरीके से हरियाणा प्रदेश में तरक्की के कार्य किये। स्पीकर साहब, टीचर्ज की हड़ताल के बारे में हमारे अपोजीशन के भाईयों ने यहां बड़े जोर शोर से कहा। मैं तो चौधरी हरद्वारी लाल जी का भाषण सुनना चाहता था क्योंकि उन्होंने अखबारों में सरकार के खिलाफ और टीचर्ज के हक में बड़े लम्बे चौड़े ब्यान दिये थे, पर वे चले गये, सुनने का मौका ही नहीं मिला। स्पीकर साहब, मैं तो टीचर्ज से निवेदन करूंगा कि इन दोस्तों से वे बच कर रहें। एक कहावत है कि चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा, ये लोग तो गरीब टीचर्ज को आलाकार बनाये हुये हैं और कुछ अखबारों ने इस बात को कुछ गलत हवा देकर के छापा हैं। इसका नतीजा क्या है ? गरीब टीचर्ज तो एक ऐसी जगह पर जा खड़े हुये है कि आगे जायें तो मरते है, पीछे को तो कोई देखता नहीं है। इसलिये मैं अपोजीशन के भाईयों से अर्ज करूंगा कि वे टीचर्ज की जिन्दगी के साथ न खेलें, उन्हें सरकारी मुलाजिम के तौर पर ही रहने दें। मैंने टीचर्ज की डिमांड को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझने की कोशिश की है और उनका जो जवाब है, उसको भी मैंने पढ़ा है, इन दोनों को पढ़ने के बाद और आज जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है, उसको सुनने के बाद मैं इस

नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक भी डिमांड मुझे ऐसी नजर नहीं आती जो कि वाजिब हो या मानने वाली हो। जैसे आज जोशी साहब ने कहा कि सरकार से डिमांड मनवाने का जो तरीका टीचर्स ने अपना रखा है, वह बिल्कुल गलत तरीका है। मैं असूलन तौर पर हर सरकारी मुलाजम की इंडीविजुअल लेबरर कैपटेलिस्ट के मुकाबले में बहुत कमजोर हो रहे थे और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब तक वे यूनियन बनाकर, एक होकर कैपटेलिस्ट के खिलाफ नहीं लड़ते थे तो उतनी देर तक कैपटेलिस्ट उन्हें एक्सप्लायट करते थे। आज उसी प्रिंसिपल को हम सरकारी मुलाजमों पर कैसे लागू कर सकते हैं ? मेरे अपोजीशन के भाई यह कहते हैं कि सरकार टीचर्स को एक्सप्लायट कर रही है। जो सहूलियतें सरकार ने टीचर्स को दी है, वह ठीक दी है। टीचर्स पिल्लर टू पोस्ट गये। टीचर्स को चाहिये था कि वे एम.एल.एज को लेकर के हमारे पास आते, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मिलते। अपना केस लेकर के वे मिलते, पर वे नहीं मिले। दरअसल बात यह है कि जब कभी भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से टीचर्स का कोई डैपुटेशन मिला है, एक दो दफा तो हमारे सामने भी बात हुई है तो वह ऐसे टीचर्स का डैपुटेशन मिला है जिनकी मंशा टीचर्स को फायदा करवाने की नहीं थी बल्कि पोलिटीकली उसको हवा देने की थी। यही बातें हैं जिनकी वजह से आज टीचर्स के ऊपर दिक्कत आई है। इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े हैं। यह सब गलत ढंग से काम करने की वजह से हुआ है अभी जोशी

साहब ने कहा था और मुझे भी अपने हलके का तजरुबा है। चार मार्च को मेरे हलके के वर्कर्स की मीटिंग हुई। लगभग दो सौ वर्कर्स वहां मौजूद थे सब की यह मांग थी कि सरकार को कहा जाये कि इस स्ट्राइक के आगे न झुका जाये। किसी गांव में, कहीं भी, किसी ने टीचर्स की स्ट्राइक के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई। डेमोक्रेटिक सैट-अप में हम लोग पब्लिक के नुमायंदे हैं। अगर स्ट्राइक से किसी को सहानुभूति होती तो लोग हमारे पास आक कहते कि जैन साहब टीचर्स की स्ट्राइक के बारे में आप सरकार को कहें। मैं जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि हिसार इतना बड़ा शहर है और वहां कई गवर्नमेंट स्कूल हैं। किन्तु वहां पर मुझे एक भी शख्स ने आकर नहीं कहा कि उसे टीचर्स के साथ सहानुभूति है। बल्कि लोगों को इस बात का रोष हे कि टीचर्स गलत टाईम पर स्ट्राइक करके बच्चों के जीवन के साथ खेलने लगे हैं इसलिए मैं अपोजीशन के भाईयों से कहूंगा कि अगर वे वाक्या ही टीचर्स के वैल-विशर्स हैं तो उनको कहो कि वे स्ट्राइक छोड़ दें। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं .....

**एक आवाज:** टीचर्स को यकीन दिलाइये।

**श्री गुलाब सिंह जैन:** हमोर चीफ मिनिस्टर साहब निहायत ही माकूल बात को करने वाले हैं। अगर वाकई उनकी किसी डिमांड में वजन होगा तो कोई वजह नहीं है कि जब पीसफुल एटमॉसफीयर हो जाये, वे गौर न करें। आज टीचर्स अपोजीशन के भाईयों के हाथों में खेल रहे हैं। जो अखबार



नवीस हैं उनका भी इसमें हाथ है। अभी एक अखबार में मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि पिछले 108 साल में हरियाणा में कभी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी। इस तरह की जो चीजें हैं ये टीचर्स को मौत के मुंह में धकेले जा रही है। जो टीचर गांव में बैठा है उसको क्या पता कि रोहतक में क्या हो रहा है और गुड़गांव में क्या हो रहा है। ऐसे अखबार को पढ़कर ही वह समझता है कि सारे देश में आग लगी हुई है। वह इस बहकावे में आकर मर जाता है। कितने ही टीचरों के वालिद हमारे पास आये कि हमारे बच्चों से गलती हो गई हैं, उनको बहकाया गया है, उनको माफ कर दिया जाये। कितने ही टीचरों ने हमारे से कहा है कि आप अफसरों को कह कर हमें माफ करवा दीजियेगा। इस बहकावे में आ गये थे और अखबारों की गलत रिपोर्टिंग के कारण हम इस तरफ आ गये थे। इन लोगों को अफसरान ने माफ भी किया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि टीचर्स हमारी सोसाइटी की एक अहम जमात है। जो इन्होंने कदम उठाया है इस कदम को वापिस करने में अपोजीशन के भाइयों को हमारे साथ देना चाहिये। उनको प्रैसटीज पर नहीं अड़े रहना चाहिये। जो हड़ताल है वह अन-कंडीशनली वापस लेनी चाहिये ताकि सरकार उनकी जायज मांगों की तरफ गौर करें। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि दो रिट्स टीचर्स ने हाई कोर्ट में की। एक ट्रांसफर के बारे में थी और दूसरी मंहगाई भते के बारे में। दोनों रिटों का फैसला हाई कोर्ट ने टीचर्स के खिलाफ दिया है। उनकी डिमांड के अन्दर अजीब चीज है कि उनको सर्विस राइट्स और यूनियन बनाने के

राइट दिये जायें। यूनियन बनाने का राट जो है वह लेबर के लिए है। इनके लिये इस किस्म की इजाजत गलत है। इसी तरह से सर्विस राइट्स का सवाल है। ये तो चाहते हैं कि इनको इलैक्शन और पोलिटिक्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाये। यह कैसे हो सकता है, यह गलत कदम होगा। कोठारी कमिशन को मैं नहीं मानता कि जिन जिन बातों का कोठारी कमिशन की रिपोर्ट में जिक्र है वे सारी सही हैं और वे सारी मानी जायें किसी रिपोर्ट के बाद सरकार ने भी तो देखना होता है कि कौन सा सुझाव इसमें मानने वाला है और कौन सा नहीं मानने वाला। कोठारी साहब ने पता नहीं कैसे सर्विस राइट वाली बात कही है। तो इन सब बातों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि टीचर्स स्ट्राइक जो है वह बिल्कुल गलत है और इसके साथ पब्लिक का कोई साथ नहीं है।

**श्री अध्यक्ष:** आपका समय समाप्त हो गया है।

**श्री गुलाब सिंह जैन:** आज हरियाणा की जनता मुकम्मल तौर पर हमोर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान 'लिक' की तरफ दिलाना चाहता हूँ:-

“The response to this Congress campaign in Haryana was undoubtedly tremendous. Even the most cynical critics of the present regime have been forced to admit that the Congress Ministry in Haryana under the stewardship of Chief Minister Bansi Lal has created its own impact on the people.”

कहने का अभिप्राय यह है कि लोगों पर इस बात का असर है कि चौधरी बंसी लाल की सरकार हरियाणा को किस तरीके से तरक्की की तरफ ले जा रही है और लोगों का कितना भला कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का जो चौधरी सरूप सिंह ने पेश किया, अनुमोदन करता हूँ।

**चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज (रोड़ी):** आदरणीय स्पीकर साहब, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में चौधरी सरूप सिंह जी ने जो शुक्रिया का प्रस्ताव पेश किया है मैं भी उसकी तार्ईद के लिए चन्द अलफाज कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राज्यपाल का अभिभाषण उस तरक्की की एक सही तस्वीर है जो हरियाणा ने पिछले चन्द सालों में की है और आइंदा सालों में दिन दुगनी और रात चौगुनी रफ्तार से करने जा रहा है इस में कोई दो राय नहीं कि पिछले चार पांच सालों में हरियाणा ने लामिसाल तरक्की की है। बहुत सारी बातों को दोहराना ही पड़ता है क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि उसी चीज को बताना पड़ता है। जहां तक पैदावार का सवाल है, जब से देश आजाद हुआ है उस वक्त से आज तक दस गुना पैदावार हरियाणा में बढ़ चुकी है। किसी वक्त हरियाणा कमी का प्रदेश था और यहां पर सिर्फ रेह और रेतीले मैदान थे। और पैदावार कम होती थी। पहले हम अनाज की कमी को दूर करने के लिए दूसरे सूबों से अनाज हासिल करते थे लेकिन अब हालत यह है कि हम दूसरे सूबों को

देते हैं और हर साल लाखों टन अनाज गवर्नमेंट आफ इंडिया का भण्डार भरने के लिए दे रहे हैं। इसी तरह बाकी बातों में और जो दूसरी इन्सानी जरूरियाते जिन्दगी हैं उनके बारे में भी हरियाणा ने लामिसाल तरक्की की है और रोटी, कपड़ा, तालीम, बिजली, ट्रांसपोर्ट, मकान तथा इलाज वगैरा में भी बहुत आगे बढ़ा है। जहां तक रोटी का सवाल है वह मैं अर्ज कर चुका हूं कि अनाज की पैदावार बहुत बढ़ी है। पीने के पानी के बारे में पोजीशन यह है कि पहले लोग छप्पड़ों का गंदा पानी जिसमें पशु भी पानी पीते थे उसके ऊपर कोई पड़ी होती थी और कई दफा वहां पशु पेशाब भी कर देते थे, वही पानी लोग पानी न मिलने की वजह से पीते थे लेकिन अब वहां पर वाटर वर्क्स लग गये हैं नलों के जरिये शुद्ध और स्वच्छ पानी लोगों को पीने के लिए मिलता है। जहां तक इलाज का सवाल है हस्पताल भी बहुत बढ़ गये हैं। जहां तक तालीम का सवाल है बेशुमार स्कूल खुले हैं और तालीम में बढ़ौतरी हुई है। राज्यपाल महोदय ने जो कुछ अपने अभिभाषण में बताया है उसमें कोई मुबालगा नहीं है और हमारी सरकार नके जो काम किया है उसकी एक सही तसवीर पेश की है। हमारे रोशन दिमाग रहनुमा चौधरी बंसी लाल की रहनुमाई में जो तरक्की के काम हरियाणा में हुये हैं उसका सही नक्शा उन्होंने अपने अभिभाषण में पेश किया है। इसके लिये हम उनके आभारी हैं। यह जो हमारे विरोधी दल के भाई है मैं चार पांच साल से देख रहा हूं उनका आम तौर पर यही रवैया है कि मुखालिफत बराये मुखालिफत करनी है लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि धूल उड़ाने से

चांद छिप नहीं सकता और वह आर्जी बात होती हैं। जब धूल बैठ जाती है तो चांद बाहर आ जाता है और उसी तरह चमकने लगता हैं। इसीलिये तो यह कहा जाता है:—

सदाकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से,

खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से।

यह तो सच्चाई है कि हरियाणा में तरक्की हुई है, यह एक सदाकत है और इससे को इन्कार नहीं कर सकता। दो—तीन बातों में मैं खास तौर पर अर्ज करूंगा। आबपाश के लिये जो भी पिछले सालों में काम हुआ है वह काबिले तारीफ हैं। यह हरियाणा की बदकिस्मती है कि यहां कोई दरिया नहीं है और जो भाखड़ा से पानी आया है वह बहुत दूर दराज जगह से और गवर्नमेंट आफ इंडिया के इन्तजाम से पहुंच रहा है। हमारे रेतीले मैदान हैं और वहां अगर नीचे खोदें तो पानी कड़वा मिलता है लेकिन बावजूद इतनी मुश्किल के हमारी सरकार ने पिछले चार पांच सालों में अपना पूरा ध्यान इस तरफ लगाकर हजार ट्यूबवैल्ज लगाये हैं। इस सरकार के आने से पहले जहां पहले हरियाणा में 12/14 हजार ट्यूबवैल्ज होते थे वहां अब इनकी तादाद एक लाख 15 हजार के करीब पहुंच गई है। यही वजह है अनाज की पैदावार ज्यादा हुई है। पहले हरियाणा में हमारे कुछ इलाके बाढ़ में डूब जाते थे और कुछ इलाके खुश्कसाली की वजह से तबाह हो जाते थे। अब इसी बाढ़ के पानी को काबू करके बाबपाशी के लिए

इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यह भी बड़ी भार अचीवमेंट है। इससे दो फायदे हो गये हैं। एक तो लोग बाढ़ की मार से बच गये और दूसरे जो सूखे इलाके थे उनको यह पानी मिलने से वहां पैदावार हो गई। सड़कें भी प्रोग्राम के मुताबिक अब तक गांव-गांव में पहुंच जानी चाहियें थीं और अब भी काफी ज्यादा बन चुकी हैं। तकरीबन 60/70 फीसदी गांव में तो सड़कें पहुंच गई हैं और जो बाकी है उनमें भी इस साल नहीं तो साल दो साल में कम्पलीट हो जायेगी क्योंकि जैसा कि बताया गया है इस काम को कुछ स्लो डाउन किया गया है। यह भी बड़ी कामयाबी की बात है कि इतनी सड़कें बन चुकी है। सबसे बड़ा काम जो हरियाणा ने सारे देश में किया है वह ये है कि ट्रांसपोर्ट को नैशनेलाइज किया गया है और हमारी रोड्स और ट्रांसपोर्ट की बसें इतनी अच्छी हैं और इतने बढ़िया तरीके से चल रहीं हैं कि काबले तारीफ हैं। यह बात नहीं है कि इस बात की हम खुद ही तारीफ कर रहे हैं बल्कि सारे देश में इसकी चर्चा है। जादू वह जो सिर चढ़ बोले, मुश्क आं अस्त के खुद बगोयद। कस्तूरी वह है जिससे अपने आप खुशबू आये न कि पंसारी कहे कि मेरी कस्तूरी अच्छी हैं। पंजाब से जब हम हरियाणामें पहुंचते हैं तो सड़क पर लारी की चलने की रफ्तार से ही पता लग जाता है कि अब लारी हरियाणा की हद में आ गई है क्योंकि स्पीड तेज हो जाती है और कोई हिचकोले नहीं लगते। आप किसी और स्टेट से रात को सफर करते आये तो जैसे ही हरियाणा में दाखिल होंगे आपको खुद-ब-खुद पता लग जायेगा कि हरियाणा में आ गये हैं क्योंकि

आपको चारों तरफ ट्यूबवैलज की बिजली जगमगाती नजर आयेगी। यह कोई मुबालगा की बात नहीं है यह तो स्पष्ट बात है और हाथ कंगन को आरसीकी जरूरत नहीं। जो कुछ भी इस अभिभाषण में बताया गया है वह एक सही तस्वीर हरियाणा की है लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे काम हैं जिन में कुछ कमी है। मैं आने हल्के के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का बैकवर्ड है और वहां पर 80 फीसदी गांवों में पीने का पानी नहीं है नीचे से जो पानी निकलता है वह इतना खारा होता है कि उससे कुल्ली भी नहीं कर सकते हैं और पीना तो दूर की बात है। फिर वहां से दरिया घघर गुजरता है जिसकी बाढ़ से हर साल कई गांवों में बनी बनाई फसलें तबाह हो जाती है और लाखों रूपये का नुकसान होता है। मैं गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यादन दें। ओटू हैड से 12/14 मील ऊपर एक बांध बनाया जाये। इससे दो काम है एक तो रिजवयिर बन कर पानी जमा होकर आबपाशी के लिए इस्तेमाल होगा और दूसरे हर साल 14/15 गांवों में बाढ़ से फसलें तबाह होती है वे बच जायेंगी। ..... (विघ्न) ..... यहां पर संत जी के बापरे में भी काफी जिक्र आया है। तो यह तो ले डूबेंगे। पंजाब में ले डूबे और यहां ले डूबेंगे। फिर आप जानते है कलियुग का जमाना है और कलियुग में ऐसे ही संत है। उनसे हम क्या सीख सकते है ? उनके मन में यही था कि उनके पास कार और कोठी होनी चाहिये क्योंकि पिछले दिनों से कार ओर कोठी की आदत उनको पड़ गई थी।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े होशियार हैं उनको उनका यह राज मालूम हो गया और ठीक उसी जगह उनको पहुंचा दिया। तो मैं संत जी से कहूंगा कि संत जी आपने अपना राज अपने पास ही रखना था क्योंकि कहते हैं:—

बशर राजे दिल कह कर जलीलों खवार होता है,

निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है,

मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मरतबा चाहे,

कि दाना खाक में मिलकर गुलोगुलजार होता है।

जब ऐसे काम से कुछ नहीं बना तो कभी उधर गये और कभी इधर गये। एक ही जुबान से कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक मास्टरो का ताललुक है, इन पर तफसरा करते हुये मैं दो लफजों में खत्म करूंगा। मास्टरो ने तहरीक दो के तहत जो स्ट्राइक की है, ऐसा मालूम होता है कि ये लोग चन्द आदमियों के बहकावे में आ गये हैं। दो भाईयों की तकरीर में यह बात आई कि अन्दाजे में गलती हो गई, हमें यह मालूम नहीं था कि यह मामला इतना जोर पकड़ जायेगा। इस बात से जाहिर होता है कि इस पर कई बातें होती रहीं और अन्दाजे की गलती हो गई और मास्टरो को कह दिया कि 'चढ़ जा बैआ सूली पर भली करेंगे राम'। और जब उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो खुद ऐसे खड़े हो गये जैसे 'भूस में आग लगाये जमालो दूर खड़ी' वाली बात है। वे ऐसी जगह फस गये हैं



जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल है। मैं इन्हें यही मशवरा दूंगा कि इस स्ट्राइक को गैर-मशरूत तौर पर वापिस लें और हम इसकी तवक्को करेंगे। मुलाजिम ओर सरकार का रिश्ता ऐसा होता है जैसे बच्चे और बालदेन का होता है। बच्चा अगर बालदेन की गोद में टट्टी पेशाब कर दें तो बालदेन उस बच्चे का फैंक नहीं देते और न ही कपड़े फैंकते हैं। कपड़े को धो लिया जाता है। मैं तवक्को करूंगा कि गैर मशरूत तौर पर स्ट्राइक छोड़ दें और रास्ते पर आ जायें। बालदेन की जो मेहरबानी होती है उसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब उनसे ठीक ढंग से सलूक करेंगे, यह मैं उनसे आशा करता हूँ।

अब मैं थोड़ा सा जनसंघ वालों का जिक्र कर दू, ये बोलते हैं इनके लिये एक ही लपज काफी है:—

मिट्टादे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे,

कि दाना खाक में मिल कर गुलोगुजार होता है।

एक काले आदमी का नाम काफूर रख दिया और वह आदमी हब्शी था। काफूर बिल्कुल सफेद होता है और वह हब्शी बिल्कुल काला था। इन जनसंघ वालों का यही हाल है। आंखों से अंधे नाम नैनसुख वाली बात हो रही है। मैं इन भाइयों से इल्तजा करूंगा कि सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं उनकी भी शलाघा करनी चाहिये और तामीरी नुक्ताचीनी करके अच्छे कामों को भी सदन में लाना चाहिए। अपोजीशन का काम है डैमोक्रेसी को ठीक

ढंग से चलाना, सिर्फ यही नहीं है कि हर चीज की मुखलिफत करते जायें, इससे कोई फायदा नहीं होता। इन लफजों के साथ में चौधरी सरूप सिंह जी द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव की तारीफ करता हूँ।

**वित मंत्री (श्री राम सरन चन्द मितल):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत इन्तजार कर रहा था कि साबिका लीडर आफ दी अपोजीशन का भाषण सुनू और कुछ जवाब देने का मौका मिले मगर उन्होंने बहुत गैर मामूली तरीके से अपना पीछा छुडवा लिया और यहां से चले गये। मैं तीन बातों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ – एक सरकार की इकोनोमिक पालिसी, दूसरी टीचर्ज स्ट्राईक और तीसरी हाउसिंग। जहां तक पावर्टी का सवाल है, दरसअल यह गरीबी आजकल की नहीं है, सैकड़ों सालों से यह गरीबी चली आ रही है जब यहां पर मुगल रूल था। इसके पेशतर हमारे देश को रिच कंट्री समझा जाता था और योरूप के बड़े बड़े ट्रैवलर्ज यहां आया करते थे। कौमन मैन की हालत कुछ खराब थी। एक फ्रैच ट्रैवलर ने कहा है कि—

Tillers of the soil themselves hungry;

Tolling to feed others;

weavers themselves naked;

toiling to clothe others.

उसके बाद अबसोल्यूट मोनार की फ्यूडल लौर्डज का राज था और उसके बाद ब्रिटिश रूलर आये। ब्रिटिश रूल में भी हिन्दुस्तान की दौलत फारेन कंट्रीज को जाती थी, उसमें इन्होंने ठीक कहा था कि "हमारा देश रोजबरोज गरीब होता जा रहा है"। आप देखे, हमारे यहां कच्ची कपास होती थी। उस कपास को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी रेल में, जहाजों में भरकर मंचेस्टर और लंकाशायर में ले जाती थी और वहां से कपड़ा बनकर यहां आता था, जिसको हम खरीदते थे। हमें सिर्फ कपास की कीमत मिलती थी और मुनाफा अग्रेज लेते थे। इस तरह हमारी गरीबी बढ़ती गई। उसके बाद स्वराज्य आया और हमारी हकूमत आई। स्वराज्य आने पर भारत की इकोनोमी पालिसी का सवाल पैदा हुआ। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के सोशलिस्टिक विचार थे क्योंकि वे पहले से ही सोशलिस्ट थे। उनके सोशलिस्टिक विचार प्रकट होत रहते थे। अब हिन्दुस्तान की कांग्रेस गवर्नमेंट का फैसला है कि हमारे यहां सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी होनी चाहिए जिसका मतलब है समाजवादी ढांचा। लोकसभा ने भी इस समाजवादी ढांचे की तार्ईद की और इसे कंट्री की, देश की पालिसी बनाया। समाजवाद के क्या मायने हैं? कई लोग यूनियन आफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की मिसाल देते हैं। हमारे यहां वह सोशलिस्ट तरीका नहीं है जो रशिया में है। हम तो पार्लियामेंट डैमोक्रेसी में बड़े पीसफुल तरीके से समाजवाद ला रहे हैं। पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के हमारे यहां मायने यह कि जनता की राय से काम करना। हमारे यहां जनता की राय से काम शुरू

हुआ। पावर्टी के मुतालिक मै एक दो लफज कह कर अपने प्वायंट को क्लीयर करना चाहता हूं। जिस वक्त हरियाणा बना था उस वक्त इकोनोमिक सर्वे आफ इंडिया के मुताबिक 1966-67 में पावर्टी लाइन 59.37 थी यानि 60 परसैन्ट आफ दी टोटल पापुलेशन हरियाणा प्रदेश बिलो पावर्टी लाइन था। पावर्टी लाइन के मायने इसमें डिफाईन किये हैं कि अक्टूबर 1972 की प्राइसिज को बेस मानकर जिसका पर मंथ पर-कैपिटा कजम्पशन एक्सपैन्डीचर 40 रूपये से नीचे हो वह पावर्टी लाईन में आता है। उस वक्त 59.37 या 60 परसैन्ट ही समझ लिजिये हमारे प्रदेश में पावर्टी लाईन थी।

According to the national Sample Survey results, 59.37% of the total population in 1966-67 was below poverty line in Haryana.

आप देखे,हरियाणा बनने के बाद, थोड़े से अर्से में 1971-72 में पावर्टी लाईन 60 परसैन्ट से धटकर 42 परसैन्ट पर आ गई है। इसी चीज को दूसरे शब्दों में कहूं कि परकैपिटा इन्कम बढ़ गई है।

The position improved considerably in 1971-72, when this percentage was reduced to 41.82 as a result of extensive and wide spread development activities.

हिन्दुस्तान की पोपुलेशन की परसैन्टज में हमारी पापुलेशन परसैन्टेज 1.8 है और प्रोडक्शन आफ फूड 4.1 परसैन्ट हैं। प्रोडक्शन के लिहाज से, इन्कम के लिहाज से आप किसी भी

दृष्टि से देख लीजिए, हरियाणा आगे बढ़ा है। ये फिगर है जो अन-डिसप्युटिड फिगर्ज है और ये फिगर्ज क्लीयर करती है कि हरियाणा में कितनी तरक्की हुई है। इस बात में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता कि यह तरक्की कैसे हुई, यह आप सब जानते हैं कि कैसे हुई ? एग्रीकल्चर, इरीगेशन, अफोरैस्टेशन, एनिमल हसबैन्डरी, रोडज, डेयरी डिवैल्पमेंट और ट्रासपोर्ट वगैरा किसी भी काम को ले लीजिये, हमारी इन्कम और तरक्की क्लीयर है, इस में दो राय नहीं हो सकती।

यह तो करंट फोर्थ फाईव इयर प्लान है इसमें चार साल के अन्दर हमारा 248 करोड़ रुपया खर्च हुआ और इसमें से 170 करोड़ से ज्यादा हमने इरीगेशन, स्वायल कंजरवेशन, अफोरैस्टेशन, विलेज रोडज,रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन,ड्रिकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्ज और एनीमल हसबैन्डरी पर खर्च किया । आधे से ज्यादा खर्चा हमारे विलेज लाईफ पर होता है। इसी से इन्कम बढ़ती है। इसी से गरीबी दूर होती हैं और आज हमारा लक्ष्य है रीमूवल आफ पावर्टी ऐंड सैल्फ रिलायंस। हम चाहते हैं कि आत्म निर्भरता इसमें आये ।

आत्म निर्भरता with economic development and extensive sharing of benefits of economic development, से आती है ।

हमारी आबादी 80 परसेंट के लगभग देहात में रहती है। देहात का खर्चा मैंने अभी आपके सामने सदन में रखा है। मतलब यह कि अब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे यहां अब यह जरूरत नहीं कि हम दूसरे के ऊपर डिपैन्ड करे। हमारी इकोनॉमिक पालिसी काफी साउंड है। स्पीकर साहब, आज यह समझा जाता है कि लैंड रिफॉर्म तो हो गया लेकिन अर्बन इनकम के ऊपर कोई सीलिंग नहीं लगी लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको इन्कम होती है रूपये की, चाहे वे सैलरीज वाले हैं, चाहे बिजनेस के प्रॉफिट्स हासिल करने वाले हैं उनके ऊपर इन्कम टैक्स हैवी है। उनके ऊपर वह काफी अच्छा चैक है। यह ठीक है कि इन्कम टैक्स सैंटर का जाता है लेकिन उसका माक्ल हिस्सा स्टेट्स को मिलता है, हमारे हरियाणा को भी मिलता है। फाइनेंस कमीशन उसका रेट मुक़र्रर करता है कि किस स्टेट को कितना मिलना चाहिए। तो निवेदन यह है कि हर तरफ से हमारा जो समाजवाद का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिये कोशिश हो रही है। यह बात ठीक है कि एक, दो या तीन चार साल के अन्दर सैकड़ों वर्ष की कमी पूरी नहीं हो सकती। हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे यहां राम राज्य है लेकिन अब हम उस रास्ते पर चले हुये हैं। कुछ काम उन्नति के हो गये हैं, कुछ आंयदा होंगे और हमें कामयाबी होगी इसमें कोई शक नहीं है।

स्पीकर साहब, आज प्राइसिज पर बड़ा जोर दिया जाता है और कहा जाता है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई में दो

बाते हैं, अध्यक्ष महोदय। जब मौनसून फेल होता है, सूखा होता है, पैदा कम होता है और कीमत बढ़ जाती है। उस पर कहा जाता है कि क्योंकि कीमत बढ़ गयी है, इसलिये तनखवाह बढ़नी चाहिए, मजदूरी बढ़नी चाहिए। यह एक चैन बन जाता है। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। वह कदम यह है कि होलसेल ट्रेड गेहूं का और चावल का गवर्नमेंट ने अपन हाथ में लेन का फैसला कर लिया है। यह फैसला इस साल से हमारे यहां लागू हो जात है। आयंदा इससे प्राइसिज पर बड़ा इससे प्राइसिज का बड़ा चैक होगा। यदि जरूरी चीजें जो हैं, जो कौमन मैन को काफी आराम पहुंचता है। लगजरी की जो चीज है उनकी कीमत यदि बढ़ती भी रहे तो उससे आम लोगो पर असर नहीं होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारी पापुलेशन बहुत ज्यादा है अभी भी बढ़ती जा रही है तथा इसके अलावा और भी कम्पलकेडिड फ़ैक्टर्ज है। इसलिए प्राइसिज को चैक करना, पापुलेशन का ज्यादा न बढ़ना और जितनी भी दूसरी इकनोमिक फ़ैक्टर्ज की बाते हैं, इन पर काबू पाना काई एक दो दिन का काम नहीं होता लेकिन फिर भी काफी कंट्रोल कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि कोई चिंता की बात किसी तरह से भी नहीं है।

स्पीकर साहब, हाउसिंग ऐक्टिविटीज के बारे में जोशी साहब ने सदन के सामने जो कहा वह यह था कि मजदूरो के लिए हाउसिंग बोर्ड जो मकान बना रहा है उनसे उनको फायदा नहीं पहुंचेगा। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हाउसिंग

बोर्ड का ऐक्ट शायद 1971 में पास किया गया था। 1972 में हाउसिंग बोर्ड बना और वह भी अक्टूबर के महीने में या उसके आस पास । इतने छोटे टाइम के अन्दर उन्होंने फरीदाबाद में लगभग एक हजार मकान बनाये । अब उन्होंने यह फैसला भी कर लिया कि यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, और बहादुरगढ़ में भी मकानात बनायेगे और उधर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज पर भी बनायेगे । उनका प्रोग्राम है कि 1973 के अन्दर 10 करोड़ रूपये खर्च किये जाये और पांच हजार मकान बनाये जाये । अब मकानात किनके लिए बनाये जाते हैं मैं थोड़ा सा इस बात को क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि इस बारे में कुछ गलतफहमी हो रही है । जहां तक लेबर हाउसिज और लेबर कालोनिज का ताल्लुक है उन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाती है । उन्हें तो ऐम्पलायर्ज जो है, कारखानो के मालिकान जो है वे बनाते है । हां गवर्नमेंट 50 फीसदी कर्जा देती है, 25 फीसदी सबसिडी देती है और 25 फीसदी ऐम्पलायर्ज लगाते है । इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के जरिये जो मकान बनाये जाते है, वे मौजुदा नीति के मुताबिक वीकर सैक्शनज के लिये, लो इन्कम ग्रुप और मिडल इन्कम ग्रुप के लिए बनाये जाते है, लेकिन वीकर सैक्शनज के मकान सबसे अच्छे मकान है । अध्यक्ष महोदय, कभी आप भी तशरीफ ले जाइए और फरीदाबाद के मकानात देखिए । मैंने गुजरात, अमदाबाद, बम्बई, तमिलनाडु ओर केरल के मकानात देखे लेकिन उन सब मकानात से सस्ते मुझे फरीदाबाद के मकानात नजर आये । वे मकानात दोनो तरीको से आउट ऐंड आउट सेल और हायर परचेज सिस्टम से दिये जायेगे । इन्हे वे लोग जिन्हे



जिनकी आमदनी शायद 350 या 360 से कम है, ले सकते हैं बशर्ते व उस इलाके में रहते हो, उस एरिया में रहते हो और उनके पास कोई मकान हरियाणा में दिल्ली या चण्डीगढ़ में न हो। इसी तरह से लो इन्कम वाले और मिडल क्लास आमदनी वाले अपनी अपनी आमदनी के हिसाब से मकान ले सकते हैं। अब इससे आगे और क्या किया जाये ? रूरल एरियाज में भी लैंडलैंस लेबरज को हाउस प्लान्टस दे दिये गये हैं। जो सरकार कर सकती थी वह उसने किया है। जोशी साहब ने कोई आल्टरनेटिव तो रखा नहीं यही कहां है कि फायदा नहीं पहुंचेगा। मुफ्त में तो मकान दिये नहीं जाते, मकान तो पैसे देकर ही मिलेगा। यदि कोई हायर परचेज पर लेना चाहे तो वैसे ले ले और यदि कार्ड वैसे खरीदना चाहे तो वैसे खरीद ले। हिन्दुस्तान में किसी भी जगह उससे अच्छा मकान नहीं मिलेगा। वह सस्ता भी है। अगर कोई मार्कीट में प्रिवेलिंग प्राइसिज की बिना पर हिसाब लगाकर देखे तब भी बड़ी दिक्कत होती है। सब-मैटीरियल नहीं मिलता, डिजायन ठीक नहीं होगा, दोड़-धूप करने में और देख-रेख करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल का सामना होता है। ऐसे हालात में मैं अगर कोई भाई या माननीय सदस्य इससे बैटर प्रपोजल लायेगा तो पूरा पूरा गौर किया जायेगा और अगर कोई प्रैक्टिकल चीज होगी तो उस पर भी जरूर अमल किया जायेगा।

टीचर स्ट्राइक के मुतालिक भी स्पीकर साहब, मुझे शब्द निवेदन करने हैं। स्ट्राइक के मुताबिक रोज ही हमारे यहां

चर्चा रहता है। असूलन मै स्ट्रांइक के खिलाफ हूं । जापान में फ़ैक्ट्रीज वर्कर्स की बात है और जहां तक गवर्नमेंट सर्वेंटस का ताल्लुक है या जहां तक टीचर्स का ताल्लुक है वे भी कभी काम करना नहीं छोड़ते । टीचर्स को भी कभी वैसे भी स्ट्रांइक नहीं करनी चाहिए। टीचर्स के बारे में आज ही हमने अपने शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना है। यहां पर टीचर्स को हम सब इज्जत की दृष्टि से देखते है बड़ा आदर करते है, सत्कार करते है और उनका मान करते है। फरीदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मैने अपने वेलकम ऐड्रेस के अन्दर गुरुओ की तारीफ की थी और कहा था कि—

कछु गुरु बिन गुण आवत नहीं ।

एक बात और स्पीकर साहब, मुझे बड़ी याद आती है। जब मै कालेज में पढ़ता था तो मुझे एक अग्रेज प्रोफेसर से पढ़ने को मौका मिला। उस प्रोफेसर का नाम मिस्टर रैले था। उनसे हम कंपैरेटिव पौलिटिक्स और पौलिटिकल थ्योरी पढ़ते थे । कभी कभी वे कहा करते थे कि —

In India there is dearth of good teachers.

हम उनसे लड़ पड़ते थे और कहा करते थे कि हिन्दुस्तान में अच्छे टीचर्स की कोई कमी नहीं है लेकिन जबसे यह पूरा गृहस्थ संभाला तो देखने में आया कि अग्रेज प्रोफेसर जो कहता था वह ठीक ही कहता था, वह सही बात थी। वहां तो

टीचर्ज की इतनी इज्जत है कि जब कभी किंग जार्ज फिफ्त कोई फक्शन करता था तो वह अपने गुरु को खुद निमंत्रण पत्र देने आया करता था लेकिन आज टीचर्ज क्लेम करते हैं कि हमे स्ट्राइक करने का यूनियन बनाने का तथा और दूसरे काम करने का राइट मिलना चाहिए।

हम तो गुरुओ की इज्जत करते है जो त्यागी भाव रखते है, गोया कि जो ऊंचे दर्जे के विचार रखते है और इन झगड़ो में नहीं पड़ते है।

उनमें त्याग भाव होना चाहिये । विश्वामित्र के पास भगवान रामचन्द्र जंगलो में गये । वे उनसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए गये । वे सही मानो में गुरु थे । अब आजकल तो खाने-पीने को हरेक को चाहिए, हरेक अपने गृहस्थ पर लगा हुआ है और जो तनख्वाह मिलती है उससे अपने गृहस्थ जीवन को चलाता है। चौधरी माडू सिंह जी ने जो हाउस में आज स्टेटमेंट दी है वह ठीक ही दी है। उन्होने बताया है कि उनके ग्निविसीज ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उनका स्ट्राइक करना ठीक नहीं है। एक बात कहनी मै भी जरूरी समझता हूं कि टीचर्ज भी अपने आप को एक पोलिटिकल पार्टी समझने लग गये है चाहे वे पार्टी थे या नहीं, लेकिन कुछ पार्टीज ने तो उनकी पीठ ठोकर उभार दिया कि आप अपना क्लेम मांगिये। हम आपके साथ है। उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं लेकिन उनकी जिन्दगी खराब हो गई। अभी तक भी इनकी समझ में यह बात नहीं आई है। जब हमारे बच्चो का जीवन

इनके हाथ में है, इन्होंने एक अच्छी नसल बनानी है तो इन्हे इस समय पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो यह कहूंगा कि चाहे अच्छी नसल बनानी है या बुरी बनानी है यह सब इनके हाथ में है। जिस प्रकार से इन्होंने यह हड़ताल कर रखी हैं उसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा ? आमतौर पर बच्चों पर मां बाप या टीचर्स का असर होता है। लेकिन ज्यादा असर तो टीचर्स का ही होता है। कभी कोई बात हो तो बच्चे यही कहते हैं कि हमारे मास्टर ने यह कहा है इसलिये हम यही कहेंगे। पिता की इतनी बात नहीं मानी जाती जितनी मास्टर जी की बताई हुई बात मानी जाती है। हम तो बचपन में मास्टर की बात को अधिक मानते थे। मास्टर के कहने के मुताबिक चलना ही एक खास चीज बनी हुई थी। ऐसी हालात इन लोगों को नहीं नहीं करना चाहिए थी। इन लोगों ने बड़ी गलती की है टीचर्स को संतोषी होना चाहिए, त्यागीभवी होना चाहिए, एक आदर्श रखना चाहिए बजाये और झगड़ों में पड़ने के। यह बड़े अफसोस की बात है कि जब कई एक ने कहा कि इनकी बात मान लेनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी बात मान ले तो मेरे पास तो और भी पहुंच जायेंगे कि हमारी इंकमेंट का मामला है, हमारी कुछ अनौमलीज हैं, ये दूर करो। कोई कहेगा कि हमारी भी इन्कम बढ़ाओ, हमारी पे बढ़ाओ, हमें यह फ़ैसिलिटिज दो इस तरह से कितने लोग की मांगें आ जायेंगी यह जो कुछ भी हुआ है यह तमाम जिम्मेवारी मास्टर्स के लीडर्स की है या कुछ पोलिटीकल पार्टिज की है जिन्होंने इनको उभारा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर दिन का भूला भटका शाम को भी

धर आ जाये तो अच्छा ही है। इसलिये उनको चौधरी माडू सिंह , एजुकेशन मिनिस्टर ओर चीफ मिनिस्टर साहब के सामने अन-कंडीशनली अपनी हड़ताल को वापिस ले लेना चाहिए । मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे बोलने का और सदन में अपने विचार रखने का मौका दिया ।

**चौधरी ईश्वर सिंह (पुण्डरी):** स्पीकर साहब कई दिनों से गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर चर्चा हो रही है। ये गवर्नर साहब का ऐड्रेस में जो कुछ हमने पीछे तरक्की की है उस बारे में दिया हुआ है। इस ऐड्रेस में जो कुछ हमने पीछे तरक्की की है उस बारे में दिया हुआ है। इस ऐड्रेस से सब कुछ जाहिर होता है । खास बात यह है कि इस हकूमत ने पिछले पांच सालों में जो कुछ किया है वह इसमें जनरेलाइज किया गया है ।

आप देखिये, बिजली हर गांव-गांव में पहुंचाई है। पहले जो भी हकूमते आई, जिनका भी राज आया वे पर्टीकुलर इलाके का ही ध्यान रखते थे अर्थात् अपने-अपने इलाको का। लेकिन अब चाहे किसी किस्म का गांव हो, चाहे वह गांव अपोजीशन के हल्के में हो, या दूसरे में हर गांव में बिजली जायेगी, हर गांव में सड़क जायेगी। जिस तरह से सूरज की धूप सभी के लिए होती है और वह सारी स्टेट के लिए किया गया, सभी के लिए किया गया ।

जहां तक हमारे अलग-अलग महकमो का ताल्लुक है उस बारे में भी अर्ज कर दूं। ट्रांसपोर्ट के बारे में चौधरी राम लाल जी ने काफी क्विटिसाइज किया। मैं उनकी बात को समझता हूं, वह इमोशनल है। उनका भी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा था। अब ट्रांसपोर्ट सारी नेशनलाईज हो गई है, यानि 100 परसेन्ट नेशनलाईजेशन हो चुकी है। नेशनलाईजेशन होने से हरियाणा की आमदनी बढ़ती ही जा रही है। सन् 1968-69 में कार्ड अढाई करोड़ के करीब आमदनी थी लेकिन इस वक्त करीब 10 करोड़ रूपये है। सैट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी रोडवेज की सर्विसिज को माना है इसका हिन्दुस्तान में पहला नम्बर है। हमारे यहां हर किस्म की बसें चलती है। मुसाफिर को हर किस्म की सहूलियते दी जाती है। हमारे यहां हर किस्म की बसें चलती है। मुसाफिर को हर किस्म की सहूलियते दी जाती है। मैं तो यह कहूंगा कि लम्बे रूट पर चलने वाले मुसाफिरो को तो ये सहूलियते मिलनी ही चाहिए। अगर रास्ते में बस बिगड़ कर खड़ी हो जाये तो उन लोगो की क्या हालत होगी ? इसलिये जो लोग लम्बे रूट पर सफर करते है उनको ज्यादा सहूलियते मिलनी चाहिए और ऐसे रूट्स पर अच्छी बसो की जरूरत है।

चौधरी राम लाल जी ने यह भी कहा कि बस अड्डो पर जो खाने पीने की चीजे मिलती है, वे बहुत मंहगी मिलती है। ऐसी बात नहीं है। यह ठीक है कि कुछ दुकाने होती है वे आक्शन होती है, उनकी ओपन आक्शन होती है। जो ज्यादा दाम देता है

उसी को दे दी जाती है लेकिन उन पर सरकार का भी कंट्रोल होता है। जनरल मैनेजर सब को चैक करता है, चीजों के स्टैंडर्ड को भी देखता है। सफाई वगैरह को भी देखता है। कई जगहों पर तो नो-प्रोफिट नो लोस पर दुकानें चलती हैं। चौधरी राम लाल जी के अपने करनाल बस स्टैंड पर अच्छा रेस्टोरेंट है, जहाँ ठीक दाम पर साफ चीजें और अच्छी जगह बैठ कर खाने पीने को मिलता है। हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हर लिहाज से बढ़ता जा रहा है।

जोशी जी ने बताया था कि हमारे रोडवेज के वर्कर्स की, कंडक्टर और ड्राइवरज की तनखाहे बहुत अच्छी हैं उनको बोनस भी दिया जाता है। मैंने लगभग हिन्दुस्तान की हर एक स्टेट को देखा है और उनके यहाँ जो तरक्की हुई है उसे भी देखा है। हर सूबे से हमारे सूबा हर बात में आगे है क्योंकि यहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनके साथी जो उनकी कैबिनेट में हैं और वे फिक्स टाइम पर उनको पूरा कर देते हैं। इस तरह से जनता में इस सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता है अफसरों में विश्वास पैदा होता है और दूसरी स्टेट्स के सब लोग इस बारे में तारीफ करते हैं।

जहाँ तक फेसिलिटिज देने का तादुलक है, हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। बिजली को ही लिजिये, बिजली के बारे में भी कहने वाले कहते हैं कि एकदम इतनी ज्यादा देने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूँ कि अगर यह

तेजी से दी जाती तो हमारा हिस्सा जो पहले 54 परसेंट होता था अब हमें 39 परसेंट मिला है, यह और भी कम मिलता। भाखड़ा से जो बिजली मिलती है वह कन्जम्पशन के बेस पर मिलती है। चीजों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आप जितना भी काम को लेट करेंगे उसमें उतनी ही ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। आजकल बिजली की तो हर जगह जरूरत है। पिछले दिनों ड्राउट की वजह से बिजली की कमी हुई। कुछ लोग कहने लगे थे कि साहब, सब को बिजली देने की क्या जरूरत थी। इतने इतने कनेक्शन दिये जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आप यह बताओ कि आप लोगों ने दरखास्त दी हुई है? अगर आपको ट्यूबवैल का कनेक्शन न दिया जाये तो आप यही कहेंगे कि हम तो जरूर लेंगे। तो सवाल यह है कि ऐक्सपैन्शन हो रही है और होनी चाहिए। बिजली बढ़ने से हमारे सूबे में इंडस्ट्री बढ़ रही है, कैनल के लिए ट्यूबवैल लग रहे हैं इस साल जो ड्राउट पड़ा। यह तो हमारे लिए बलैसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है क्योंकि इसने सरकार को भी चेतन कर दिया है कि बिजली का पैदावार आरे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी सरकार ने इस हिसाब से अपने प्रोग्राम भी बना लिये हैं जो कि जाहिर है और गवर्नर ऐड्रेस में भी दिये हुए हैं कि जिस तरीके से हम ब्यास-सतलुज लिंक बनाने जा रहे हैं उससे गोविंद सागर में पानी बढ़ता जायेगा। पानीपत में पहले 220 मैगावट आ उसके बाद फिर 220 मैगावट का थर्मल प्लांट लगाने जा रहा है। फरीदाबाद में और बदरपुर में भी लगाने जा रहे हैं, वहां पर भी बिजली पैदा की जायेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि चारों



तरफ से बिजली की प्रोडकशन बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बारे में अपनी पूरी कोशिश कर रही है हमें जितनी भी बिजली की जरूरत है, उसको पूरा किया जाये। मैं यह समझता हूँ कि सरकार इस बिजली की कमी को जल्दी ही पूरा करने में कामयाब हो सकेगी क्योंकि बिजली ही एक ऐसी चीज है जिससे ऐग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीयल प्रोग्रेस होती है। यह जो अनाज की पैदावार इतनी बढ़ी है वह सब बिजली की वजह से ही बढ़ी है।

इस सरकार के दूसरे कामों को देख लीजिये। यहां पर बारिशों की वजह से मंडियों के अन्दर फसले भीग गईं। फसले काफी खराब हुई हैं। यह सरकार इतनी तेजी से चली कि जहां पहले हमारे पास 28 लाख बोरी के करीब अनाज रखन की जगह थी वहां अब हमारे पास 68-72 लाख बोरी रखने की करीब स्टोरेज कैपैसिटी हो जायेगी। यह जल्दी ही बढ़कर इतनी हो जायेगी कि जितना हम स्टॉक खरीदेगे, उस सारे को हम अपने यहां स्टॉक कर सकेंगे।

इसी तरह से दूसरी और भी हम आगे बढ़े हैं। मैथिलीकल फसिलिटीज के ऊपर पांच रूपये के स्थान पर अब हमारा 10 रूपये पर कैपिट के हिसाब से खर्च हो रहा है। इसके साथ ही साथ जगह-जगह पर ड्रिकींग वाटर और सीरेज की फसिलिटिज प्रोवाइड की जा रही है। आप देख लीजिये कि देहातो के लिए किस तरह से पानी मुहैया किया गया है। 62 की 62

म्यनुनिसिपिल कमेटीज की सीवरेज और ड्रिफिंग वाटर की स्कीमें बना दी गई है । इसके साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं क पिछले पांच सालो में साढ़े तीन सौ देहातो मे ओर इस बार 130 देहातो में पीने का पानी का प्रबन्ध किया गया ओर यह काम आगे भी चालू रखा जायेगा । जहां पर खारा पानी था, नीचा पानी था या किसी वजह से खराब पानी था और जहां पर लोगो को और पशुओ को पानी मिलना मुश्किल होता था वंहा पर अब लोग अपने पशुओ को नहलाते है । लोग अब हर तरह से उस पानी को इस्तेमाल करते है मैं यह समझता हूं कि हमे कुछ अपने डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रैन्थन करने की सख्त जरूरत है । आजकल जो हमारा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है वह ठीक है । अनाज की या आटे की जो अब दुकाने खोली गई है, वे अगर इससे भी पहले होती तो और भी अच्छा होता क्योंकि यह जो आखरी टाईम होता है इसमें गरीब लोग सवाये पर अनाज लेते है । इसी हिसाब से उनको आगे देना पड़ता है । इस वक्त आकर कीमते भी ज्यादा बढ़ जाती है । जो राशनग का सिस्टम जारी कर दिया गया है यह ठीक है लेकिन इस बात की जरूरत है कि गांव में ऐक ऐसी कमेटी बनाई जाये जो दुकानो की अच्छी तरह सुपरवाइज कर सके । चाहे चीनी है, चाहे कपड़ा है, चाहे अनाज है, या चाहे आटा है यह अच्छी तरह से बिकता भी है या नहीं, वह कमेटी इस बात की जांच रखे । जहां तक फूडग्रेन्ज प्राईस का ताल्लुक है मैं यह समझता हूं कि इसका लिंक हर चीज की प्राईस से होना चाहिए । चीजो के भाव हर साल बढ़ते जा रहे है । जमीदारो को भी उसी

हिसाब से रिमुनरेटिव प्राईस मिलना चाहिए अनाज की भी जो प्राईज फिक्स हो, वह दूसरी चीजों के भाव से हिसाब लगाकर फिक्स होनी चाहिए ।

टीचर्ज के बारे में यहां काफी चर्चा हुई है । मैं भी एक टीचर रहा हूं। मैं समझता हूं कि टीचर्ज मिस-गाइड हुये हैं। वे कुछ पोलिटिकल पार्टीज के हाथ में खेले हैं, आप एक मिसाल लिजिये । जब अबोहर-फाजिल्का और चण्डीगढ़ के बारे में दिल्ली में फैसला हो रहा था, आखिरी दिन थे जब फैसला लिया जा रहा था और यह उम्मीद थी कि आज आ जायेगा, उस वक्त पांच-छ हजार टीचर्ज दिल्ली पहुंचे । वे प्राईम मिनिस्टर की कोठी के सामने पहुंचे । वह कोई प्रोपर मौका नहीं था। कुछ बताने वाले यह कहते हैं कि कोठी के बाहर कुछ इधर-उधर के आदमी भी बैठे थे । कई अन्दर जो रहे थे तो कई अन्दर से बाहर आ रहे थे । उस वक्त बाहर बैठे हुये आदमियों ने इनमें से कहा कि भई हरियाणा के बारे में भी कुछ बोल दो कि चण्डीगढ़ या अबोहर-फाजिल्का हरियाणा को मिलना चाहिए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें इससे क्या ? हमें तो तनख्वाह से ताल्लुक है। उनमें कुछ आदमी अच्छे भी थे, इन्होंने कहा कि अब जाने का मौका नहीं है लेकिन जो पालिटिकली गाईडिड थे वे नहीं माने । जिस तरह से आग में लकड़िया डाल रहा है उसी तरह से जो लोग उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने का मौका आज है। इसी तरह से अब एजीटेशन चल रही है वह भी इसी हिसाब से चल रही है कि इधर

हमारी असैम्बली का भी सेशन है और उधर पार्लियामेंट का भी सेशन है ।

सभी अपोजीशन पार्टीज वाले इनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी यूनियन में बहुत से आदमी ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इनके पेड आदमी हों और जिनका होल टाईम यही काम हो कि किसी तरह से टीचर्स को उकसाया जाय। पिछले साल जो पार्लियामेंट के इलैक्शनज हुए, उनमें हमने यह देखा कि टीचर्स को बकायदा अपोजीशन के कुछ आदमियों, ने जो यह चाहते थे कि उनका मकसद हल हो जाये, कार्ड बनाकर उकसाया और यह कहा कि आप लौटा नून डाला भी । पार्लियामेंट के इलैक्शनज में जिनमें इंटरनेशनल ओर नेशनल इश्युज पर वोटिंग होती है—हर आदमी यह समझ सकता है कि डेढ़ सौ साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे और देश में मजबूत हकूमत की जरूरत थी, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ 15-15 वोट जरूर डलवाये । उन्होंने उसकी इंपोटेंस ना देखते हुए अपने लिमिटेड माहौल में यह देखा कि बंसी लाल के खिलाफ वोट देने हैं, इसलिये उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ 15-15 वोट जरूर डाले । यह जाहिर करता है कि वे मिस गार्ड किये गये और वे उस बहकावे में आ गए । उन लोगों के बहकावे में आ गये जो पेड भी हो सकते थे और ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बाते वे पूरी तरह से समझ गये। ये जो कोठारी—कमीशन की बाते करते हैं, इनमें बहुत से टीचर्स ने तो कोठारी कमीशन की किताब भी नहीं पढ़ी होगी कि उसमें क्या

रिपोर्ट दी हुई है । एक जो मिस-अन्डरस्टैंडिंग है वह खास तौर पर कही जाती है और वह है डी.ए. कट के बारे में। डी.ए. कट के बारे में कोठारी कमीशन ने उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि डी.ए. में से कुछ हिस्सा काट कर बेसिक-पे में शामिल कर दिया जाये । यह मामला हाई-कोर्ट में भी एग्जामिन हो लिया। हाई कोर्ट में भी बड़े बड़े वकीलो की बहस होती है और वहां पर बड़े बड़े रोशन दिमांग वाले जज होते हैं। वहां पर कोई चीज बाकी नहीं रही उन्होंने यह फैसला दे दिया कि जो सरकार ने दिया है, वह जायज है। गवर्नमेंट के दूसरे मुलाजिमो को और इनको जो कुछ दिया गया है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तनख्वाह के मामले में अगर वही डी.ए. इधर से बेसिक पे में डाल दिया गया तो यह तो उंगली पकड़ का पहुंचा पकड़ने वाली बात है । ये कहते हैं कि वह तो बेसिक पे है। इसी पर हमें पूरा डी.ए. दो । यह बात कायदे कानून के खिलाफ है। सरकार ने अपनी माली हालत को भी ध्यान में रखना है । टीचर्ज की एप्रोच क्या है, किस ढंग की है ये सारी चीजे भी सरकार ने देखनी हैं

18.00 बजे मैं समझता हूं कि अब जरूरत यह है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से रिफार्म किया जाये । जहां एजुकेशनल पालिसी है इनको 20 मील दूर रखा जाये, डिस्ट्रिक्ट से बाहर रखा जाये उसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट सुपरवीजन की भी जरूरत थी। पहले इंस्पैक्शन किया जाता था और उनकी सनदो के पीछे लिखा जाता था कि सैटिसफैक्टरी है या नहीं है बी.ई.ओ. को

ही या डी.ई.ओ. बच्चो का टैस्ट लेते थे । अब जब कि आने जाने के साधन बढ़ गये है तो बी.ई.ओ. को ही मोटल साईकिल दी जा सकती है ताकि उसके अन्दर जो 40-50 स्कूल है उनमें आसानी से पहुंचा जा सके और टीचरो की फरलो मारने की आदत है उस पर चैक हो सके ।

**श्री अध्यक्ष:** आपका समय हो गया है ।

**चौधरी ईश्वर सिंह:** बहुत अच्छा जी। मैं समाप्त करता हूं और गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर जो रेजोल्यूशन आया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

**चौधरी पीर चन्द** (बरवाला अनुसूचित जाति): मानीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके द्वारा सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, ओर इस सदन को उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां कि राज्यपाल महोदय ने पहले दिन अपना अभिभाषण दिया । उस अभिभाषण के पहले पेज के अन्दर ही गरीबी दूर करने का जिक्र है और इसके अन्दर ही दूसरा प्रस्ताव है प्लाटो को सुरक्षित रखने का यानि पट्टेदारी सुरक्षित रखने और हर इंसान को तरक्की देने की बात इसके अन्दर है । दूसरी तरफ पेज 19 के अन्दर टीचरो के लिए भी कुछ सुझाव दिये है । मैं समझता हूं कि यह सब गरीब समाज से ताल्लुक रखते है । स्पीकर साहब, मैं आपके ,द्वारा चीफ मिनीस्टर ओर सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से दो साल पहले जब कि पार्लियामेंट के इलैक्शन थे, सन् 1971 में उस

वक्त हमारी प्रधानमंत्री ने भी जनता के सामने एक ऐसा ही मैमोरेण्डम रखा था और उन्होंने प्रोग्राम रखा था कि गरीबी दूर की जायेगी लेकिन उसका असर आज उसके उल्टा है । आज गरीब भूख से मर रहे है । आज हरियाणा मे हालत यह है कि मजदूरो को काम नहीं मिलता, वे मजदूरी के लिये तड़पते है ओर हरिजनो का तो यह हाल है कि उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिलता । पहले सड़को का काम था। लेकिन आजकल वह भी सरकार ने बंद की हुई है, नहरो के काम को बंद किया हुआ है। आज हरियाणा में हालत यह है कि डेढ़ रूपये किला अनाज मिलता है चाहे जमीदार हो चाहे गरीब हरिजन हो, चाहे छोटा मुलाजिम हो उसके खाने का गुजारा चलता क्योकि आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है । हरिजनो का तो यह हाल है उनको वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके बच्चे बिलबिलाते है लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है हम हरियाणा को बहुत बड़ा प्रदेश बना रहे हैं और हमार प्रदेश सबसे अच्छा है। इस बात को सुनकर बड़ी शर्म आती है कि एक तरफ तो गरीबी हटाने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ लोग भूख से मर रहे है । आज अमीर लोग गरीबो का खून चूसकर खुश होते है गरीब आदमियो के लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है और बेचारे रोजगार न मिलने के कारण भूखे मरते है । उनके सरकार ने कुछ नही किया ।

एक सवाल इसके अन्दर टीचरो का आया। आज यह हालत यह है कि उन बेचारो को पुलिस द्वारा पिटवाया जाता है ।

एस.डी.ओ. और बी.डी.ओ. की ड्यूटी लगी हुई है कि उनको मारो । कहना चाहता हूँ कि उनका कसूर क्या है । उन्होंने अपने पेट को सरकार के सामने रखा अपनी जो मांगे है और उनको सरकार के सामने रखा है और वे मांगे बिल्कुल जायज है । अगर गरीब आदमी अपनी डिमांड रखता है, या अपने पेट की रोटी का सवाल रखता है तो उसमे हर्ज क्या है । दो साल पहले इन्होंने एक नोटिस दिया कि हमारी ये मांगे है ओर उनको माना जाये । आज हमारे रूलिंग पार्टी के भाई कहते हैं कि टीचर्ज की डिमांड जयाज नहीं है । आज उन टीचर्ज के चार नुमाइंदे मरने के घाट पर हैं लेकिन इस सरकार की आंख नहीं खुलती । अगर कहीं किसी वजह से उनकी मौत हो गई तो हरियाणा पर यह एक कलंक होगा । मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि उनकी जायज बात को मान लेना चाहिये और उनको रोटी देनी चाहिये । आज मैं सरकार से निवदेन करना चाहता हूँ इन्होंने दावा किया है कि यह जो गरीबी है हम इसको दूर करेंगे और उस वादे को पूरा करने के लिए सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये । उनके लिये रोटी और कपड़े का प्रबन्ध करना चाहिए । अगर यह सरकार इन चीजों का इन्तजाम नहीं कर सकती, गरीबों को रोजी-रोटी नहीं दे सकती तो सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार को गरीबों का शोषण करना छोड़ देना चाहिये । इसको गरीबों का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है । एक बात मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से और कहना चाहता हूँ कि जहां हरियाणा में तरक्की हुई है वहां गरीबों के साथ शोषण भी हुआ है ।



हरियाणा के अन्दर जो हमारे हरिजन भाई हैं वे दर-दर मारे फिर रहे हैं, उनके लिये रोजगार के साधन नहीं हैं। उनके पास इतने साधन भी नहीं हैं कि अपना गुजारा कर सकें। उनकी माली हालत इतनी खस्ता है कि वे अपनी रोटी का भी प्रबन्ध नहीं कर सकते। आज देश में गरीबी को मिटाने का नारा जरूर है लेकिन हालत यह है कि गरीब को कोई सम्भालता नहीं। आज जितने सरमायेदार हैं वे गरीबों को दबाते चले जा रहे हैं। गरीबी ज्यादा बढ़ती जाती है और सरमायेदारी भी बढ़ती जाती है। आज हरियाणा के अन्दर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि एक या दो टाईम फाका करते हैं लेकिन यह सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती।

स्पीकर साहब, आज से साल पहले इतने काम शुरू किये कि दिन और रात अफसरों ने गैस जला करके काम खत्म किया और उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने कामयाबी हासिल की, गरीब आदमियों को कोई मदद नहीं मिली। अगर सरकार यह सोचे कि आज से दो साल पहले हमने बिजली लगा दी, सड़के बना दी, तो इससे क्या होता है, आज भी गरीबों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, गरीबी दूर नहीं हुई है, गरीब तो दिन रात नीचे को जा रहे हैं। गरीबी दूर करने का सिर्फ यह मतलब नहीं कि सरकार ने बिजली ला दी, सड़के बना दीं तो गरीबी दूर हो गई। बिजली से तो उन लोगों को फायदा है, जिनके पास जमीन है और जिन्होंने अपनी अपनी जमीनों पर ट्यूबवैल लगाये हुये हैं, गरीब हरिजन के पास कोई जमीन नहीं,

कोई ट्यूबवैल नहीं तो उन्हें इससे क्या फायदा होगा। सड़कों से सिर्फ इतना फायदा जरूर हुआ कि कुछ दिन के लिए गरीब आदमी ने मजदूरी के जरिये पेट जरूर भर लिया और सड़कों से गरीबों को क्या फायदा है ? मैं मानता हूँ कि सड़कों और बिजली से कुछ लोगों को फायदा होता है पर यह फायदा हुआ तो उन लोगों को होता है, जिनके पास बड़ी-बड़ी कोठियां हैं, कारखानेदार जो है, उन्हें इससे फायदा पहुंचा है, जिनके ट्यूबवैल लगे हुये है, उन्हें फायदा पहुंचा है लेकिन हरिजनों के पास, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के पास अपने कोई ऐसे साधन नहीं हैं, गरीब तो यी कहता है कि हमें रोटी दो, कोई काम दो, हम भीख नहीं मांगते, हमें भीख नहीं चाहिये, हम तो सरकार से काम चाहते हैं ताकि अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पर यहां हरियाणा सरकार के सभी काम ठप्प पड़े हैं, इसलिये किसान और मजदूर लोग बेचार बेचैन पड़े हुये हैं। स्पीकर साहब, यहां हरियाणा में इतनी बुरी हालत है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहते हैं कि हमने जगह जगह पर अनाज के डिपो खोल रखे हैं तो मैं मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि वे गरीबों के लिए गांव-गांव में सस्ते अनाज के डिपो खोलें और इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि गांव में केवल तीन किलो पर मैनबर के हिसाब से अनाज दिया जाता है। क्या इतने थोड़े अनाज से गरीब आदमी का पेट भरता होगा या उनका कल्याण होगा। मैं तो सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि अगर सरकार चाहती है कि गरीबी दूर हो और गरीब आदमी उन्नति करें तो उनके लिये

छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज लगाई जायें ताकि उन्हें काम मिले और उससे वे लोग ऊपर उठें। और उनकी हौसला अफजाई हो। स्पीकर साहब, अगर इसी तरह से यह सरकार चलती रही तो मैं एक बात कह देता हूँ कि गरीब नहीं रहेगा, सरमायेदार ही नजर आयेंगे और सरकार का मसला हल नहीं होगा। गरीबी ही रहेगी, यह कभी दूर नहीं होगी। यह सरकार तो गरीब आदमियों को देखना नहीं चाहती। हर गरीब चाहता है कि मैं यहां खुशी से रहूँ, अच्छा खाने को मिले, अच्छा जीवन व्यतीत करूँ, पहनने के लिए कपड़े मिलें, बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इन्हें कोई सुझाव दें, इन्हें अकल दें, ताकि ये लोग गरीबों की तरफ देखें और उनका भला करें। ..... (विघ्न) ..... पोसवाल साहब, मैं मानता हूँ कि जब सता हाथ में होती हैं तो दिमाग भी कुछ आसमान से बातें करता है और दूसरी तरफ का ध्यान नहीं रहता। उन्हें गरीब नहीं दिखते, बल्कि सब सरमायेदार ही सरमायेदार दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। अन्त में स्पीकर साहब, मैं फिर आप से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इन्हें कहें कि कम से कम गरीब लोगों का भी ध्यान रखें।

**चौधरी फूल चन्द (मुलाना, अनुसूचित जाति):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बड़े जोर से चर्चा चल रही है। राज्यपाल महोदय ने प्रारम्भ में गरीबी के बारे में ही चर्चा की है। स्पीकर साहब, यह

गरीबी तो कोई नई चीज नहीं है, यह तो पुराना अभिशाप है। मैं, इस बात के लिये, इस आवाज को उठाने के लिए अपनी प्राईम मिनिस्टर साहिबा को ंबारिकबाद देता हूं कि वे यह बात लेकर सबसे पहले चलीं कि हमने देश में गरीबी को दूर करना है, खत्म करना है। इससे पहले इतने जोर से इस बात के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। मेरे साथी चौधरी पीर चन्द जी, जो कि लखपति हैं, मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वे कितने गरीबों का भला करते हैं, कभी इस बारे में सोचते भी हैं कि नहीं। ..... (विघ्न) ..... लेकिन हरिजन तो हैं, इतना गीब होना कोई कंडीशन नहीं है। स्पीकर साहब, हमारी ीारत सरकार ने इस गरीबी के खिलाफ ऐसे बहुत से कदम उठाये हैं जैसे बैंक नैशनलाइजेशन का कदम, जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है इससे गरीबों को लाभ हुआ है, गरीब किसानों को लाभ हुआ, गरीब मजदूरों को लाभ हुआ है। इसके बाद सरकार ने प्रिवी परसिज के खिलाफ आवाज उठाई। ऐऐ और बहुत से काम हमारी हरियाणा सरकार ने भी किये। सबसे पहले, हरियाणा सरकार ने अक्टूबर, 19732 में भूमि-सुधार का बिल पास करके दे दिया जिसे दिसम्बर, 1972 में भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। जैस गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में बताया है कि लगभग एक से डेढ़ लाख एकड़ भूमि गरीब मजदूरों और किसानों में बांट दी जायेगी, यह तो रिकार्ड की बात है। स्पीकर साहब, मुझे विश्वास है कि लोगों के आब्जैक्शनज सुनने के बाद जो प्रैक्टिकली रकबा निकलेगा, तो जो फर्जी बेनामे लोगों ने किये हुये हैं, उनकी पूरी इन्क्वारी करने

के बाद यह रकबा और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से गीबी हटाओ स्कीम के तहत सरकार ने कुछ स्कीमें बनाई हैं जैसे कि स्माल फारमर्ज एजेंसी, मारजीनल फारमर्ज एजेंसी, लैन्डलैस एग्रीकल्चरिस्ट एजेंसी, इनसे गरीब किसानों, को गरीब मजदूरों को और हरिजनों को व लेबररज को लाभ होगा इसके तहत सरकार बहुत सी ग्रांट भी देती है और कर्ज भी देती है। इसके आगे आगे जो कदम उठाये जा रहे हैं वे बहुत सैटीसफैक्टरी हैं किन्तु मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीबी हटाने के लिए और तेजी से कदम उठाये ताकि समाज से सदियों पुराना अभिशाप समाप्त हो और कांग्रेस पार्टी को इस बात का श्रेय जाये।

दूसरा पहलू गवर्नर महोदय ने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया है। यह छिपी हुई बात नहीं है कि हरियाणा ट्रांसपोर्ट को नैशनेलाईज करने में दूसरे दर्जे पर आया है ओर बहुत से लोगों ने यह तजुर्बा भी किया है कि हरियाणा की जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वह सबसे अच्छी है। सदन के सदस्य बसों में सफर करते हैं, वे इस चीज को मानेंगे कि वाकई यह सबसे अच्छी सर्विस है। गाड़ियां न मिलने की वजह से या खराब हो ने की वजह से कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन जिस रफतार के साथ हमने इस काम के बढ़ाया है, माईलज को बवर किया है यह एक सराहनीय काम है। भविष्या में इसमें और भी तरक्की होने की संभावना है।

वाटर सप्लाई स्कीम को टच करते हुये गवर्नर साहब ने बताया है कि ये अधिक से अधिक कार्यान्वित की जा रही है। जिन गांवों में पीने का पानी देखने तक को नहीं मिलता था, ऊंटों पर पानी लाया जाता था, आज वहां टूटियां लगी हुई हैं। उस स्थान पर जहां पानी नहीं पहुंचता था, वहां पानी पहुंचाने के लिए चौधरी बंसी लाल ने भगीरथ का रूप ले कर पानी पहुंचाया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ट्यूबवैल्ज की सप्लाई कैपेसिटी से ज्यादा है वहां प्राइवेट कुनैक्शन दे दिये जायें।

मैडिकल फैसिलिटी की चर्चा आई हस्पताल बहुत खोले गये, स्वास्थ्य सुविधायें भी बहुत दी गईं। सरकार ने यह भी फैसला किया कि हर ब्लॉक लेवल पर एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोला जायें। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इससे बहुत से लोगों को सुविधा मिली और उनकी सेहत में बहुत फर्क पड़ा है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ब्लॉकस के अन्दर अब तक प्राइमरी हैल्थ सेंटर नहीं खोले गये जैसे हमारे बराड़े ब्लॉक में अब तक नहीं खुला है उनके लिये मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार वहां भी खोलेगी।

शिक्षा सुविधाओं की बात चल रही थी। इस पर मुझे कोई शंका नहीं है। हरियाणा बनने के बाद हमने हर पहलू में तरक्की की है। स्पीकर साहब, आपको ध्यान होगा कि जब हम

पढ़ा करते थे तो हमारे से पुराने लोग कहा करते थे कि आज की पढ़ाई क्या है ? पढ़ाई तो पहले हुआ करती थी। कल को और बच्चे पढ़ेंगे तो हम भी कहेंगे कि यह क्या पढ़ाई है ? पढ़ाई तो हमारे टाइम में थी। इस कारण को जानने के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहरायेंगे ? वह है आज का टीचर। वे इस बात में विश्वास नहीं करते कि उनकी ड्यूटी क्या है ? वे तो मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि बिल्कुल अनुचित है। क्या टीचर की स्ट्राइक जायज है ? मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सीधे-सीधे टीचर किसी बहकावे में आ गये हैं और मुझे तो कुछ ऐसा भी पता चला है कि कुछ प्रतिक्रियावादी लोग बाहर से आकर (बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी वगैरह से) उनको इनीशियेट करते हैं कि तुम सरकार के खिलाफ काम करो। कुछ लीडर जो धिसे-पिटे हैं और जिनकी सोसायटी में कोई जगह नहीं है वे इस पहलू को लेकर आगे आ रहे हैं। यह अकेली मास्टर्स की स्ट्राइक नहीं है कल को और भी बात हो सकती है। मैं सरकार से कहूँगा कि वह इस मामले में पूरी संजीदगी से काम लें। अगर सरकार पूरी संजीदगी से काम नहीं लेगी तो कल को और महकमें के लोग कहेंगे कि हम तो काम नहीं करेंगे, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तो मैं अपने मास्टर भाईयों से पुरजोर निवेदन करूँगा कि वे किसी के चक्कर में न आयें, लालच में न आयें। उनको चाहिये कि वे अपनी स्ट्राइक वापस ले लें और संजीदगी से बातचीत करें।

स्पीकर साहब, इसके बाद इरीगेशन की चर्चा आई। इरीगेशन के मामले में हमारी सरकार ने जितना कार्य किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इरीगेशन स्कीम के अन्दर न केवल हमारी सरकार ने खेतों को पानी पहुंचाया है बल्कि जो पानी बाहर से फालतू आकर फलड के रूप में लोगों को तबाह करता था उसकी भी रोक की है। इस बात के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ लेकिन साथ ही साथ एक बात यह भी कह देना चाहता हूँ कि जहां नहरों का पानी नहीं जाता वहां पर जितने ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवैल लगायें। मैं यह मानता हूँ कि ट्यूबवैल्ज लगाये भी जा रहे हैं लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि बहुत मात्रा में लगाये जायें किसी किसान को यह शिकायत न रहे कि मेरे खेत को पानी नहीं मिला।

स्पीकर साहब, पावर प्लांटस की बात आई। बिजली का संकट सारे देश का संकट है। सब जानते हैं कि इसकी कमी की वजह से हमें पावर नहीं मिल सकी। उसके लिये सरकार ने थर्मल प्लांट लगाने के जो कदम उठाये हैं मैं निवदेन करूंगा कि उनको इम्पीमेंट किया जाये। क्योंकि बिजली सभी चीजों का साधन है। जितनी जल्दी यह काम हो सकता है उतनी जल्दी करवायें। लेकिन साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले संकट के दिनों बिजली की सप्लाई में जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की हो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले ताकि लोगों को गिला न रहे।



रूलिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र किया गया है। मैं यह बात समझता हूँ कि जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारतवर्ष की जनता गांवों के काम, सिवाये खेती-बाड़ी के और कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि हम गांव में इंडस्ट्री लगायेंगे। देहातों की इंडस्ट्री तब तक नहीं पनप सकती जब तक उनको प्रोटैक्शन न दी जाये। उनको प्रोटैक्शन देना बहुत जरूरी है, ग्रामोद्योगीकरण बहुत जरूरी है। अगर किसान को छोटा-मोटा धंधा और मिल जायें तो वह और अच्छी हालत में हो सकता है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह पालिसी बदलकर स्माल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटैक्शन दी जाये और वह इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा खोली जाये।

अम्बाला जिला की चर्चा करते हुये गवर्नर साहब ने ब्रिजेज का जिक्र किया है। अम्बाला के निकट टांगरी नदी का पुल है। वैसे तो वह तैयार होने वाला है लेकिन मैं फिर भी सरकार से निवेदन करूंगा कि बरसात से पहले-पहले उसे जरूर तैयार करवा दिया जाये। अगर उसमें कुछ डिले होने की संभावना हो तो उसको रोका जाये क्योंकि बारिश के आने से न केवल लोगों को असुविधा रहेगी बल्कि जो लगा हुआ माल है वह भी बह जायेगा।

शेड्यूल्ड कास्ट्स और दूसरी जातियों के बारे में चर्चा करते हुये कहा कि हैं उनको सहायता दी जा रही हैं। मैं सरकार से अपील करूंगा कि आर्यदा भी जितनी ज्यादा से ज्यादा उनकी

इमदाद की जा सके उतनी करें। दूसरा, स्पीकर साहब, स्पोर्ट्स के बारे .....

**श्री अध्यक्ष:** पोसवाल साहब, बातचीत न करें।

**गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल):** स्पीकर साहब, क्या करूं मेरे पड़ोसी ही ऐसे हैं। ..... (हंसी) .....

**चौधरी फूल चन्द:** स्पीकर साहब, ला ऐंड आर्डर की सिचुयेशन बहुत अच्छी रही .....

**श्री अध्यक्ष:** हाउस का समय हो गया है, सदन कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

**18.30 बजे**

(इस समय सभा 14 मार्च, 1973 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई)